

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF 3rd

LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र]
[Eleventh Session]



[खंड 39 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. ~~33-34~~ contains Nos. 21-30]

40
लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price • One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 28, मंगलवार, 30 मार्च, 1965/9 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
639	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अलग मंत्रालय	2605-07
640	पर्यटकों के लिये सुख-सुविधायें	2607-10
641	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 13	2610-11
642	पुराने जहाजों को बदलना	2611
644	रिंग रोड, दिल्ली	2612
645	केन्द्रीकृत बीज उद्योग	2613-15
646	पंचायतों की वित्तीय स्थिति	2616-18
647	एयर-इंडिया के विज्ञापन	2619-21
648	हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग	2621-23
649	हल्दिया बन्दरगाह	2623
652	चीनी का निर्यात	2625

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या

6	हिन्दी में पता लिखे पत्र	2626
---	------------------------------------	------

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

643	मरमागाओ बन्दरगाह	2628
650	हुगली नदी के तल से मिट्टी कीचड़ आदि निकालना	2650
651	चीनी का निर्यात	2629
653	नमूने के फार्म	2629
654	कृषि बैंक	2629
655	चम्बल घाटी में डाकू-पीड़ित क्षेत्रों का आर्थिक विकास	2630
656	बम्बई बन्दरगाह	2630-31
657	आधुनिक फार्म	2632
658	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	2631-32

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 28 — Tuesday, March 30, 1965/Chaitra 9, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

<i>Starred Questions Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
639	Separate Ministry for S. Cs. and S. Ts.	2605-07
640	Amenities for Tourists .	2607-10
641	National Highway No. 13	2610-11
642	Replacing of Old Vessels	2611
644	Ring Road, Delhi	2612
645	Centralised Seed Industry	2613-15
646	Financial Conditions of Panchayats	2616-81
647	Air India Advertisement	2619-21
648	Hindu Religious Endowments Commission	2621-23
649	Haldia Port	2623
652	Sugar Export	2625
<i>Question No.</i>		
<i>Short Notice</i>		
6	Letters addressed in Hindi	2626

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

<i>Starred Questions Nos.</i>		<i>PAGES</i>
643	Marmagao Port	2628
650	Dredging in Hooghly	2650
651	Sugar Export	2629
653	Model Farms	2629
654	Agricultural Bank	2629-30
655	Economic Development of Dacoit-infested areas in Chambal Valley	2630
656	Bombay Port	2630-30
657	Modern Farming	2631
658	Central Warehousing Corporation	2631-32

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1699	राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना	2632-33
1700	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	2633
1701	एलीफेंटा गुफाओं में विश्राम-गृह	2633-34
1702	कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर के लिये अनुदान	2634-35
1703	केरल में चुनाव	2635
1704	मलकानी समिति की सिफारिशें	2635-36
1705	दिल्ली दुग्ध योजना	2636
1706	दिल्ली से चोरी छिपे अनाज ले जाना	2636-37
1707	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के रेडियो अधिकारी	2637
1708	एयर इंडिया बोइंग में दरार	2637-38
1709	बिहार में चावल और गेहूं के भाव	2638
1710	नंगल में हवाई अड्डा	2638
1711	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	2638-40
1712	पंचायत चुनाव	2640-41
1713	अनाज की हानि	2641
1714	केरल में चावल का उत्पादन	2642
1715	चैकोस्लोवाकिया का "जेड-326 ट्रेनर मास्टर" विमान	2642
1716	वस्तु-समिति	2643
1717	परमाणु बम के भूमिगत परीक्षणों से उत्पन्न झटकों का अनुभव किया जाना	2643
1718	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	2643-44
1719	सहकारी समिति	2644
1720	दिल्ली परिवहन	2644
1721	सहकारी खेती	2645
1722	भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त नौवहन सेवा	2645
1723	पटना में गंगा पर पुल	2645-46
1724	ब्रह्मपुत्र में नौपरिवहन	2646
1725	उड़ीसा में नलकूप	2646
1726	उड़ीसा में चावल का उत्पादन	2646-47
1727	कोनार्क में हवाई अड्डा	2647
1728	उड़ीसा में संयुक्त खेती सम्बन्धी अग्रिम योजनाएँ	2647-48
1729	उड़ीसा को वित्तीय सहायता	2648
1730	दिल्ली में मिठाइयों के भाव	2648-49
1731	एवरो 748	2649
1732	केन्द्रीय अनाज गोदाम, ग्वालियर	2649
1733	बम्बई-पूना तथा बम्बई-नासिक सड़क	2649-50

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

<i>Unstarred</i>	PAGES
<i>Questions Nos.</i>	<i>Subject</i>
1699	Old Age Pension Scheme in Rajasthan 2632-33
1700	Welfare of S. C. & S. T. in Orissa 2633
1701	Rest House at Elephanta Caves 2633-34
1702	Grant to Farm University, Pant Nagar 2634-35
1703	Elections in Kerala 2635
1704	Malkani Committee Recommendations 2635-36
1705	Delhi Milk Scheme 2636
1706	Smuggling of Foodgrains from Delhi 2636-37
1707	I.A.C. Radio Officers 2637
1708	Crack in Air India Boeing 2637-38
1709	Rice and Wheat Prices in Bihar 2638
1710	Aerodrome at Nangal 2638
1711	Indian Airlines Corpotion 2638-40
1712	Panchayat Elections 2640-41
1713	Loss of Foodgrains 2641
1714	Rice Production in Kerala 2642
1715	'Z-326, Trenner Master,' Czech-Plane 2642
1716	Commodity Committee 2643
1717	Tremor caused by Underground Atomic Tests 2643
1718	Employees' State Insurance Scheme 2643-44
1719	Co-operative Society 2644
1720	D.T.U. 2644
1721	Co-operative Farming 2645
1722	Joint Shipping Service between India and Germany 2645
1723	Bridge over Ganga at Patna 2645-46
1724	Navigation in Brahmaputra 2646
1725	Tube-wells in Orissa 2646
1726	Rice Production in Orissa 2646-47
1727	Aerodrome at Konark 2647
1728	Joint Farming Pilot Schemes in Orissa 2747-48
1729	Financial Assistance to Orissa 2648
1730	Rates of Sweets in Delhi 2648-49
1731	Avro 748 2649
1732	Central Food Storage Godown, Gwalior 2649
1733	Bombay-Pooan and Bombay-Nasik Roads 2649-50

के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1734	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का वन विभाग	.
1735	बेगमपेट में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का इंजीनियरिंग बेस	2650
1736	राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड,	2650-51
1737	बेपुर नदी को गहरा करना	2651
1739	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	2651
1740	केन्द्रीय सड़क उपकर निधि	2652
1741	कोयम्बटूर-बंगलौर-मद्रास उड़ान	2652
1742	अननुसूचित आदिम जातियां	2652-53
1743	ऊन अनुसन्धान केन्द्र	2653
अबिलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
(एक) चीन के प्रधान मंत्री को ले जाने वाले विमान की कलकत्ता के ऊपर से उड़ान करने के समाचार		
		2653-54
	श्री हुकम चन्द कछवाय :	2654
	श्री स्वर्ण सिंह	2654
(दो) पश्चिम बंगाल सीमा पर पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोला-बारी :		
	श्री यशपाल सिंह	2655
	श्री स्वर्ण सिंह	2658
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	2659
	राज्य-सभा से सन्देश	.
	प्रयत्नकलन समिति]	.
	चौहतरवां प्रतिवेदन	2659
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	2659
	पहला प्रतिवेदन	.
अनुदानों की मांगें		
प्रतिरक्षा मंत्रालय :		
	श्री जोकीम आल्वा	2659
	श्री नारायण दांडेकर	2659-60
	श्री रघुनाथ सिंह	2662-64
	श्री श्याम लाल सर्राफ	2664-70
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	2667-70
	श्री मजीठिया	2670

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

<i>Unstarred Questions Nos.</i>	<i>Subject</i>	PAGES
1734	Forest Department of Andaman and Nicobar Islands	2650
1735	I. A. C. Engineering Base at Begumpeta	2650-51
1736	National Shipping Board	2651
1737	Dredging in Beypore	2651
1739	I.C.A.R.	2652
1740	Central Road Cess Fund	2652
1741	Coimbatore-Bangalore-Madras Flights	2652-53
1742	Denotified Tribes	2653
1743	Wool Research Centre	2654

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

(i) Flight of Chinese Premier over Calcutta :

Shri Hukam Chand Kachhavaia	
Shri Swaran Singh	2655

(ii) Pakistan Rifles firing on West Bengal Border :

Shri Yashpal Singh	
Shri Swaran Singh	2658

Papers laid on the Table

Messages from Rajya Sabha	
Estimates Committee	2658
Seventy-fourth Report	2659

Committee on Public Undertakings 2659

First Report	2659
------------------------	------

Demands for Grants 2659

Ministry of Defence	1659
Shri Joachim Alva	2659
Shri N. Dandeker	2660-62
Shri Raghunath Singh	2662-64
Shri Sham Lal Saraf	2664-67
Shri Indrajit Gupta	2667-70
Shri Majithia	2670

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	2671-72
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	2672-73
श्रीमती शारदा मुर्जी	2673-74
श्री नाथ पाई	2674-76
श्री रवीन्द्र वर्मा	2676-78
श्री बृजराज सिंह कोटा	2678
श्री शिकरे	2679
श्री इकबाल सिंह	2679
श्री यशपाल सिंह	2681
श्री मं० रं० कृष्ण	2681-84
श्री यशवन्तराव चह्वाण	2684-89

<i>Subject</i>	PAGES
Shri Surendra Pal Singh .	2671-72
Shri Jagdev Singh Siddhanti	2672-73
Shrimati Sharda Mukerjee	2673-74
Shri Nath Pai . . .	2674-76
Shri Ravindra Varma . . .	2676-78
Shri Brij Raj Singh Kotah	2678
Shri Shinkre .	2679
Shri Iqbal Singh . . .	2679
Shri Yashpal Singh .	2681
Shri M.R. Krishna .	2681-84
Shri Y.B. Chavan	2684-89

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 30 मार्च, 1965/9 चैत्र, 1887 (शक)

Tuesday, 30 March, 1965 [Chaitra 9, 1887 (Saka)]

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at the eleven of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Oral Answers to Questions

Separate Ministry for S.Cs. and S.Ts.

*539. {⁺ Shri Hukam Chand Kachhavaia :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Siddiah :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Scheduled and Backward Classes League has approached Government for setting up a separate Ministry to look after the interests of Scheduled and Backward Classes ;

(b) whether any such proposal is under consideration of Government ;
and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) सरकार को मार्च, 1964 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी जातियों के अखिल भारतीय संघ, नई दिल्ली से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। संघ को एक मांग ये भी थी कि केन्द्र तथा राज्यों में पिछड़ी जातियों के हितों का ध्यान रखने के लिये अलग मंत्रालय स्थापित किए जाएं। इस बारे में सरकार के विचार सभा में 22 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या, 2381 के उत्तर में बताये जा चुके हैं। केन्द्र में अलग मंत्रालय बनाने के प्रश्न पर ध्यान पूर्वक विचार किया गया था,

परन्तु अलग मंत्रालय की आवश्यकता नहीं समझी गई। अधिकतर राज्यों में पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु अलग विभाग है। इस उत्तर के बाद केन्द्र में सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना हो चुकी है। पिछड़ी जातियों का कल्याण इस विभाग का एक महत्वपूर्ण विषय है।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Is it a fact that the Ministry of Home Affairs is very hard-pressed with work and therefore, they are not able to pay proper attention to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? If so, taking into account all these factors why the creation of a separate Ministry has not been considered by Government?

Mr. Speaker : She has stated that this work has now been transferred to the Ministry of Social Security and the Ministry of Home Affairs is no more dealing with it.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : During the past many years the works relating to the uplift of these classes could not be done as envisaged. In view of this fact whether government propose to give special powers and information to this Ministry?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जैसा मैंने मूल उत्तर में कहा, इस सामाजिक सुरक्षा विभाग में पिछड़ी जातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और विशिष्ट योजनाएँ तैयार की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस सम्बन्ध में इस विभाग को विशेष अधिकार प्रदान करने की कोई योजना है ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस मंत्रालय के विस्तार की संभावना को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने खान कल्याण बोर्ड को इस मंत्रालय के नियंत्रण में लाने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इसके लिए एक अलग प्रश्न की सूचना दी जाये।

विधि तथा समाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : यह प्रश्न प्रधान मंत्री जी से पूछा जाना चाहिये।

Shri Gulshan : Is it not a fact that at present when the prices are ruling very high, 90 per cent. Scheduled Castes and Backward classes are starving? It was contemplated to start 30 community development projects for providing employment to them. May I know how many of these have since been opened.

श्री अ० कु० सेन : केवल आदिम जातियों के लिये आदिम जाति कल्याण खंडों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के लिये अलग खंड बनाने का कभी कोई विचार नहीं था।

श्री सुबोध हंसदा : क्या डेबर आयोग ने यह सिफारिश की थी कि ऐसे सभी राज्यों में, जहाँ आदिम जातियों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इसके लिये एक पृथक विभाग होना चाहिए और यदि हो, तो क्या राज्यों का ध्यान इस ओर दिलाया गया था? कितने राज्यों ने यह विभाग बना दिया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ऐसी सिफारिश की गई थी। यह निश्चय किया गया कि केन्द्र में पृथक मंत्रालय की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि प्रायः सभी राज्यों में सामाजिक सुरक्षा के लिये पृथक विभाग हैं जो हरिजन कल्याण सम्बन्धी विषयों का काम करते हैं।

Shri Naval Prabhakar: Is the Ministry of Social Security doing the work hitherto done by the Home Ministry or it is doing some special work for them ?

श्री अ० कु० सेन : वह सभी काम तथा और अधिक काम हो रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या उनको ये अथवा इससे कुछ कम रियायत दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एक पृथक मंत्रालय के बारे में है।

Amenities to Tourists

*640 { **Shri S.C. Samanta :**
Shri M.L. Dwivedi :
Shri Yashpal Singh :
Shri Koya :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the arrangements regarding amenities, entertainment and boarding for foreign tourists at tourist centres, places of interest along sea-coasts and places of historical importance in this country are not satisfactory as compared to those existing at the tourist centres in other countries ;

(b) if so, the steps proposed to be taken in this direction ;

(c) whether the Ministry of Transport has made any study of the arrangements existing at tourist centres in foreign countries with a view to introducing them in India ; and

(d) the estimated allocation for the above-mentioned purposes during the fourth Five Year Plan ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या ए० टी०--4090/65)।

श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूँ कि पर्यटन की उन्नति के लिये विदेशी पर्यटकों द्वारा सुझाव देने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ? क्या इस प्रक्रिया को बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री राज बहादुर : आने वाले पर्यटकों का मत जानने के लिये हम अनेक कदम उठाते हैं। हमने केलिफोर्निया की एक प्रसिद्ध अनुसंधान संस्था से अनुरोध किया है कि वह भारत से लौटने वाले पर्यटकों का इन्टरव्यू करें तथा उनकी प्रतिक्रिया हमें बताये। हम विशेषतया पर्यटन में रुचि रखने वाली पत्रिकाओं के पत्रकारों के दलों को हमारे पर्यटन के स्थानों व उपलब्ध-सुविधाओं का अध्ययन करने के लिये भी आमंत्रित करते हैं और वे अपना मत प्रकट करते हैं, इसके अन्य तरीके भी हैं।

श्री स० चं० सामन्त : पर्यटन की उन्नति के लिये किस प्रकार के पर्यटन निगम स्थापित किये गये हैं अथवा स्थापित करने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : समय समय पर हमें बताया गया है कि होटल आवास की बहुत कमी है तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की भी कमी है जैसे परिवहन, खरीदारी व मनोरंजन आदि। इन सब कमियों को दूर करने के लिये दो निगम स्थापित करने का विचार है। एक तो भारतीय होटल पर्यटन निगम (होटल इण्डिया टूरिज्म कारपोरेशन) स्थापित कर दिया गया है जो जहां भी होटल आवास की कमी है उसको दूर करने का प्रयत्न करेगा। हमने जो रेस्तोरां व होटल स्थापित किये हैं, यह उन की भी देखभाल करेगा। और भी मोटल स्थापित किये जा सकते हैं। दूसरा निगम मनोरंजन व सामान खरीदने की सुविधाओं, पर्यटन परिवहन, प्रचार सामग्री आदि की व्यवस्था का काम रेगा।

Shri Yashpal Singh : It appears from this statement that wherever there is shortage of hotel accommodation, no socialistic curbs are applied on the incomes of hoteliers who charge exorbitant rates. May I know the action Government propose to take in the matter?

Shri Raj Bahadur : No, Sir. We exercise control over it and impose restrictions on the rates also. We apply these controls in the matter of granting licences for import of their requirements from abroad and attention is also paid that proper facilities are provided to them.

Shri Bibhuti Mishra : Has it come to the knowledge of the Hon. Minister that no facilities are available to Raxaul to lakhs of Indians and foreigners proceeding to Pashupatinath Temple, Kathamandu? What arrangements are being made in this behalf?

Shri Raj Bahadur : It will be attended to as far as our finances permit.

Shri Achal Singh : May I know whether this Ministry looks after foreign tourists only or Indian tourists as well?

Shri Raj Bahadur : It is our considered opinion that it is most essential for the development of any tourist Centre that attention is paid not only to the amenities of foreign tourists but also to the amenities of inland tourists. More attention should be paid to its own tourists for fostering the growth of tourist amenities at any place.

श्री अ० ना० विद्यालंकार : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों की सहायता व मार्गदर्शन करने के लिये हवाई अड्डों और अन्य अवतरण स्टेशनों पर पर्यटन विभाग के कुछ अधिकारियों के उपस्थित रहने के सुझाव पर विचार किया है ताकि विदेशी पर्यटकों की इन आम शिकायतों को दूर किया जा सके कि सीमा-शुल्क तथा अन्य पड़ताल चौकियों पर कुछ अधिकारियों का व्यवहार साधारणतया कष्टकारक तथा तंग करने वाला होता है ?

श्री राज बहादुर : गत समय में सीमा शुल्क अधिकारियों व अन्य अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध अनेक शिकायतें थी। ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिये हमने एक सम्मिलित आन्दोलन किया था और हमने सीमा-शुल्क अधिकारियों का एक विशेष पूल बनाया है जिसमें से अधिकारियों को विभिन्न हवाई अड्डों व अन्य प्रवेशद्वारों पर तैनात किया जायेगा। ऐसी शिकायतों की जांच करने तथा अच्छे से अच्छे ढंग से पर्यटकों की सहायता करने के लिये हमने पर्यटन अधिकारी भी नियुक्त

किये हैं। मैं कह सकता हूँ कि अब ये शिकायत बहुत कम हो गई हैं। वास्तव में, पहले की अपेक्षा ये बहुत कम हैं।

Shri Sinhasan Singh : May I know whether some Indian style rest houses have been constructed where Indian tourists may stay at a cheaper rate.

Shri Raj Bahadur : We have tried to construct cheap rest houses, called Low Income Group Houses, at some places. These could not be constructed in sufficient numbers but a beginning has been made. I hope they will expand.

डा० मा० श्री० अग्ने : क्या सरकार को पर्यटन के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये कोई विशेष परामर्शदात्री समिति है, जिसके सदस्य विदेश घूमे हुए व्यक्ति भी हैं ?

श्री राज बहादुर : हमारी एक पर्यटन विकास परिषद् है जिसमें इस सदन को व दूसरे सदन को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मैंने इस प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं किया है कि इसके सदस्य विदेशों में प्राप्त सुविधाओं का अध्ययन करने के लिये वहाँ भी जायें। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूँ।

श्री दाजी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या लाल किले में चालू किया गया प्रकाश तथा ध्वनी का नया कार्यक्रम पर्यटकों में सफल रहा है और क्या सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं कि सारे कार्यक्रम से महात्मा गांधी व मौलाना आज़ाद को निकाल देने से पर्यटकों को इससे राष्ट्रीय आन्दोलन का इकतरफा दर्शन होता है ?

श्री राज बहादुर : जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है सीटों की बहुत भारी बुकिंग हो रही है। वास्तव में, अन्त के दो दिनों के लिये अनेक दर्शकों को स्थान नहीं मिल सका। प्रश्न के दूसरे भाग पर वास्तव में विचार किया गया था और चूँकि लाल किले की सच्ची ऐतिहासिक कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास था, हमने यह सोचा कि जहाँ तक संभव हो यह यथार्थ होनी चाहिये। विशेषज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों का यह प्रबल मत था कि यदि किसी नाटकीय साधन से महात्मा गांधी के नाम का भी उल्लेख हो सके तो उस पर विचार करना चाहिये। जब भी हम इसकी लिपि पर पुनर्विचार करेंगे तो हम इतिहासक खंडन किये बिना इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे तथा व्यक्त किये गये उद्गारों पर विचार करेंगे।

Shri Yudhvir Singh : Have the attention of the Government been drawn to the fact that the knowledge of history of the guides, conducting the visitors round various historical places, is so little that a guide taking a tourist round the Ajanta caves attributed the paintings there to the Moghal period according a newspaper report. May I know whether Government is contemplating to appoint guides, well up in history, at the places of historical importance ?

Shri Raj Bahadur : Of course, some old timers are there. We can not remove them on block because it will create unemployment. But I have stated that we have got guides, selected systematically. They are graduates of history. They are well trained in their job and perform their duties well. Whenever complaints are received they are looked into.

श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ : पर्यटकों की एक प्रमुख शिकायत इंडियन एअरलाइन्स की भयजनक थल सेवा के विरुद्ध है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार सजगता से इस पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इसको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : हवाई अड्डों पर सुविधाओं को उन्नत बनाने का निरन्तर प्रयास किया जाता है और मुझे विश्वास है कि असैनिक उड्डयन मंत्रालय इस समस्या के बारे में पूर्णतया सजग है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 13

+

*641. { श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 13 के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ; और
(ख) चालू वर्ष में उपरोक्त राजपथ के निर्माण के लिये मंजूर की गई धन राशि में से अब तक कितनी रकम खर्च हो चुकी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 13 के स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति नीचे दी जा रही है :—

1. सड़क सुधार कार्य : जंगल काटना, कटाई-भराई और सामान को इकटित करने का काम शुरू कर दिया गया है। कुल 0.9 प्रतिशत प्रगति हुई है।

2. तृंगभद्रा नदी के ऊपर का पुल :

सामान इकट्ठा करने और आधार से सम्बन्धित निर्माण कार्य शुरू कर दिये गये हैं। कुल 0.7 प्रतिशत प्रगति हुई है।

3. डोन नदी के ऊपर का पुल :

सामान इकट्ठा करने और आधार से सम्बन्धित निर्माण कार्य शुरू कर दिये गये हैं। कुल 10 प्रतिशत प्रगति हुई है।

4. कुस्तगी और हौस्पेट के बीच की सड़कों के लिये भूमि प्राधिकरण कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) चालू वर्ष के 10.75 लाख रुपये के बजट आवण्टन के विपरीत अबतक 2,07,802 रुपये खर्च किये गये हैं।

श्री रा० गि० दुबे : मंत्री महोदय ने इस राजपथ के निर्माण में जो रुचि दिखाई यद्यपि मैं उसकी पूर्ण सराहना करता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतना कम व्यय क्यों हुआ है ? 10 लाख और कुछ रुपये की मंजूर की गई राशि में से केवल 2 लाख और कुछ रुपये ही खर्च किये गये हैं।

श्री राज बहापुर : यद्यपि मैं कम खर्च के लिये उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटूंगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि सड़क-निर्माण आदि जैसे कार्यों, विशेषकर नये कार्यों के लिये प्राक्कलन तैयार करने, टेंडर मंगाने तथा काम करने के लिये ठीक प्रकार के ठेकेदारों के चुनाव में समय लगता है ।

पुराने जहाजों को बदलना

+

*642. { श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन प्बोर्ड ने पुराने जहाजों को बदलने और नये जहाज प्राप्त करने में अन्य असमर्थताओं को दूर करने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान परिस्थितियों में जहांतक संभव है उस सीमा तक राष्ट्रीय नौपरिवहन मंडल की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of ships to be replaced ?

Shri Raj Bahadur : We make its periodical assessment. The following types are to be replaced :—

9 Liner, 1 Tramp and 3 Cargo cum-Passenger Vessels. These are over seas Vessels and the following Vessels are for coastal trade :

Colliers	26
General cargo carriers which are less than 3500 G.R.T. .	25
Tanker	2

These will be replaced by the end of next Plan period.

Shri Yashpal Singh : May I know the amount of foreign Exchange involved in it ?

Shri Raj Bahadur : It will depend on the costs of the ships to be procured for replacement.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : ये कितने टन भार के होंगे ?

श्री राज बहादुर : इसका हिसाब लगाना पड़ेगा ।

रिंग रोड, दिल्ली

+

*644. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री श्रींकार लाल बेरवा :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिंग रोड पर रोशनी की व्यवस्था करने का निश्चय कब किया गया था ;

और

(ख) इसको क्रियान्वित करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) रिंग रोड मुख्यतः उन तेज मोटर गाड़ियों के सीधे यातायात के लिये बनाई गई थी जो अपनी गाड़ी के प्रकाश द्वारा चलती है और इसीलिये इस सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था जरूरी नहीं समझी गई। फिर भी कई स्थानों से निरन्तर मांग के कारण, फरवरी 1963 में यह निश्चय किया गया कि सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था की जाये। इस कार्य को दिल्ली प्रशासन ने हाथ में लिया और उन्होंने इस कार्य की लागत की पूर्ति के लिये जिसका अंदाजा 12 लाख रुपये था भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी। चूंकि प्रकाश की व्यवस्था करना एक नागरिक सुविधा है, अतः इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया कि सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिये भारत सरकार कानूनी तौर पर जिम्मेदार है। उसे अब यह सलाह दी गई है कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति और दिल्ली नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र की सड़क के भागों पर प्रकाश की व्यवस्था का दायित्व परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार का है और दिल्ली कन्टूनमेंट बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र की सड़क के भागों पर प्रकाश करने के लिये जिम्मेदार है। इस प्रयोजन के लिये धन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : May I know the time by which Government propose to make lighting arrangements on the Ring Road and the cost thereof ?

Shri Raj Bahadur : I have already stated in the reply that it was to be decided as to who would bear the expenditure for providing light on that road. Now it has been decided that the Ministry of Transport will be responsible for this work. This will be undertaken as soon as funds are available.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Do the Central Government propose to have such schemes in big cities ?

Shri Raj Bahadur : If Ring Road is constructed there as National Highway, Government will consider it.

Shri Naval Prabhakar : Will the Minister be pleased to state whether the overbridges constructed on the Ring Road have been put to use ?

Mr. Speaker : This does not relate to the original question.

केन्द्रीकृत बीज उद्योग

+

* 645. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में केन्द्रीकृत बीज उद्योग विकसित करने के लिए विदेशी फर्मों को भागीदार बनाने के लिए प्रयत्नशील है;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के उद्योग को भूमि सीमा अधिनियम से छूट देना चाहती है; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किये गये बीज संतुलित कार्यक्रम का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केन्द्रीकृत बीज उद्योग विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी "प्रोस्पैक्ट्स फार सीड इंडस्ट्री इन इंडिया" नामक एक पुस्तिका को तैयार करके प्रिचरित किया गया है ताकि उन विदेशी कम्पनियों को आकर्षित किया जाए जोकि देश में एक सुदृढ़ बीज उद्योग स्थापित करने में भारतीय कृषकों के साथ सहयोग करने में दिलचस्पी रखें हों ।

(ख) तकनीकी कारणों से जब भी आवश्यकता होगी इस पर विचार किया जाएगा ।

(ग) "सीड सेच्यूरेशन प्रोग्राम" के अन्तर्गत इस समय तक लगभग 1015 लाख एकड़ भूमि का क्षेत्र सुधरे बीजों के अन्तर्गत लाया गया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अब तक किन किन देशों ने इस कार्य के लिए सहायता देने की पेशकश की है ?

श्री शाहनवाज खां : इस समय रूस, अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी कृषि कार्यों के लिए सक्रिय रूप से सहायता दे रहे हैं । किन्तु विशेष परियोजना के लिए कुछ देशों की उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस उद्योग के संगठित आधार पर महत्व को देखते हुए सरकार ने इसके लिए आगामी चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की कोई विशेष व्यवस्था की है ।

श्री शाहनवाज खां : हम इसके महत्व को अच्छी तरह समझते हैं । इस सम्बन्ध में राज्य सभा बीज विधेयक पारित कर चुकी है और आशा है लोक सभा भी इसे चालू सत्र में पारित कर देगी । उसके पश्चात् हम मामले में गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करेंगे ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Government have made up their mind regarding seed farms ? Government are having a scheme to open a seed farm in every Block but due attention is not being paid to it. Do they propose to develop seed farms ?

Shri Shahnawaz Khan : Yes, Sir There are about four thousand seed multiplication farms. After having experiments on these we have come to the conclusion that instead of having small farms we should have big farms, like Surat Farm, on which we may have our own control. These farms should have more area than fivehundred acres so that we may look after them properly and afford to engage experts in these farms. We intend to have such farms in the country.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने पंजाब में एक केन्द्रीय बीज फार्म खोलने की वांछनीयता पर विचार कर लिया है ?

श्री शाहनवाज खां : जी, हां । इस पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has stated that the farms opened in various States are not working satisfactorily. Do the Government propose to open such central farms and if so at what cost ?

Shri Shahnawaz Khan : I have not said that all farms are not working satisfactorily. Many of them are working in a very satisfactory manner. Our experience shows that we can work more efficiently on big farms like Suratgarh Farm, Jethsar Farm.

Shri U.M Trivedi : The hon. Minister has just stated that about four thousand farms are running in the country. I want to know their production and the loss incurred on these farms.

Shri Shahnawaz Khan : The hon. Member should give separate notice for it because we will have to collect figures in this regard. All farms are running satisfactorily. Therefore the question of loss does not arise.

Shrimati Lakshmi Bai : According to the hon. Minister the farms are running very satisfactorily. I want to know the expenditure being incurred on these farms and the income derived from them.

Shri Shahnawaz Khan : Each of these farms has an area of 25 acres and mostly all of them are selfsufficient.

Shri J. P. Jyotishi : The profit expected from these farms is not being derived. What are the reasons for it ?

Shri Shahnawaz Khan : These are small farms. We cannot engage experts to supervise these farms. Therefore, now we have decided to establish big farms so that scientists and experts could be engaged to supervise them properly.

श्री तिरूमल राव : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कुछ बीज फार्मों में पैदा किया गया बीज आनाज मंडियों में बेचा जाता है जहां उसके अधिक मूल्य प्राप्त होते हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : ये बीज फार्म राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं । अतः में समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि बिड़ला जैसे बड़े व्यापारियों को बीज फार्म के लिए पंजाब में हजारों एकड़ भूमि दी गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां । पंजाब में उनके बीज फार्म है । किन्तु इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें कितनी भूमि दी गई है ।

Shri Rameshwaranand : How the seeds produced in these farms are distributed among the farmers ?

Shri Shahnawaz Khan : It is distributed from the Headquarters. These are also distributed through Cane Developing Societies and Cooperative Societies.

Shri R. S. Tiwary : According to the hon. Minister the Government propose to establish big farms. May I know whether the Suratgarh Farm is running on profit or loss ?

Shri Shahnawaz Khan : It is a fact that Suratgarh Farm is running on loss because it is a desert area and there is no provision to irrigate the whole area. I hope this desert will be turned into greenery when the whole area will be irrigated by the Rajasthan Canal.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : कई सरकारी संस्थाओं द्वारा बीज का वितरण किया जाता है । क्या सरकार को इस बात का पता है कि इसमें से कई बीज फूटते भी नहीं है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रश्न को नहीं समझा ।

Shri Rameshwaranand : I rise on a point of order. The seeds produced in these farms do not reach the farmers. That is why the production is very low.

Mr. Speaker : There is no point of order in it.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : कई सरकारी संस्थाओं द्वारा वितरित किये जाने वाले बीज में अंकुर नहीं फूटता है ।

श्री शाहनवाज खां : इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस बात की जांच करें कि इस प्रकार की कार्यवाही के लिए कौन उत्तरदायी है ।

श्री कपूर सिंह : आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं का दाना काला हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि यह बीज किस राज्य में पैदा किया गया था ?

श्री शाहनवाज खां : हम इस बारे में सूचना एकत्रित करेंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : शायद माननीय सदस्य यह जानने के इच्छुक हैं कि यह बीज पंजाब से आया ।

अध्यक्ष महोदय : कदाचित वह जिले और गांव का नाम भी जानना चाहते हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या राज्यों के विभिन्न जिलों में विभिन्न जलवायु को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर बड़े फार्म खोलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री शाहनवाज खां : यदि भूमि उपलब्ध हुई तो हम ऐसे कई फार्म खोलेंगे । आरम्भ में हम एक राज्य में एक फार्म खोलेंगे और हमें आशा है कि बाद में जिलों में भी यह फार्म खोले जायेंगे ।

Financial Conditions of Panchayats

+

*646. { **Shri Siddheshwar Prasad :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri D. J. Naik :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Balwantrai Mehta Committee appointed to study the financial resources of the Panchayat i Raj institutions has submitted its interim report ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) the reaction of Government thereon ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां (ख) अंतरिम रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4091/65]

(ग) सलाहकार परिषद् ने 29 मार्च, 1965 को अपनी बैठक में समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार किया है और अब सरकार उस पर विचार कर रही है ।

Shri Siddheshwar Prasad : Sir, according to the statement, Panchayati Raj Institutions have not adequate finances to perform their function and it has been recommended that the Central Government should give some grant to them. May I know the decision taken by the Government in this respect ?

श्री ब० सू० मूर्ति : रिपोर्ट हाल में ही प्राप्त हुई है और संबन्धित मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है । इसे राज्यों को भी भेजा जायेगा । अतः केन्द्र अभी इस बारे में कुछ निर्णय नहीं कर सकता ।

Shri Siddheshwar Prasad : It is also one of the recommendations made in the report that the Panchayats should be empowered to levy more taxes. May I know the decision taken by the Government, and instructions issued to State Governments and Panchayats in this regard ?

श्री ब० सू० मू : सम्बन्धित राज्यों के वर्तमान कानून के अनुसार पंचायतों को पहले से ही कुछ कर लगाने के अधिकार हैं । इन करों का इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है : (क) उनके द्वारा लगाये गये करों से प्राप्त आय; (ख) शुल्क तथा प्रभार; (ग) सम्पत्ति, विनियोजन तथा लाभ कमाने वाले उपक्रमों से प्राप्त आय और साधारणतः पंचायतें मकान, मोटरगाड़ियों तथा व्यवसाय पर कर लगा सकती हैं ।

इन करों से 1962-63 में महाराष्ट्र राज्य को अनुदान के अतिरिक्त 474.50 लाख रुपये की आय हुई तथा बिहार राज्य को 0.45 लाख रुपये की आय हुई । यह आय सब राज्यों से कम है ।

Shri Yashpal Singh : There is no mention about the dues of Panchayat Tax to be realised and the misappropriation of lakhs of rupees in the statement. How these huge amounts will be realised for the benefit of rural areas ?

श्री ब० सू० मूर्ति : विवरण में इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

आंध्र प्रदेश में भू-राजस्व वसूली का कार्य पंचायतों को सौंपा गया था । यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप पंचायतों को 4000 रूपये से 8000 रूपये तक कमीशन मिल रहा है । किन्तु साधारणतः भू-राजस्व वसूली का कार्य पंचायतों को नहीं अपितु भू-राजस्व अधिकारियों को सौंपा जाता है । अतः पंचायतों को कर लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती है ।

Shri Ram Harkh Yadav : May I know the steps taken to improve the deplorable condition of Panchayats, particularly in Uttar Pradesh, which are the foundation of democracy ?

श्री ब० सू० मूर्ति : सभा-पटल पर रखे गए विवरण में कुछ सुझाव दिये गये हैं । या तो केन्द्र सरकार सीधे अनुदान दे सकती है अथवा राष्ट्रपति वित्त आयोग को निर्देश दे सकते हैं कि वे पंचायतों के मामलों की ओर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारों को दिये गये अनुदान पंचायतों की आवश्यकता के अनुसार आवंटित किए जायें । इन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगा और इस पर काफी समय लगेगा ।

Shri Vishwanath Pandey : Taking into consideration the fact that due to inadequate funds Panchayati Raj Institutions are unable to function properly, how much amount will be required to run them properly and how the Government propose to finance them ?

श्री ब० सू० मूर्ति : राज्य सरकारें उचित ढंग से कार्य कर रही हैं । पंचायतों को अनुदान तथा कर लगाने के लिए अधिकार दिए जा रहे हैं । किन्तु यह काफी नहीं है । अतः समिति ने उन्हें अधिक धन देने तथा उन्हें व्यवस्थित करने की सिफारिश की है ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं जानना चाहता हूँ कि जब मंत्रालय ने पहले ही पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय साधनों की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया था तो दूसरी समिति नियुक्त करने के क्या कारण हैं तथा इस समिति के विशेष निर्देश पद क्या हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : वह समिति केवल पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय साधनों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी । इस समिति ने अनेक पहलुओं पर विचार किया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Is it a fact that the Congressmen are responsible for the embezzlement and irregularities which were found in the Panchayati Raj institutions ?

श्री ब० सू० मूर्ति : कांग्रेसियों को कोई एकाधिकार प्राप्त नहीं है ।

Shri Yudhvir Singh : It has been mentioned in the statement that the Committee have given some suggestions for improving the financial position of the Panchayats. It has also been mentioned that the collection of land revenue in Andhra Pradesh has been entrusted to Panchayats and they are functioning very satisfactorily. But the experience gained in other parts of the country shows that the Panchayats have not been able to realise even fifty percent of the tax levied in villages in addition to the land revenue. May I know whether Government are in a position to suggest some measures or machinery to the Panchayati Raj institutions in order to enable them to have a smooth realisation of taxes ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जहां तक मालगुजारी का सम्बन्ध है आन्ध्र प्रदेश 25 प्रतिशत, आसाम 15 प्रतिशत तथा विहार 6½ प्रतिशत दे रहा है । धीरे धीरे सारी मालगुजारी पंचायतों को दी जायेंगी ।

Shri Yudhvir Singh : May I know the steps being taken by Government to realise the taxes levied by Panchayats in addition to the land revenue ?

श्री ब० सू० मूर्ति : राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य तथा अन्य मदों पर किया जाने वाला सारा व्यय भी पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : आन्ध्र प्रदेश के अन्य अन्य राज्यों में पंचायतों बकाया राशि वसूल करने में असमर्थ हैं । इनकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : सभी राज्य सरकारें इन संस्थाओं को कुछ कार्यों के लिए काफी अनुदान दे रही हैं ।

Shri Yudhvir Singh : Mr. Speaker Sir, in spite of your repeated instructions my question has not been answered properly.

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : लोगों से कर वसूल करने में राज्य सरकारें पंचायतों की पूरी सहायता कर रही हैं । आज यह धारणा बन रही है कि राजस्व वसूल करने वाली संस्था पंचायती राज संस्थाओं का कर वसूल करें । हमें अभी इसके बारे में अंतिम निर्णय लेना है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का अधिकांश भाग सत्तारूढ़ दल के चुनाव अथवा चुनाव की तैयारी पर खर्च किया जाता है । क्या चुनावों पर इस प्रकार के अपव्यय को रोकने के लिए कोई व्यवस्था है ?

श्री सु० कु० डे : माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना निराधार है ।

श्री दाजी : क्या सरकार को पता है कि पंचायतों को अधिक सहायता देने से बचने के लिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य पंचायती राज लागू नहीं कर रहे हैं । आश्वासन दिये जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू नहीं किया गया । सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सु० कु० डे : यह बात सच नहीं है । मुझे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पहले ही राज्य में पंचायती राज लागू कर दिया जायेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या उन्होंने तथ्यों के बारे में पता लगाया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है ।

Shri Sheo Narain : May I know terms of reference of the Committee appointed by the Government and whether this Committee have suggested to disband the Panchayati Raj institutions ?

श्री सु० कु० डे : पंचायती राज को तोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता । कोई भी अब इन संस्थाओं को नहीं तोड़ सकता । सन्तानम समिति वित्तीय साधनों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई थी जबकि बलवन्त राय मेहता समिति दूसरे मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई थी । बलवन्तराय मेहता समिति को सौंपे गये विषयों का विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

एयर इंडिया के विज्ञापन

+

*647. { श्री प्र० चं० बरुआ :
 श्री यशपाल सिंह :
 श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
 श्री फ० गो० सेन :
 श्री राम सेवक :
 श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या असेनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1965 में 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित एयर इण्डिया के एक विज्ञापन में भारत के नक्शे से काश्मीर को निकाल दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

असेनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). "हमें एक बार यह कहना चाहिए कि एयर इंडिया की जेट सेवा बम्बई तक प्रतिदिन चलती है और उसकी नयी दिल्ली के लिए सबसे तेज सेवा है" नामक विज्ञापन, कारपोरेशन की बम्बई और दिल्ली के लिए जेट सेवाओं पर विशेष प्रकाश डालने के लिए अमेरिका में एयर इण्डिया के विज्ञापन एजेंटों द्वारा तैयार किया गया था । बम्बई और दिल्ली को भारत के एक 'रफ' खाके में दिखाया गया था, भौगोलिक नक्शे में नहीं । भारत की राजनैतिक या भौगोलिक सीमाओं को बताना इसका उद्देश्य नहीं था । क्योंकि इस विज्ञापन को गलत तरीके से समझा जा सकता था इसलिए कारपोरेशन द्वारा इसे तुरन्त वापस ले लिया गया ।

(ग) भारत की सीमाओं को बताने वाले नक्शे को जब कभी इस्तेमाल करना हो, इसके बारे में एयर इण्डिया में सम्बद्ध सभी को बहुत सावधानी बरतने की उचित रूप से हिदायत दे दी गयी है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी विज्ञापन अभिकरण ने किन परिस्थितियों के कारण इस भ्रामक खाके को प्रकाशित किया था, इस खाके के प्रकाशित होने के कितनी देरी के बाद इस त्रुटि का पता लगा और इसे ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कानूनगो : जैसा विवरण में बताया गया है, यह भारत का मानचित्र नहीं था, क्योंकि भारत के बहुत से भाग इस में नहीं दिखाये गये हैं । तथापि न्यूयार्क से पी० टी० आई० के सन्देश से पता चलता है कि कुछ गलतफहमी हो गई थी और विज्ञापन को तुरन्त ही वापिस ले लिया गया था और उसके स्थान पर पुनरीक्षित विज्ञापन पारचालित किया गया था ।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी अभिकरण भी भारत के मानचित्र की पवित्रता के लिये विशेष सम्मान नहीं रखते हैं क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का

विचार विज्ञापन के लिये मानचित्रों को छानने में कोई प्रतिबन्ध लगाने का या कोई नियम बनाने का है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कानूनगो : जैसा मैं पहले कह चुका हूँ यह भारत का मानचित्र नहीं था। इसमें भारत का कुछ भाग दिखाया गया था, विशेषकर जेट सेवा के लिये बम्बई और दिल्ली को दिखाया गया था।

Shri Sidheshwar Prasad : The Hon. Minister has stated in his reply that it was a 'rough' map of India. May I know what portions were not shown in it apart from Kashmir; and if only Kashmir was omitted does it not indicate that it was done intentionally ? What is the correct position in this regard ?

श्री कानूनगो : जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था मैंने उसे देखा है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश का तथा आसाम के भागों सहित सारा पूर्वी भारत नहीं दिखाया गया था और दक्षिण भारत का भी बहुत भाग नहीं दिखाया गया था क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य बम्बई और दिल्ली को दिखाना था।

Shri Yashpal Singh : May I know whether it is correct that in a map in Kremlin in Russia, Kashmir has been shown as Disputed part—a common part.

Mr. Speaker : The hon. Member is asking about a map in Kremlin which has no connection with this question.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it correct that first of all some American had drawn the attention towards the map of Air India which is under discussion today and our embassy in U.S.A. has criticised Air India's this tendency ?

श्री कानूनगो : मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि किस ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था परन्तु मेरी जानकारी तो यही है कि इस गलतफहमी के लिये न्यूयार्क से पी० टी० आई० के एक सन्देश से हमें यह पता लगा। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ यह भारत का मानचित्र नहीं था। इसके पश्चात् विज्ञापन को वापिस ले लिया गया था।

Shri Prakash Vir Shastri : What did our Ambassador write ?

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य ऐसी विमान कम्पनियां भी हैं जिनके विमान भारत से होकर गुजरते हैं और जो ऐसे मानचित्र बांटती हैं, जिनमें कश्मीर को एक विवादास्पद क्षेत्र दिखाया जाता है; और यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरों का इस में कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह पहली बार ही नहीं है जबकि एयर इण्डिया ने अपने विज्ञापन के लिये जो मानचित्र दिया उस में काश्मीर को नहीं दिखाया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे मानचित्र भविष्य में नहीं प्रकाशित किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : एयर इण्डिया ने काश्मीर को मानचित्र में पहले भी नहीं दिखाया था।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : जी हां, यह बात भूतपूर्व मन्त्री के ध्यान में लाई गई थी।

अध्यक्ष महोदय : तब उन्हें इस बारे में पता नहीं है।

Shri R. S. Tiwary : China has claimed over Northern India and the same portion has not been shown in the map. Is it correct ?

Mr. Speaker : It is another issue.

हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग

+

* 648. { श्री हेमराज :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग की सिफारिशों को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है ;
- (ख) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में संसद् में कब आवश्यक विधान पेश करने का है ;
- (ग) क्या यह विधान सिखों के तीर्थ स्थानों तथा गुरुद्वारों पर भी लागू होगा ; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). सरकार इस विषय पर बड़ी तत्परता से विचार कर रही है और आशा है कि इस विषय पर शीघ्र ही विनिश्चय कर लिया जायेगा ।

(ग) और (घ). जो नहीं । यह बात आयोग के विचारार्थ विभागों के अन्तर्गत नहीं थी और आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की ।

श्री हेमराज : क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों के विचार मिल गये हैं तथा वे क्या हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : केरल और पश्चिम बंगाल तथा गोआ, पाण्डीचेरी और मनीपुर के राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों के विचार मिल गये थे । क्योंकि बहुत विचार व्यक्त किये गये हैं इसलिये उनको विस्तार से बताना कठिन है ।

श्री हेमराज : क्या मैं जान सकता हूँ कि सिख धर्म हिन्दू धर्म का ही अंग था, और यदि हां, तो क्या कारण है कि इसे आयोग को नहीं सौंपा गया ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : यह आयोग के निर्देश पद में नहीं था और इसे सम्मिलित न करना ही उचित समझा गया था क्योंकि इस प्रयोजन के लिये सिख गुरुद्वारा अधिनियम ही पर्याप्त समझा जाता है . . . (अन्तर्बाधायें)

Shri Vishwa Nath Pandey: Before enacting legislation and while considering the suggestions of this Commission will the heads of Maths be consulted in this regard ?

श्री अ० कु० सेन : आयोग ने सारे मामले की विस्तार से जांच की थी और सभी संगत बातों पर विचार किया था ।

श्री पु० र० पटेल : सिफारिशें मुस्लिम तथा ईसाई धर्मस्वों के बारे में नहीं की गई हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि केवल हिन्दुओं के लिये ही क्यों एक पृथक् कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है और इस गैर-साम्प्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी समुदायों के लिये ही क्यों नहीं ?

श्री अ० कु० सेन : जैसाकि नाम से ही पता चलता है कि यह आयोग केवल हिन्दू धार्मिक धर्मस्व के लिये ही नियुक्त किया गया था ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या कोई ऐसा कानून सरकार के विचाराधीन है जिसमें पृथक् पृथक् धर्मों के नहीं बल्कि सभी धर्मों के धर्मस्व आ जायें ?

श्री अ० कु० सेन : जी, नहीं ।

श्री श्रीनारायण दास : माननीय उपमन्त्री ने कहा है कि इन सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूँ कि इन पर निर्णय करने के लिये ठीक ठीक कितना समय लगेगा ?

श्री जगन्नाथ राव : प्रारूप विधेयक तैयार है और उस को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । विधेयक को जल्दी से जल्दी पुरःस्थापित करने का विचार है ।

Shri Sinhasan Singh : The report of this Commission was published five or six years ago *i.e.* in 1958 or 1959. May I know for how long it will remain under consideration? Have Government also got the statistics with them about the property and the income of these Mandirs ?

श्री जगन्नाथ राव : यह आयोग 1960 में नियुक्त किया गया था । इसने सरकार को अपना प्रतिवेदन 31 मई, 1962 को प्रस्तुत किया था । इसके पश्चात् राज्य सरकारों की राय मांगी गई थी । कोई असाधारण देरी नहीं हुई है । क्योंकि यह एक समवर्ती विषय है और हमें राज्य सरकारों की सिफारिशों और विचारों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है . . .

अध्यक्ष महोदय : इन की आय के बारे में ।

श्री अ० कु० सेन : जो धर्मस्व किसी कानून के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनके वास्तविक आंकड़े हमारे पास नहीं हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the attention of Government has been drawn to the fact that there are some religions in the country who are getting money from foreign countries in the name of religion and are utilising that amount for political purposes? If it is so, do Government propose to appoint a Commission to know the working and the policies of these religious Mandirs ?

Mr. Speaker : This does not relate to this question.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The Hindus alone give this money to the Mahants in all the Maths, Mandirs or Shivalayas. Have you ever thought that all this money would be utilised for the welfare of all the Communities of the Hindus only in the case of any function ?

श्री अ० कु० सेन : यह चीज हर एक मठ, न्यास, तथा धर्मस्व को ही निश्चित करनी चाहिये कि यह विशेष निधि किस प्रयोजन और किन धार्मिक सम्प्रदायों पर खर्च की जानी चाहिये ।

Shri Rameshwaranand : There was Muslim rule here for years together and then came the British rule. But they never interfered officially in religious matter. They never tried to bring any legislation in this connection. Why then the present Government considers it necessary to appoint a commission regarding religious places also ?

श्री अ० कु० सेन : हिन्दू धार्मिक धर्मस्वों के सम्बन्ध में बहुत से कानून अंग्रेजों के राज में ही बनाये गये थे और वे बहुत सफल सिद्ध हुए हैं ।

श्री तिरुमल राव : उत्तर के भाग (ख) के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे आन्ध्र प्रदेश और मद्रास जैसे कुछ राज्यों को छोड़ा जा सके जहाँ राज्य अधिनियम सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और जहाँ उन्होंने यह राय व्यक्त की है कि इस प्रयोजन के लिये हमारे अपने अधिनियम पर्याप्त है ?

श्री अ० कु० सेन : ऐसा विचार है कि यह एक आदर्श कानून होगा और कोई भी राज्य अपने लिये इसे अपना सकता है ।

हल्दिया बन्दरगाह

+

*649. { श्री स० च० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया बन्दरगाह के स्थान से कितने विस्थापित व्यक्तियों या परिवारों को उनके लिये विकसित की गयी भूमि पर बसाया गया है ;

(ख) बसाने की बात क्या है ;

(ग) क्या विकसित भूमि की प्रति एकड़ लागत का हिसाब लगा लिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो वह क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल सरकार से मालूम हुआ है कि अभी तक 117 परिवारों ने इस प्रयोजन के लिये विकसित भूमि पर पुनर्वास के लिये सहायता मांगी है । इनमें से 80 परिवारों ने भूमि का औपचारिक अधिकार प्राप्त कर लिया है और उनमें से चार ने निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

(ख) राज्य सरकार ने बसाने के लिये जो शर्तें रखी हैं वे मुख्यतः ये हैं :—

1. प्रत्येक परिवार को 4 कोठे दिये जायेंगे ।
2. दी हुई भूमि 30 वर्षों के प्रारम्भिक पट्टे पर दी जायेगी । इससे पुनर्वर्गीकरण का विकल्प होगा ।
3. पट्टेदार जमीन को अपने तथा अपने परिवार के तथा बारिसों के रहने के लिये मकान बनाने के प्रयोजन के लिये रख सकता है । इसके अलावा और किसी प्रयोजन के लिये उसका इस्तेमाल नहीं किया जायेगा और पट्टेदार को अधिकार मिलने की तारीख से तीन वर्षों में या उस अतिरिक्त समय में जिसकी मिदनापूर के कलेक्टर द्वारा अनुमति दी जाये, मकान का निर्माण पूरा करना होगा ।

4. इस कब्जे के लिये पट्टेदार को किराया देना होगा ।

(ग) और (घ). वास्तविक मूल्य के तय होने तक प्रत्येक परिवार से जो पुनर्वास चाहता है मकान बनाने की भूमि के . 06 एकड़ के प्लाट के तदर्थ आधार के लिये पश्चिम बंगाल की सरकार केवल 500 रुपये की राशि वसूल कर रही है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस मंत्रालय को सिफारिश की है कि डेबर आयोग की सिफारिशों के अनुसार हल्दिया में विस्थापित हुए प्रत्येक अनुसूचित जाति के परिवार को भूमि के लिये 500 रुपये तथा मकान बनाने के लिये 2,500 रुपये दिये जायेंगे और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मेरा ख्याल है बन्दरगाह के आयुक्तों को सामाजिक सुरक्षा विभाग से कोई ऐसा सन्देश नहीं मिला है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि जिन 117 परिवारों का विवरण में उल्लेख किया गया है उन्हें अपने मकानों की भूमि का प्रतिकर मिल गया है ताकि वे प्लाट खरीद सकें ?

श्री राज बहादुर : भारत सरकार अथवा बन्दरगाह आयुक्तों ने पश्चिम बंगाल सरकार के सम्बद्ध भूमि अर्जन अधिकारियों द्वारा किये गये निर्णय तथा की गई घोषणा के अनुसार दी जाने वाली भूमि अर्जन की लागत पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी है । बाकी का सारा काम पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी है ।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे परिवारों से जो पुनर्वास चाहते हैं मकान बनाने की भूमि के 0.06 एकड़ प्लाट के लिये 500 रुपये की राशि वसूल कर रही है । विवरण से यह भी पता चलता है कि ऐसा तदर्थ आधार पर किया जा रहा है जिस के मायने यह हुए कि लागत अधिक हो जायेगी । मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन द्वारा अर्जित की गई भूमि के लिये जो प्रतिकर दिया गया है उस की तुलना में यह कैसे बैठता है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक भूमि की लागत की वसूली का सम्बन्ध है उसे पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्धारित किया है । मेरा विचार है कि उन्होंने सम्बन्धित परिवारों के बहुत से व्यक्तियों के विस्थापन की बात को भी ध्यान में रखा है । मुझे खेद है कि भूमि अर्जन की दर के बारे में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री बसुमतारी : क्या मैं जान सकता हूँ कि वहां से विस्थापित हुए व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत कहां तक ठीक है कि प्रतिकर के भुगतान, भूमि के आवंटन आदि के मामले में एक दूसरे समुदाय के बीच भेदभाव किया गया है ।

श्री राज बहादुर : मेरे विचार से पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विशेष मामले में एक दूसरे समुदाय में कोई भेदभाव नहीं किया है ।

Shri Sheo Narain : May I know whether it is also mentioned in Dhebar Commission's report that a separate Ministry should be formed for development of ports and whether the same has been formed ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न इस मंत्रालय से पूछे गये प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Sugar Export

*652. Shri J. P. Jyotishi : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of those countries to which sugar was exported during 1964, the rates at which those exports were made and the quantity exported to each country respectively ; and

(b) the net foreign exchange earned thereby after deducting the expenditure incurred thereon ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

विभिन्न देशों को 1964 में निर्यात की गई चीनी की मात्रा और उन की नौतल पर्यन्त निःशुल्क अनुमानतः वसूली निम्न प्रकार थी :—

क्रम संख्या	देश	निर्यात की गई मात्रा (टनों में)	अनुमानतः नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (प्रति टन व रुपयों में)
1	मलाया	14,509	895
2	दक्षिण वियतनाम	19,346	731
3	ब्रिटेन	10,525	969
4	संयुक्त राज्य अमरीका	99,431	727
5	हांग कांग	10,469	674
6	इटली	19,153	730
7	जापान	60,866	988

(ख) अनुमानतः 19 करोड़ रुपये ।

श्री विश्वनाथ राय : विभिन्न देशों को चीनी के निर्यात को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उस की मांग बढ़ रही है और क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य की वर्तमान दरों पर हम अधिक निर्यात कर सकते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हमें कुछ राजसहायता देनी पड़ती है क्योंकि हमारी लागत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से बहुत अधिक बैठती है । उसी आधार पर हम निर्यात करते रहे हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Letters addressed in Hindi

+
 S.N.Q.6. { **Shri Bagri :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Yashpal Singh :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Kapur Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there have been some incidents in which letters bearing addresses in Hindi have been returned from Bengal and Tamilnad with instructions that the addresses thereon may be written in English ;

(b) whether such letters also include 'Ka, Kha, Ga' (क, ख, ग,) journals (published from Allahabad) that were returned to the senders resulting in great inconvenience to the subscribers ;

(c) whether any incidents of returning the letters bearing addresses in Hindi ever occurred during British regime ; and

(d) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagawati): (a) Only one complaint from the Manager, 'Ka Kha, Ga' (क, ख, ग,) Journal, Allahabad regarding the return from Calcutta of two book packets posted from Allahabad addressed in Hindi has come to notice.

(b) As already mentioned the only complaint received was from theanager, 'Ka, Kha Ga' journal.

(c) No record is available at this late date.

(d) According to the Departmental Rules, Hindi addresses should have been transcribed into English by the office of posting because the book packets were to be delivered in an area where Hindi is not commonly known. The failure of the staff at Allahabad to do so will be suitably noticed. It will also be investigated why these book packets were not got transcribed at any of the Transcription Centres in Calcutta or the RLO, Calcutta if there was difficulty in deciphering them by the delivery staff and responsibility fixed.

Shri Bagri : May I know that there are no arrangements in the Post and Telegraph offices of Madras and Tamilnad or some other non-Hindi States for translation into Hindi or vice versa ?

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narain Sinha) : Everywhere in the whole of India there are persons knowing regional languages. If somebody does not know Hindi, we have provided in our offices for translation.

Shri Bagri : May I know whether the attitude adopted by the employees was not due to the resignations submitted by the Central Ministers. If so,

whether Government are taking any step to check this type of attitude developing amongst employees ?

Shri Satya Narain Sinha : I can not say that that attitude was due to some political reasons. But whatever happened was not good and we are making enquiries. The person responsible will be punished.

Shri Kishen Pattnayak : There are few instances published in the current issue of 'Dharamyug'. I want to draw the attention of the minister and want to know that whether he feels that orders of Central Government in regard to language are not being carried out effectively by the Bureaucracy in Calcutta and Tamilnad.

Mr. Speaker : A question can not be asked in regard to feeling.

Shri Madhu Limaye : Government itself is responsible in regard to language problems. May I know whether Government is prepared to issue orders that all the letters are to be delivered, whether they have addresses in Hindi, Tamil or in any other regional languages ?

Shri Satya Narain Sinha : I have informed the House that everywhere there are persons who know regional languages and if any difficulty arises, they can get the addresses transliterated.

Shri Yashpal Singh : When these Packets were sent from Allahabad second time, may I know, how late these have been delivered.

Shri Satya Narain Sinha : Papers have not been sent to us yet. We will enquire when they will come to us from Allahabad.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the employees at Allahabad have not transliterated the address.

Shri Satya Narain Sinha : I have just now told that the employees at both the places were responsible. Postal employees at Allahabad should have transliterated the addresses.

Shri Yudhvir Singh : It is being pressed since few years that Postman and Postal clerks should know three languages, Hindi, English and the regional language. May I know any steps are being taken in this regard ?

Shri Satya Narain Sinha : People have not accepted the three language Formula yet. Therefore I cannot force my employees.

श्री कपूर सिंह : संभवतया ऐसा हिन्दी के नये विरोध के कारण हुआ हो । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसा हिन्दी के विरोध में नहीं अनितु राजनैतिक कारणों से किया जा रहा है जिससे हिन्दी को सरकारी भाषा के रूप में न योमा जाये । यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या करने का है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : माननीय सदस्य जैसा चाहें वैसा अर्थ निकाल सकते हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : Hon. Minister has just now said that those employees will be brought to book who are responsible, but whether Ministry will also issue orders in this regard, so that this type of incidents will not occur again in future ?

Shri Saty a Narain Sinha : [Definitely.

श्री वारियर : क्या यह सच है कि केवल रजिस्टर्ड पैकेट ही नहीं अपितु अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को हिन्दी में लिखे पते वाले तथा हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों को अंग्रेजी में लिखे पते वाले साधारण पत्र और मनीआर्डर भी गलत आदमी के पास पहुंचा दिए गए तथा यदि नां, तो क्या इस प्रकार की गलतियों को दूर करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

श्री सत्यनारायण सिंह : सभी प्रसिद्ध स्थानों पर व्यवस्था है। यदि पत्र ऐसे प्रदेश में जा रहा हो जहां पर लिखे पते की भाषा नहीं समझी जाती हो तो जहां से पत्र चला हो वहां के अथवा जहां पहुंचना हो वहां के डाकखाने को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में वह पता लिख देना चाहिए। दुर्भाग्य-वश इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मरमागाओ बन्दरगाह

*643. महाराज कुमार विजय आनन्द : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मरमागाओ बन्दरगाह के विकास के बारे में रेंडाल पामेर एण्ड ट्रीटन का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना कब चालू की जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मरमागाओ पत्तन के विकास के बारे में मेसर्स रेंडाल, पामेर एण्ड ट्रीटन ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है।

हुगली नदी के तल से मिट्टी कीचड़ आदि निकालना

*650. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुगली नदी से मिट्टी, कीचड़ निकालने का काम बहुत बिगड़ गया है ; और

(ख) सफाई करने तथा कलकत्ता बन्दरगाह को बड़े जहाजों के आने-जाने योग्य बनाये रखने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। कमिश्नरों ने अपने निकर्षण बेड़े को वास्तव में पर्याप्त बढ़ा लिया है और नदी का निकर्षण खूब जोरों से किया जा रहा है जिससे जहाजों के लिये अधिक से अधिक संभव डुबाव की व्यवस्था की जा सके।

(ख) हुगली नदी के नौगम्य जलमार्ग में पंद्रह बार है जिनका नौपरिवहन की पर्याप्त गहराई रखने के लिये निकर्षण करना पड़ता है इन बारों में पानी की गहराई पर नौचालन के लिये डुबाव निर्भर करता है। इन बारों के निकर्षण के लिये पत्तन 6 बड़े सकशन ड्रैजर्स का बेड़ा रखता है। उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

संख्या	सेंटर का नाम	खरीदने का वर्ष
1.	बलारी	1913
2.	गंवर	1921
3.	जलेंगी	1950
4.	भागीरथी	1950
5.	मैटेना (पुराना)	1960
6.	चुरनी	1961

ऊपर की तालिका से विदित होगा कि पत्तन को निकर्षण बेड़े का विस्तार धीरे धीरे करना पड़ा है। नदी के खराब होने की वजह से निकर्षण कार्य में निपन्तर वृद्धि के कारण यह विस्तार जरूरी था।

चीनी का निर्यात

*651. श्री दे० जी० नायक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या 1964-65 में सरकार को चीनी के निर्यात में कोई घाटा हुआ है ; और
(ख) यदि हां, तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी, हां। 2 करोड़ रुपये का अनुमान है।

नमूने के फार्म

{ श्री दी० चं शर्मा :
*653. { श्री विश्वनाथ राय :
 { श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने कृषि में सुधार करने के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में एक नमूने का फार्म खोलने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) रूस सरकार की पेशकश विचाराधीन है।

कृषि बैंक

*654. { श्री पें० वेंकटासुब्बया :
 { श्री दी० चं० शर्मा :
 { श्री यशपाल सिंह :
 { श्री कपूर सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषकों को ऋण देने के लिये एक पृथक कृषि बैंक खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की विशेषतायें क्या हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) हाल ही में कृषकों को ऋण देने के लिये एक पृथक कृषि बैंक खोलने के सम्बन्ध में मुख्य बातों पर विचार त्रिनिमय हुआ है। इन पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) अभी प्रस्ताव का व्योरा तैयार किया जा रहा है।

चम्बल घाटी में डाकू पीड़ित क्षेत्रों का आर्थिक विकास

* 655. { श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने चम्बल घाटी में डाकू-पीड़ित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई बन्दरगाह

* 656. { महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई बन्दरगाह के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस पर कुल कितना व्यय होगा?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). बम्बई पत्तन के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिये बम्बई पत्तन ट्रस्ट ने डाक विस्तार और बेलार्डपार विस्तार करने की दो योजनाएं बनायीं हैं। डाक विस्तार योजना के अन्तर्गत अलेक्जेंड्रा डाक में चार अतिरिक्त बर्थों का निर्माण, हार्बर दीवाल की तीन बर्थों की 28 फीट गहरा और फेरी मेसलों तथा हार्बर लांचों के लिये 575 फीट लम्बी एक जेटो की व्यवस्था शामिल है। इन योजनाओं पर 13.25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

दूसरी बर्थ बनाने के लिये वैलार्ड पायर का 750 फीट दक्षिण की ओर विस्तार किया जायेगा इस योजना पर अनुमानित व्यय 4.69 करोड़ रुपये है ।

जनवरी 1965 में उन दो योजनाओं से सम्बन्धित मुख्य सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिये सरकार ने एक ठेका मंजूर किया है । यह ठेका 10.70 करोड़ रुपये का है ।

आधुनिक फार्म

*657. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि में वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रोत्साहन देने के शन पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि में कुछ मशीनों का प्रयोग करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में आधुनिक कृषि उपकरणों के विस्तृत निर्माण को उच्चतम प्राथकता दी है ; और

(घ) छोटे ट्रक्टर बनाने में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). कृषि विकास योजनाओं में उन्नत खेती तथा फसल काटने की पद्धतियों में वैज्ञानिक कृषि के महत्व को आमतौर पर मान्यता दी जाती है ।

(ग) उच्च प्राथकता दी गई है ।

(घ) एक यूनिट जो हैदराबाद कृषि इंजिन कहलाता है ने पहिले ही उत्पादन शुरू कर दिया है, और गैर-सरकारी संस्थाओं के कई प्रस्तावों पर विचार हो रहा है । एक पब्लिक सैक्टर कार्यभार ग्रहण की स्थापना के लिए भी एक प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय भण्डागार निगम

*658. { श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री पें० बेंकटासुब्बया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री फ गो० सेन :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के खाद्य निग की संग्रह सम्बन्धी संभावित मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय भण्डागार निगम की संग्रह क्षमता बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा उसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) उस पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) नये भाण्डागार किस-किस स्थान पर बनाये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास राज्य में 2 लाख टन और आन्ध्र प्रदेश में 3.35 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता के गोदाम बनाने का विचार है ।

मद्रास राज्य में पहले ही गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । आन्ध्र-प्रदेश में यह कार्य शीघ्र ही शुरू करने की आशा है ।

(ग) रु० 958.25 लाख ।

(घ) गोदाम निम्न स्थानों पर होंगे :--

मद्रास	टन
मद्रास	50,000
तिरुचिरापल्ली	50,000
मनरगुड़ी	50,000
थंज्यूर	50,000
आन्ध्र प्रदेश	
तड़ेपल्लीगुडम	25,000
राजमुदरी	25,000
विजयवाड़ा	25,000
गुड़ीवड़ा	25,000
नन्दयल	50,000
निजामाबाद	20,000
रेनीगुंटा	25,000
निल्लौर	20,000
मसूलीपत्तनम	15,000
महब्बूनगर	25,000
सूर्यपट	10,000
बोधन	20,000
वदलामुड़ी	20,000
मेड़क	10,000
सिद्दीपेट	10,000
करीम नगर	10,000

राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना

1699. श्री कर्णो सिंहजी : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि मांगी गई है और कितनी सहायता दी गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

1700. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 से अब तक केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए उड़ीसा राज्य के गैर-सरकारी संगठनों को कुल कितनी धन राशि दी ; और

(ख) उन संगठनों के नाम क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : ठक्कर बापा आश्रम, डाकखाना नीमरवांडी, जिला गंजम, उड़ीसा को निम्नलिखित सहाय्य अनुदान दिय गए हैं:

	रुपए
1961-62	शून्य
1962-63	शून्य
1963-64	12,000
1964-65	10,300
कुल	22,300

अखिल भारत स्तर के कुछ अन्य संगठनों, जैसे एजेंट्स आफ इण्डिया सोसाइटी भारतीय दलित वर्ग लोग और अखिलभारत पिछड़े वर्ग फेडरेशन, को भी उड़ीसा समेत अनेक राज्यों में कल्याण योजनाओं के लिए अनुदान दिए गए हैं ।

Rest House at Elephanta Cave

1701. **Shri Baswant** : Will the Minister of Transport be pleased to state :

(a) whether any new rest house has been constructed at Elephanta Caves near Bombay.

(b) if so, the expenditure incurred thereon ;

(c) whether it is a fact that for want of water supply arrangements, the rest house has not so far been opened to Indian and foreign tourists ; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) A Restaurant-cum-retiring room at the Elephanta caves near Bombay, has been constructed as one of the schemes included in the Second Five Year Plan for Tourism.

(b) Rs. 4.21 lakhs.

(c) and (d). In November 1964, the above establishment was handed over to the Government of Maharashtra for its day-to-day management. The State Government have since made arrangements for the water supply, and the Restaurant portion has already been put into commission.

Steps are also being taken by the State Government to improve the water supply position on a permanent basis.

It is hoped that the State Government will shortly throw open the Retiring room for the use of the tourists visiting the caves.

कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर के लिए अनुदान

1702. श्री राम हरख यादव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने पन्त नगर में कृषि विश्वविद्यालय के लिए विशेष अनुदान मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह अनुदान किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार 1959 से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर को निम्न प्रकार सहायता देती रही है :—

1—परामर्श तथा शिक्षण कार्यों के लिए अमरीकी तकनीशनों की सेवायें प्रदान करना ;

2—संयुक्त राज्य अमरीका में विश्वविद्यालय से स्टाफ को उच्च प्रशिक्षण देना ;

3—प्रयोगशाला के लिए उपकरण तथा पुस्तकालय के लिए पुस्तकें देना ;

इस समय तक निम्नलिखित सहायता दी गई ।

(क) तकनीशनों की सेवायें प्रदान करना :

17 तकनीशनों (जिनमें 5 अल्पकालीन परामर्शदाता भी शामिल हैं) की सेवायें प्रदान की गई हैं जिनमें से 11 (5 परामर्शदाताओं सहित) को उनका कार्य समाप्त होने पर वापिस भेजा दिया गया है इस प्रकार इस समय 6 तकनीशन कार्य कर रहे हैं । दो स्वीकृत पदों के लिए नाम-जदगियां होने की प्रतीक्षा है ।

(ख) स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण :

इस समय तक स्टाफ के 18 सदस्यों की प्रति नियुक्ति की गई है जिनमें से 9 सदस्य अपना प्रशिक्षण पूरा करके वापिस आ चुके हैं। स्टाफ के 8 सदस्य, जिनकी नामजदगी के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, प्रस्थान के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में हैं।

(ग) प्रयोगशाला सामग्री तथा पुस्तकों का सम्भरण:

इस कार्य के लिए 5,00,000 डालर राशि की व्यवस्था की गई है। उपकरण तथा पुस्तक उपलब्धि विषयक अमरीकी एजेन्सी को 4,75,000 डालर राशि के लिए इन्डेंट भेज दिये गये हैं और 2,63,204 डालर के मूल्य के उपकरणों तथा पुस्तकों के लिए पोत परिवहन प्रलेख प्राप्त हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त अमरीकी सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत सिचित रुपया निधि से 2,16,00,000 का अनुदान दिया है ताकि विश्वविद्यालय, तराई स्टेट फार्म तथा विश्वविद्यालय प्रयोगात्मक केन्द्र में निर्माण तथा विकास पर होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके इसमें से जो खर्च हुआ है उसके आधार पर अब तक अमरीकी सरकार ने वास्तव में 1,60,30,405.31 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति कर भी दी है।

Elections in Kerala

1703 { Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Mnister of Law be pleased to state :

(a) whether any complaints about some irregularities and clashes during the General Elactions recently held in Kerala have been received ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) whether Government have got some indication that some foreign money was spent there during the elections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao);
(a) and (b) Only two complaints from the contesting candidates during the recent general elections held in Kerala were received by the Election Commission. Both the complaints were about the alleged interference of the local police in a partial and prejudicial manner.

(c) No, Sir ; neither the Government nor the Election Commission has got any such indication or information.

मलकानी समिति की सिफारिशें

1704. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि भंगियों की दशा के सम्बन्ध में मलकानी समिति की मुख्य सिफारिशों/सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : स्कैवैल्जिग कन्डीशन्स एन्क्वायरी कमेटी (सफाई दशा जांच समिति) के प्रतिवेदन की प्रतियां सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मन्त्रालयों को विचारार्थ तथा क्रियान्विति के लिए भेज दिए गए हैं। समिति द्वारा की गयी अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकारें अपने अधीक्षण में स्थानीय संस्थाओं द्वारा लागू की जायेंगी। ये सिफारिशें लगभग 223 हैं। इनमें से अधिकांश पर एक साथ कार्यवाही नहीं की जा सकती। स्थानीय संस्थाओं को प्रवास्थाभाजित कार्यक्रम बनाना है तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन सिफारिशों को लागू करना है। जबकि विभिन्न राज्यों की स्थानीय संस्थाओं ने विभिन्न सिफारिशों को लागू करना आरम्भ कर दिया है, आशा यह है कि धीरे धीरे इन सिफारिशों को अन्य स्थानों पर भी लागू किया जायेगा। कई राज्यों में गन्दगी को सिर पर ले जाने की प्रथा बन्द कर दी गयी है। इस प्रणाली के बहुत समय से चले आने के कारण पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के विभाग तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के गैर सरकारी मेहतरों ने 'ब्हलिवरों' से गन्दगी ले जाने से इंकार कर दिया क्योंकि वह समझते हैं कि इससे सभी मेहतर तथा उनका अपना काम नगरपालिका के अधीन आ जायेगा।

मलकानी समिति की सिफारिश पर 'व्हील बरो' देने की योजना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने में उदारता दिखाई गयी है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय तथा रेलवे मन्त्रालय के नियन्त्रण में आने वाले क्षेत्रों में सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। प्रो० मलकानी के सभापतित्व में एक सलाहकार समिति मई 1962 में दो वर्षों के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी तथा उसको यह काम सौंपा गया था कि मलकानी समिति की सिफारिशों को लागू करने तथा स्थानीय संस्थाओं तथा मेहतरों को उन्हें स्वीकार करने के लिए व्यवस्था करे।

Delhi Milk Scheme

1705. { **Shri Yashpal Singh :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Hukam Chand Kachhavaia :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had to suffer a loss of Rs. eight lakhs in 1963-64 on account of mismanagement in the Delhi Milk Scheme ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to make up this loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) ; (a) and (b) The Delhi Milk Scheme suffered a loss of Rs. 23.09 lakhs in 1963-64. This was not due to mismanagement but due to increase in the procurement price of milk and in the dearness and other allowances admissible to the D.M.S. employees, and the general increase in prices of consumable store. To reduce the losses, the Scheme has already raised the prices of ghee, butter and ice cream ; a revision of the price structure of milk is also under consideration.

दिल्ली से चोरी छिपे अनाज ले जाना

1706. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने संघ सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि पंजाब राज्य से दिल्ली भेजा जाने वाला अनाज, व्यापारी दिल्ली से चोरी छिपे बाहर ले जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने भारत सरकार के ध्यान में यह बात लायी थी कि दिल्ली से गेहूं चोरी छिपे सीमावर्ती राज्यों में ले जाया जा रहा था। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली से खाद्यान्नों के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए विस्तृत उपाय जिनमें सीमा पर चौकियों को मजबूत करना शामिल है, किए हैं।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के रेडियो अधिकारी

1707. श्री हेडा : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने अपने रेडियो अधिकारियों के वेतन-क्रम बढ़ाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या यह वृद्धि अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के अनुरूप है ; और

(ग) इस वृद्धि के कारण कारपोरेशन पर कितना वास्तविक भार पड़ेगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1963-64 के दौरान अनुमानित व्यय 80,000 रुपया है और 1964-65 के दौरान 2,60,000 रुपये।

एयर इंडिया बोइंग में दरार

1708. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिडनी जाने वाला एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान 12 जनवरी, 1965 को पर्थ से रवाना होने के एक घंटे बाद वापस लौट आया था क्योंकि उस में कोई दरार पायी गयी थी

(ख) यदि हां, तो विमान को क्या तथा कितनी क्षति हुई ; और

(ग) क्या निगम के अन्य बोइंग विमानों में भी इसी प्रकार की दरार पायी गयी है और यदि हां, तो कितने विमानों में ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सिडनी जाने वाला एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान 11 जनवरी, 1965 को पर्थ से रवाना होने के 1 घण्टे और 55 मिनट बाद वापस लौट आया था क्योंकि सह-विमान चालक के बाहरी विण्डशील्ड पैनल में एक दरार पायी गयी थी।

(ख) सह-विमान चालक के नंबर 1 विण्ड-शील्ड पैनल के केवल बाहरी पैनल में दरार आयी थी ।

(ग) एयर इंडिया द्वारा 1960 में बोइंग परिचालनों के शुरू किये जाने से अब तक कारपोरेशन के बोइंग विमानों के विण्ड-शील्ड पैनलों में दरार पड़ने के 10 मामले हो चुके हैं ।

बिहार में चावल और गेहूं के भाव

1709. { श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बिहार सरकार ने चावल और गेहूं के भाव कम कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक कमी की गई है ; और

(ग) क्या कमी करने से पहले केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त की गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने मोटे चावल के निकासी भाव रु० 2.56 प्रति क्विंटल और गेहूं के निकासी भाव रु० 3.50 प्रति क्विंटल कम कर दिये हैं । भारत सरकार ने भाव कम करने की सहमति दे दी है ।

नंगल में हवाई अड्डा

1710. श्री दलजीत सिंह: क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नंगल में एक हवाई अड्डा बनाने के बारे में कोई निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) नांगल में एक विमान क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

1711. { श्री हेडा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को किन मार्गों से अब भी घाटा उठाना पड़ रहा है ;

(ख) किन मार्गों से अच्छा लाभ हो रहा है ; और

(ग) सेवाओं के विस्तार के लिये आगे क्या कार्यक्रम है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) 1964-65 की पहली छमाही के दौरान निम्न सेवाएं हानि पर चलती थीं :—

- (i) कराची, लाहौर, ढाका, चिटगांव, रंगून, और काठमांडू को सेवाएं ।
(ii) कलकत्ता/अगरतला को छोड़ कर बाकी सभी डकोटा सवारी और भारवाही सेवाएं ।
(iii) दिल्ली-मद्रास कारवेल सेवा ।
(iv) दिल्ली-आगरा-लखनऊ-बनारस-कलकत्ता और मद्रास-कोलम्बो वाइकाउण्ट सेवाएं ।
(v) रात्रिकालीन वायुडॉक सेवाएं ।
(vi) फ्रेंडशिपसेवाएं :—

- (क) बम्बई-गोवा ।
(ख) मद्रास-त्रिची-मदुराई-त्रिवेन्द्रम ।
(ग) बम्बई-अहमदाबाद-उदयपुर-जयपुर-दिल्ली ।
(घ) कलकत्ता-बागडोगरा ।
(च) मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर ।
(छ) दिल्ली-कानपुर-बनारस-पटना-कलकत्ता ।
(ज) दिल्ली-लखनऊ-इलाहाबाद ।

(ख). वे मार्ग, जिन पर लाभ होता है, निम्नलिखित हैं :—

1. बम्बई-कलकत्ता
2. बम्बई-मद्रास
3. बम्बई-दिल्ली
4. कलकत्ता-दिल्ली
5. कलकत्ता-मद्रास
6. कलकत्ता-बागडोगरा
7. मद्रास-बंगलौर
8. कलकत्ता-गोहाटी
9. बम्बई-बंगलौर
10. बम्बई-हैदराबाद
11. हैदराबाद-मद्रास
12. हैदराबाद-बंगलौर
13. दिल्ली-हैदराबाद
14. दिल्ली-श्रीनगर
15. दिल्ली-काबुल

(ग) सेवाओं के विस्तार का आगे का कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

कारवेल/बोइंग

चौथे कारवेल को 1-4-1965 से चलाना आरम्भ किया जा रहा है। इससे कारवेल सेवाएं निम्न प्रकार परिचालित की जायेंगी :—

कलकत्ता-दिल्ली	प्रतिदिन दो सेवाएं।
बम्बई-दिल्ली	प्रतिदिन तीन सेवा।
दिल्ली-मद्रास	प्रतिदिन एक सेवा।
बम्बई-बंगलौर-मद्रास	प्रतिदिन एक सेवा।

बम्बई-दिल्ली मार्ग की बोइंग सेवाएं बन्द कर दी जायेंगी और इसके बदले वे बम्बई-कलकत्ता मार्ग पर चलायी जायेंगी।

वाइकाउण्ट

उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, कारपोरेशन कलकत्ता/गोहाटी/चबुआ मार्ग पर एक वाइकाउण्ट सेवा, कलकत्ता और गोहाटी के बीच दोपहर के बाद की एक दूसरी शटल, कलकत्ता/बागडोगरा क्षेत्र पर एक सुबह की शटल और बम्बई एवं हैदराबाद के बीच दोपहर बाद देर की सेवा चलाने लगेगा। इनके अतिरिक्त, दिल्ली और श्रीनगर के बीच एक दूसरी आवृत्ति की सेवा (मौसमी) भी चलाई जायेगी।

फ्रेंडशिप

फ्रेंडशिप विमानों की सेवाओं के नमूने को फिर से नियोजित किया गया है ताकि कारपोरेशन इस प्रकार के विमानों से कलकत्ता अग्रतला/सिलचर, कलकत्ता/तिजपुरा/जोरहाट और दिल्ली/कानपुर/बनारस/गोरखपुर/लखनऊ मार्गों पर सेवाएं चला सके। पहले दो मार्गों पर दैनिक आवृत्ति की सेवा चलायी जायेगी जब कि आखिरी मार्ग पर सप्ताह में 4 दिन की सेवा चलायी जायेगी।

डकोटा

हैदराबाद/बेजवाड़ा/विजग डकोटा सेवा सप्ताह में दो दिन की वर्तमान सेवा के बजाय सप्ताह में 3 दिन चला करेगी।

बम्बई/औरंगाबाद/नागपुर सेवा जो कि इस समय सप्ताह में 4 दिन परिचालित की जाती है, पहली अप्रैल, 1965 से रोजाना परिचालित की जायेगी।

पंचायत चुनाव

1712. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायत चुनावों में मतदान को अनिवार्य करने की संभावना पर विचार किया है ;

(ख) जनता वर्तमान प्रणाली में ऐसे सुधार का कहां तक समर्थन करती है ; और

(ग) नवीनतम पंचायत चुनावों में मतदान की औसत प्रतिशतता क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस बारे में जनमत का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) 1963 से अब तक हुए पंचायत चुनावों में मतदान की औसत प्रतिशतता का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4092/65]]

अनाज की हानि

1713. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में अनाज को लाने ले जाने में तथा भाण्डागारों में अनाज की कितनी हानि हुई ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) वर्ष 1963-64 में लाने ले जाने और भाण्डागारों में खाद्यान्नों की हानि की मात्रा और उसका मूल्य निम्न प्रकार था :—

(मात्रा हजार मीट्रिक टन में और लाख रु० में)

लाने ले जाने पर हुई हानि की मात्रा	मूल्य
31.4	138.2
भाण्डागार में हुई हानि की मात्रा	
12.3	58.8

(ख) जब खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना अनिवार्य हो जाता है तब खाद्यान्नों की कुछ हानि अनाज के बिखरने आदि के कारण होती है और इसे नहीं रोका जा सकता खाद्यान्नों के लाने ले जाने में कुछ हानि भेजने वाले स्थान और गंतव्य स्थान पर विभिन्न प्रकार के तोल के तरीके होने के कारण होती है । लाने ले जाने में और हानि खाद्यान्नों के मार्ग में सूख जाने और छोटी मोटी चोरी के कारण होती है ।

भाण्डागारों में खाद्यान्नों की हानि अनाज के सूख जाने और कीड़ों, चूहों और पक्षियों द्वारा खराब करने से भी होती है ।

(ग) सड़क परिवहन से होने वाली हानि के अनेक मामलों की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदारों पर डाली गई है और इस हानि की वसूली उनके बिलों से की गई है। रेल द्वारा संचलन से होने वाली कमी के दावे के जो मामले उचित हों, रेलवे से मांगे जाते हैं। कुछेक मामलों में जिन विभागीय अधिकारियों पर शक होता है, में सतर्कता केस चलाए गए हैं। तथापि, जिम्मेदारी निर्धारण करने के लिए अभी कुछ मामलों की छानबीन हो रही है ।

केरल में चावल का उत्पादन

1714. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के किसी दल ने केरल में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या सिफारिशों की हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) दल ने सिफारिश की है कि केरल के कुछ चावल उगाने वाले निचले क्षेत्रों को एक परियोजना के लिये चुना जाना चाहिए । इस परियोजना के अन्तर्गत पांच वर्षों में हवाई जहाज द्वारा फोटोग्राफी, विस्तृत तथा अर्द्ध-विस्तृत भूमि सर्वेक्षण, नई धान किस्मों के साथ अनुसन्धान तथा परीक्षण, परिधिरेखा-मानचित्र, भू-जल साधनों का अध्ययन, उद्धारित भूमि सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों की रूपरेखा बनाना और सुधार कार्य के प्रभावों के सम्भाव्य अध्ययन सम्बन्धी कार्य किये जाने चाहियें । लगभग 190,000 एकड़ क्षेत्र को परियोजना के अन्तर्गत लाने की सिफारिश की गई है ।

(ग) जी हां । संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि को भेजने हेतु एक प्रारूप योजना तैयार करने के लिए केरल सरकार से प्रार्थना की गई है ।

चेकोस्लोवाकिया का "जेड-326 ट्रेनर मास्टर" विमान

1715. { श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राधेलाल व्यास :
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेकोस्लोवाकिया का ट्रेनर विमान 'जेड-326 ट्रेनर मास्टर' खरीदने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का व्यौरा क्या और सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

असेनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है ।

वस्तु-समिति

1716. { महाराजकुमार विजय आनन्द :
 श्री इन्द्रजीत गुप्त :
 श्री फ० गो० सेन :
 श्री राम सेवक :
 श्री ओंकार लाल बेरवा :
 श्री दीनेन भट्टाचार्य :
 श्री स० मो० बनर्जी :
 श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 17 नवम्बर, 1964 के तारकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विभिन्न वस्तु-समितियों के पुनर्गठन की दिशा में क्या प्रगति हुई है;
 (ख) पुनर्गठन योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और
 (ग) उसका अंतिम परिणाम क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). केन्द्रीय वस्तु-समितियों के भावी ढांचे तथा कार्यों के बारे में अभी विचार हो रहा है ।

परमाणु बम के भूमिगत परीक्षणों से उत्पन्न झटकों का अनुभव किया जाना

1717. श्रीमती सावित्री निगम : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय प्रयोगशालाएं हाल में किए गये परमाणु बम के भूमिगत परीक्षणों से उत्पन्न झटकों को रिकार्ड कर सकी थीं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : हमारे भूकम्प-लेखियों (सीसमोग्राफस्) द्वारा हाल में इस प्रकार के कोई झटके रिकार्ड नहीं किये गये हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

- 1718 { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
 श्री दाजी :
 श्री दीनेन भट्टाचार्य :
 डा० रानेन सेन :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदित है कि पश्चिम बंगाल में दवा बेचने वाली पंजीबद्ध दूकानें कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमाकृत कर्मचारियों को नियत औषधियां देने से इस कारण इन्कार करती हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने उनके बिलों का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) ऐसी दर्व्यवस्था के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी समिति

1719. श्री विभूति मिश्र : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान अनेक समितियों के स्थान पर केवल एक प्रकार की सहकारी समिति स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रस्ताव के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के क्या विचार हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली परिवहन

1720 { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री लखमू भवानी

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन बसों में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिये बस ट्रेलर चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ;

(ग) इससे दिल्ली परिवहन को राजधानी में बसों द्वारा यात्रा करने वाली जनता की आवश्यकता को पूरा करने में कितनी सहायता मिलेगी ; और

(घ) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हां । परीक्षण के रूप में एक ट्रेलर बस यूनिट चालू की गई है ।

(ग) इस प्रकार की बसें अत्यधिक यातायात के मौकों पर बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी क्योंकि उनकी वहन क्षमता बहुत अधिक है ।

(घ) प्रत्येक बस को ट्रेलर बस, जो पहले ही है, में बदलने के लिए 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च होती है ।

सहकारी खेती

1721. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीबा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 1 दिसम्बर, 1964 के तारार्कित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त सहकारी खेती में एक मध्यवर्ती प्रक्रम आरम्भ करने के विषय पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बीच गाडगील समिति का जो सहकारी खेती समितियों की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये नियुक्त की गई थी, प्रतिवेदन मिल चुका है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त नौवहन सेवा

1722 { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के बीच एक संयुक्त नौवहन सेवा चलाने के बारे में हाल में नई दिल्ली में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो अगर इस मामले में कोई समझौता हुआ हो तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले में अभी अन्तिम समझौता नहीं हुआ है ।

Bridge Over Ganga at Patna

1723. { Shri Bibhuti Mishra :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri D.N. Tiwary :
Shri P.R. Chakraverti : -

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government had approached the

Central Government for financial assistance for constructing a bridge over the Ganga at Patna; and

(b) if so, the estimated cost of the project, and the decision taken by Government in the matter ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) : The proposed bridge over the Ganga at Patna would fall on a State road. The Government of Bihar are, therefore, primarily concerned with its construction. The State Government have sent so far no formal proposal for Central financial assistance for the construction of the aforesaid bridge. They are however getting river model test experiments carried out at (1) Irrigation Research Station, Roorkee and (2) Hydraulic Research Station, Poona for selection of suitable site.

ब्रह्मपुत्र में नौ परिवहन

1724. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने राज्य में दो अन्तर्देशीय नदी-बन्दरगाहों का निर्माण करने और ब्रह्मपुत्र में नौपरिवहन की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार से मंजूरी तथा सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). ब्रह्मपुत्र नदी के गौहाटी और सादिलपूर घाट पर पत्तन सुविधाओं के सुधार के लिए आसाम सरकार ने प्रस्ताव भेजे हैं । राज्य सरकार के साथ सलाह करके इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा में नलकूप

1725. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उड़ीसा में (जिलावार) कितने परीक्षात्मक नलकूप खोदे गए ; और
(ख) उनमें से कितने सफल सिद्ध हुए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उड़ीसा में भूमिगत जल का समन्वेषण करते समय 1964-65 की अवधि में पुरी जिले में 6 परीक्षात्मक नलकूप खोदे गए थे ।

(ख) कोई नहीं ।

उड़ीसा में चावल का उत्पादन

1726. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1964-65 में उड़ीसा में कितना चावल पैदा हुआ ;
 (ख) इसी अवधि में दूसरे राज्यों को कितना चावल भेजा गया; और
 (ग) उसका मूल्य कितना था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) चावल की ग्रीष्म ऋतु की फसल की अभी कटाई होनी है और 1964-65 में उड़ीसा में चावल की उपज का ठीक-ठीक अनुमान इस समय नहीं दिया जा सकता है ।

(ख) और (ग). 1-12-64 से 8-3-65 तक उड़ीसा से अन्य राज्यों को कुल 60, 370 मीट्रिक टन चावल की मात्रा भेजी गयी थी । इस चावल का अनुमानतः मूल्य 3.65 करोड़ रुपये है ।

कोनार्क में हवाई अड्डा

1727. { श्री रामचन्द्र उलाका :
 श्री धुलेश्वर मीना :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उड़ीसा में कोनार्क में हवाई अड्डा बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;
 और
 (ख) उस पर अब तक कुल कितना खर्च हो चुका है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). कानार्क में विमान क्षेत्र के लिये स्थान का निरीक्षण कर लिया गया है । भूमि की स्थिति विषयक तकनीकी समस्याओं की जांच की जा रही है । अभी तक कुछ व्यय नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में संयुक्त खेती सम्बन्धी अग्रिम योजनाएं

1728. { श्री रामचन्द्र उलाका :
 श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या 1965-66 में उड़ीसा में संयुक्त खेती सम्बन्धी अग्रिम योजनाएं बनाने का विचार है;
 (ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि रखी गई है;
 और
 (ग) उड़ीसा में इस समय ऐसी कितनी अग्रिम परियोजनाएं चालू हैं और तीसरी योजनावधि में अब तक इन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) 1965-66 में अग्रगामी परियोजना क्षेत्रों में गठित की जाने वाली सहाकारी खेती समितियों के लिए 4.73 लाख रुपये की धनराशि रखी गई है।

(ग) इस समय उड़ीसा में 5 अग्रगामी परियोजनाएँ हैं। उन में 63 सहाकारी खेती समितियाँ गठित की गई हैं। 1963-64 के अन्त तक इन समितियों को 5.78 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी।

उड़ीसा को वित्तीय सहायता

1729. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964-65 में खेती से पैदावार बढ़ाने के लिये उड़ीसा सरकार को कोई अल्पकालीन ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख) जी हां। उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों तथा उन्नत बीजों को जिनमें संकर मक्का बीज भी शामिल है, किसानों में उधार बांटने के लिए 61.20 लाख रुपये के एक अल्पकालीन ऋण की उड़ीसा सरकार को स्वीकृति दी गई है जो निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	कार्य	राशि (रुपयों में)
		लाख
1.	उर्वरकों का वितरण	30.00
2.	कीट-नाशक औषधियों का वितरण	6.00
3.	उन्नत बीजों का वितरण जिसमें संकर मक्का बीज भी शामिल हैं।	25.20
	कुल	61.20

दिल्ली में मिठाइयों के भाव

1730. श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हलवाई मिठाइयाँ बहुत अधिक भावों पर बेच रहे हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं विशेष कर जब कि सरकार उन्हें निश्चित भाव पर चीनी का कोटा दे रही है; और

(ग) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) यह सच है कि दिल्ली में मिठाई के भाव काफी ऊंचे हैं । तथापि मिठाई के भाव केवल शर्करा के भाव पर ही नहीं बल्कि कुशल कारीगर, जगह का किराया तथा दूध, खोया, घी, वनास्पति, मैदा, ईंधन आदि अन्य वस्तुओं के भावों पर भी निर्भर करते हैं ।

(ग) अन्य वस्तुओं के भावों पर नियंत्रण न होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना कठिन है ।

एवरो 748

1731. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन किन मार्गों पर एवरो 748 विमान चलाये जायेंगे ; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप प्रशुल्क में कोई परिवर्तन हाने की सम्भावना है और यदि हां, तो किस हद तक ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) : इण्डियन एयरलाइन्स को, उनके मार्गों पर चलने के लिए ठीक साबित होने और उनकी आवश्यकताओं के लिए इसकी उपयुक्तता का विचार करने के लिए अभी अभी एक एवरो विमान उपलब्ध किया गया है । उन्हें डकोटा मार्गों पर चलाने का विचार है । इस समय यह कहना कठिन है कि चालनों की लागत क्या होगी और किरायों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ।

केन्द्रीय आनाज गोदाम, ग्वालियर

1732. श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ग्वालियर से केन्द्रीय आनाज गोदाम हटाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उसे कहां ले जाया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : ग्वालियर में केन्द्रीय संग्रहण डिपो को बन्द करने का विचार था, किन्तु मध्य प्रदेश सरकार की प्रार्थना को मान कर यह निश्चय किया गया कि इस केन्द्रीय डिपो को फिलहाल चलने दिया जाए ।

Bombay-Poona And Bombay-Nasik Roads

1733. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether a proposal for doubling Bombay-Poona and Bombay-Nasik roads is under consideration of the Government;

(b) whether the World Bank representatives have given any suggestions in this regard ;

(c) whether these roads are damaged during rainy season; and

(d) if so, the action being taken by Government for their proper maintenance ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) These Sections of National Highways already have double-lane (20 feet) carriage ways. The need for further widening is under investigation.

(b) World Bank representatives suggested that a detailed survey should be carried out, including cost-benefit analysis.

(c) Yes.

(d) Damages are made good as part of maintenance measures. Detailed field surveys, as preliminary to projecting and improvement programme, are under consideration.

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का वन विभाग

1734. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार प्रशासन के वन विभाग में इस समय कुल कितने श्रमिक काम पर लगे हुए हैं ;

(ख) कितने व्यक्ति ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या अन्दमान प्रशासन ने वन विभाग में कोई छंटनी की थी ; और

(घ) कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई थी और इसके क्या कारण थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 3934 ।

(ख) 982 ।

(ग) और (घ) जी नहीं, फिर भी दो वर्ष के ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके पर रखे गये 9 मजदूरों की सेवायें समाप्त की गई थीं और ऐसा भी इसलिए किया गया क्योंकि आगे की अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेका फिर से शुरू करने से उन्होंने इन्कार कर दिया था ।

बेगमपेट में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का इंजीनियरिंग बेस

1735. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेगमपेट (हैदराबाद) में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के इंजीनियरिंग बेस बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो बेगमपेट इंजीनियरिंग बैस के कर्मचारियों को किस प्रकार से खपाया जायेगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड

1736. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड की सत्रहवीं बैठक हाल में पंजिम में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विशिष्ट विषयों पर चर्चा हुई तथा बोर्ड ने क्या निर्णय किये ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) । (क) जी हां ।

(ख) बैठक का अभी अधिकारिक कार्यवृत्त प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी बैठक में जो चर्चा हुई तथा बोर्ड ने जो सिफारिशें की हैं उनका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—4093/65]

बपुर नदी को गहरा करना

1737. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोटेकाट्ट :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बेपुर नदी को गहरा करने के मामले में, जैसी कि छोटे पत्तन विकास समिति ने सिफारिश की है, क्या प्रगति हुई है ;

(ख) 1965-66 में इसके लिये कितनी धन राशि नियत की गई है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) : केरल सरकार ने एक निकर्षक एकांश के निर्माण की आज्ञा दी है । इसमें एक कटर सकशन ड्रेजर, एक दो टन का ग्रेब ड्रेजर, तीन डंब हापर वारजे और एक टग होगा जिनकी लागत 27.10 लाख रुपये होगी । यह केरल में अन्य सब दूसरे छोटे पत्तनों के आन्तरिक निकर्षण के लिये और बेपुर की नाव नहर और बेपुर नदी के निकर्षण में काम में लाये जायेंगे । निकर्षण एकांश 1965-66 के अन्त तक मिल जाने की आशा है । निकर्षण एकांश के तैयार हो जाने के बाद राज्य सरकार निकर्षक कार्य प्रारंभ कर देगी । यह कहना संभव नहीं है कि काम कब तक पूरा हो जायेगा ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

1739. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इसी कारण एक गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो गया है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने उर्वरकों तथा पौधा संरक्षण रसायन को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध का आश्वासन दिये बिना बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं बनाने के सिद्धांत पर ही आपत्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् तथा सरकार के बीच चल रहे मत-भेद का ठोक स्वरूप क्या है ; और

(ग) इसे किस प्रकार दूर किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने केवल यह सुझाव दिया है कि सिंचाई के विकास के साथ ही साथ उर्वरकों तथा वनस्पति रक्षा के उपकरणों आदि के बारे में भी व्यवस्था की जाए ताकि नई सिंचाई सुविधाओं से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क उपकर निधि

1740. श्री र० ना० रेड्डी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 में केन्द्रीय सड़क उपकर निधि से आन्ध्रप्रदेश के लिये कितनी रकम दी गई ; और

(ख) कितन-कितन कार्यों के लिये इस धन राशि का उपयोग किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 15.00 लाख रुपये। संभवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य केन्द्रीय सड़क निधि से है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कोयम्बटूर-बंगलौर-मद्रास उड़ान

1741. श्री मधुलिमये : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अपनी ग्रीष्म-समय-सारिणी में कोयम्बटूर से बंगलौर तथा मद्रास उड़ानों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां। वर्तमान समय-सारिणी में कोयम्बटूर, बंगलौर और मद्रास के बीच सुबह और शाम चलने वाली दो फ्रेण्डशिप

उड़ानें हैं। पहली अप्रैल, 1965 से लागू होने वाली समय-सारिणी में एक उड़ान बन्द की जा रही है, अर्थात् कोयम्बटूर, बंगलौर और मद्रास के बीच दोपहर बाद चलने वाली केवल एक फ्रेडशिप उड़ान होगी। कारपोरेशन, फिर भी, मद्रास-बंगलौर-बम्बई की कार्वेल सेवा के साथ सम्बन्ध जोड़ने की व्यवस्था के लिए बंगलौर और कोयम्बटूर के बीच एक सेवा की सम्भावना पर विचार कर रहा है।

(ख) : उक्त परिवर्तन की आवश्यकता निम्न कारणों के वजह से पड़ी है :—

- (i) मद्रास में दर्घटना के परिणाम-स्वरूप एक एफ-27 विमान के बेकार हो जाने के वजह से विमान की कमी ;
- (ii) पहली अप्रैल, 1965 से उड़ान और ड्यूटी के समय की परिसीमाओं के लागू हो जाने के कारण विमान कमियों (कू) की कमी।

अनुसूचित आदिम जातियां

1742. { श्री म० प० स्वामी :
श्री काशीनाथ दुरै :
श्री मलाइछामी :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित आदिम जातियों के शैक्षणिक, रोजगार तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उसके अन्तर्गत क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। पूरे देश के लिए एक योजना बनाने के बजाये अनुसूचित आदिम जातियों का शिक्षा का स्तर सुधारने तथा आर्थिक सुधार करने के लिए कई योजनाएँ चालू हैं। ऐसी योजनाओं की सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4094/65]

(ख) तीसरी योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी केन्द्रीय कार्यक्रम में इन योजनाओं को शामिल किया गया है। तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में संभवतया 276.50 लाख रुपये कम होने हैं जब कि इसके लिए योजना में 419 लाख रुपये की व्यवस्था है।

ऊन अनुसन्धान केन्द्र

1743. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुलू घाटी में ऊन अनुसन्धान केन्द्र खोलने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसन्धान संस्था के कुलू घाटी के घेरसा में स्थित एक उप-केन्द्र ने काम शुरू कर दिया है।

इस उप-केन्द्र के लिए अभी तक पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध की गई 30 एकड़ भूमि को ले लिया गया है। इस भूमि को साफ करके इसका विकास किया गया है। आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। रिहायशी और दफ्तर तथा प्रयोगशाला दोनों के भवनों के निर्माण के लिए हाल ही में मंजूरी दे दी गई है और शीघ्र ही कार्य के शुरु होने की आशा है। चारे की प्रयोगात्मक रूप से बुआई को जा रही है तथा गत वर्ष न्यूजिलैंड से 'रोमनी मार्श' तथा 'साउथ डाउन' नामक भेड़ों की जो नस्लें प्राप्त हुई थीं उनकी जलवायु के लिए अभ्यस्त करने तथा प्रवर्धन के लिए रखा जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीन के प्रधान मंत्री को ले जाने वाले विमान की कलकत्ता के ऊपर से उड़ाने करने का समाचार

Shri Hukam Chand Kachhawaiya (Dewa) : I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent Public importance and request that he may make a statement thereon:

“Reported flight of a Plane carrying the Chinese Premier, Mr. Chou-En-Lai, over Calcutta on the 23rd March, 1965”.

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : चीन के प्रधान मंत्री, चाऊ-एन-लाई तथा उनके साथियों ने रूमानिया जाते हुए ढाका से कराची को पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स में 23 मार्च, 1965 को उड़ान की। अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवा परिवहन समझौते के अन्तर्गत, यदि ऐसी उड़ान करनी हो तो केवल पूर्व सूचना देना ही काफ़ी है। यही सुविधा भारत को उपलब्ध है यदि हमें ऐसी उड़ान करनी हो।

22 तारीख की सुबह इस बात की सूचना पी० आई० ए० कराची ने भारत के डी० जी० सी० ए० को दी और कहा कि वे 23 तारीख की सुबह ढाका से कराची यह उड़ान करेंगे। ऐसी ही सूचना भारत स्थित चीनी दूतावास के प्रथम सचिव ने हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय को दी और कहा कि चीन के प्रधान मंत्री तथा उनका दल इसमें उड़ान करेगा।

जब से चीन-पाकिस्तान का विमान उड़ान सम्बन्धी समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत चीन तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीधी विमान उड़ान सेवा स्थापित हुई है, चीनी यात्रियों के पाकिस्तानी वायुयानों में भारत के ऊपर से होकर उड़ानों में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के ये वायुयान भारत-पाकिस्तान विमान उड़ान समझौते तथा अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवा परिवहन समझौते के अन्तर्गत उड़ते हैं। ऐसी उड़ान करने के लिये केवल पूर्व सूचना देना आवश्यक है और किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

वैसे चीन की सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि जब कभी कोई चीनी दल भारत के ऊपर से अनिर्धारित अधिकृत वायुयान में उड़ान करे तो भारत से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : I want to know whether the aircraft concerned was a fighter one and whether China considers granting of such permission as a sign of our weakness and is India Government going to take a serious action for such flights.

Shri Swaran Singh : This was an ordinary aircraft of Pakistan Air Lines which carries passengers and not a Chinese aircraft. Under the agreement our aircrafts of Hindustan Air Lines can also fly over Pakistan.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : पहले दो बार जब श्री चाऊ-एन-लाई भारत के ऊपर से उड़े तो उन्होंने भारत सरकार से अनुमति ली। इस बार ऐसा नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि (क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के ऊपर से उड़ते हुए श्री चाऊ-एन-लाई ने हमारे प्रधान मंत्री को एक सन्देश रेडियो से भेजा। (ख) क्या बिना पूर्व घोषणा की उड़ानों के बारे में यह समझौते में निर्धारित है कि वायुयान को हमारे हवाई अड्डे पर ठहरना चाहिये था जैसा कि इस बार नहीं किया गया और (ग) क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का जो उल्लंघन हुआ है वह पाकिस्तान तथा चीन को विदित कर दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा करने में किसी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई समझौते का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिये पाकिस्तान अथवा चीन को विरोध प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक पूर्व सूचना का सम्बन्ध है वह सामान्य पी० आई० ए० सेवा की उड़ानों के लिये आवश्यक नहीं है। हमें पहले ही बता दिया था कि चाऊ-एन-लाई भी एक यात्री उस उड़ान में होंगे। यह सत्य है कि उसने हमारे प्रधान मंत्री को एक सन्देश भेजा था।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Is there legal obstacle under the agreement that we could not refuse permission to the flight of Chou-En-Lai or such other enemies of India.

Shri Swaran Singh : There is no such international agreement nor any such practice.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Chou-En-Lai could go to Rumania *via* Moscow but he did it deliberately to injure India's feelings. May I know whether Prime Minister can say frankly that in future India will not permit such flights. Moreover China has not subscribed to any air agreement.

Mr. Speaker : The question relates whether Pakistan did a proper thing or not in so doing.

पश्चिम बंगाल सीमा पर पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोली बारी—जारी

अध्यक्ष महोदय : वैदेशिक कार्य मंत्री कल के ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में जिसका सम्बन्ध कूच-बिहार सीमा पर गोली चलने से था, अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैंने इस सदन में 22 मार्च को एक वक्तव्य दिया और कहा कि पाकिस्तान ने हमारी 4-बिन्दु वाला प्रस्ताव मान लिया है जो हम ने 20 मार्च को उन्हें दिया था। इसका सम्बन्ध पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने जो कूच-बिहार सीमा पर गोली चलाई है, उस से था। हमारा पहला प्रस्ताव तो यह था कि सीमा पर तुरन्त गोली बारी

बन्द हो। यदि ऐसा हो गया तो पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिवों की बैठक हो जिसमें शान्ति बनाये रखने के लिये आगे बात हो और जो व्यक्ति दाहाग्राम छोड़ कर चले गये हैं व वहां वापिस जावे। यह भी मान लिया गया कि पूर्वी पाकिस्तान के कमान्डेन्ट जल्दी ही पश्चिमी बंगाल सीमा पुलिस के कमान्डेन्ट से युद्ध-विराम के लिये मिलें। इस पर हमारे ढाका स्थित उप-उच्च आयुक्त उन पाकिस्तानी अधिकारियों को वीसा देगे जो भारत से होकर दाहाग्राम जाना चाहें।

दुर्भाग्यवश पाकिस्तान की सरकार ने अपने कमान्डेन्ट को यह निर्देश देने में देर कर दी और उसके कारण कूच-बिहार में गोली-बारी अभी जारी है। 24 मार्च की रात से तो लड़ाई तीनबीघा क्षेत्र में और तीव्र हो गई है। 28 मार्च तक खड़खड़या, बागडोकरा, जिकाबारी और तीनबीघा में गोली-बारी जारी रही तथा तेज रही।

पश्चिमी बंगाल सीमा पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई तथा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया।

हम ने समझा कि यह तेज लड़ाई इसलिये है कि पाकिस्तान के उच्च अधिकारी रावलपिंडी गये हुए हैं जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति के अपने पद ग्रहण का उत्सव है। हमारे उप-उच्चायुक्त ने ढाका में कह दिया कि दाहाग्राम आदि में जाने के लिये वीसा तब दिये जावेंगे जब युद्ध-विराम होगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिवों की बैठक शीघ्र ही हो।

पाकिस्तान के भारत स्थित उच्चायुक्त पहले ही ढाका के लिये चले गये हैं और हमारे उच्चायुक्त भी कराची से ढाका पहुंच रहे हैं और ऐसी आशा है कि 22 तथा 29 मार्च को लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित किया जावेगा और इस प्रकार वहां गोलीबारी बन्द हो जावेगी और मुख्य सचिवों की बैठक के लिये मैदान तैयार हो जावेगा।

अध्यक्ष महोदय : हम अपनी भूमि में उन्हें बढ़ने से रोकने में सफल हो पाये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सत्य है और मैंने अपने वक्तव्य में भी कह दिया है।

अध्यक्ष महोदय : फिर स्थगन-प्रस्ताव के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ध्यान आकर्षण सूचना की अनुमति देता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Are the Government prepared to consider the use of as good arms as our adversaries are using?

Shri Swaran Singh : We will use even better arms to protect our country.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : पाकिस्तान ने पूर्व के समझौते को तोड़ कर गोली-बारी जारी कर दी है। वहां पाकिस्तान में इस समय चीन के वैदेशिक कार्य मंत्री भारत के विरुद्ध हर जल्स में बोल रहे हैं। पाकिस्तान वैसे भी कह रहा है कि भारत को सबक सिखायेगा। इन बात को देखते हुए क्या सरकार को विश्वास है कि पाकिस्तान कोई बड़ी शरारत करना नहीं चाहता ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इन सब बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं और हमारा सब से बड़ा कार्य यह है कि अपने देश की रक्षा करें।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : पाकिस्तान ने भारी सैनिक जमाव पश्चिमी बंगाल के पास किया हुआ है और वहां हवाई अड्डा बनाने के लिये जंगल भी साफ कर रहा है। पाकिस्तान के रेडियो ने भी 26 मार्च, 1965 को भारत पर झूठा आरोप लगाया है कि वह गोली बारी कर रहा है और दाहग्राम में पूर्व जैसी स्थिति रखने में असफल रहा है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपने देश की रक्षा करेंगे। भारत ने किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। यह तो पाकिस्तान ने किया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या चीनी प्रधान मंत्री की ढाका में उपस्थिति ने इस समस्या को और गम्भीर बना दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : आप अपना ही अनुमान लगाइये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सैनिक 2" तथा 3" मोरटर को प्रयोग कर रहे हैं। क्या सरकार ने हर प्रकार के आक्रमण को विफल बनाने के आदेश जारी किये हुए हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपनी रक्षा के लिये जो भी शस्त्र आवश्यक होगा प्रयोग करेंगे।

श्री दाजी (इन्दौर) : क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान की ओर से पुलिस का ही प्रयोग हो रहा है अथवा सैनिक भी हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : अभी तक हमें जो कुछ पता है उसके अनुसार तो वे सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : पाकिस्तान का रेडियो हमारे विरुद्ध झूठा प्रचार कर रहा है। पाकिस्तान का सारा उद्देश्य यह है कि पहले तो बीड़ा ले ले और फिर युद्धविराम करे। क्या ऐसा करके हम ने अपना अपमान नहीं करवाया है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम ने अपना अपमान नहीं करवाया है। यह सच है कि पाकिस्तान रेडियो हमारे विरुद्ध पाकिस्तान झूठा प्रचार कर रहा है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : समाचार पत्रों में यह समाचार आया है कि हमारे अधिकारियों ने कुछ मोरटर पकड़े हैं जो पाकिस्तान को "सीटी" द्वारा प्राप्त हुए और जिसमें ब्रिटेन तथा अमरीका मिले हुए हैं। क्या यह सच है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास कोई सूचना इस समय नहीं है। मैं इसे देख कर बताऊंगा।

श्री प्रभात कार (हुगली) : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार इस गोली बारी को जारी रखना नहीं चाहती। यह कहां तक सच है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा है। मेरा कहना तो यह है कि हमारा आरोप यह है कि पाकिस्तान ने समझौते को कार्यान्वित नहीं किया है।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Whether India has control over its enclave called Sheet Mahal which is in Pakistan? What facilities exist to come from these?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने एक दिन पहले कहा था कि भारत की जो बस्तियां पाकिस्तान में हैं उन पर हमारा अधिकार है ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : मंत्री महोदय ने कचार सीमा के लाठीटीला-घुनाबारी क्षेत्र के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया । क्या वहां की गोलीबारी के बारे में कोई वक्तव्य देंगे ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान्, मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ 21(11)/64-पी आर (टी) की एक प्रति, जो दिनांक 7 जनवरी, 1965, के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 में कुछ संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4088/65]

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : श्रीमान्, मैं पशु कल्याण बोर्ड मद्रास के वर्ष 1963-64 के वार्षिक लेखे के बारे में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4089/65]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान् मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है ।

1. कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 25 मार्च, 1965 को पारित किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1965 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

2. कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 26 मार्च 1965 को पारित किये गये केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1965 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

3. कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1965 को पारित किये गये केरल विनियोग विधेयक, 1965 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyer) : I want to raise a point of order regarding item No. 5. We are going against the provision of Constitution. We are not competent to discuss Budget of Kerala. A legislative Assembly has been elected there. It is the right of that Assembly to discuss the Budget of Kerala. That is my point of order.

Mr. Speaker : At the time of Kerala Budget we were competent to discuss that and we have passed that. If it was wrong, it could be challenged in a court of Law. This question cannot be raised here now.

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

चौहतरवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं गृह-कार्य मन्त्रालय जनशक्ति तथा व्यवहारिक जनशक्ति गवेषणा, संस्था, नई दिल्ली के बारे में प्राक्कलन समिति का चौहतरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

पहला प्रतिवेदन

श्री प० गो० मेनन (मुकुन्दपुरम) : मैं नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

प्रतिरक्षा मंत्रालय—जारी

श्री जोकीम आलवा (कनारा) : देश के विभाजन के साथ साथ हमारी प्रतिरक्षा की समस्याओं में वृद्धि हो गई है। आज भी चीन से खतरा बना हुआ है। चीन के विदेश मंत्री ने शेख अब्दुल्ला को निमंत्रण भेजा है। विभाजन के समय यह तय कर लिया जाना चाहिये था कि यदि इन बातों का उल्लंघन हुआ तो विभाजन की संधि अत्रैध हो जायेगी। इसी प्रकार की संधि रूस और इरान के बीच हुई है। पाकिस्तान के साथ यदि विभाजन के समय यह हो जाता तो आज के सीमा सम्बन्धी विवाद न होते।

हमें अपने देश के लिये शक्तिशाली सेना तैयार करनी है। मुझे प्रसन्नता है कि हम 8,25,000 व्यक्तियों की सेना तैयार करने जा रहे हैं। परन्तु यह संख्या अपर्याप्त है। मेरे विचार में हमें बीस लाख सैनिकों की सेना बनानी चाहिये। केवल तभी हम प्रभावी रूप से देश की रक्षा कर सकते हैं। हमें पाकिस्तान को बूसपैठों का भी जवाब देना है और चीन की धमकियों के प्रति चौकस रहना है। आज कल संसार के सभी देशों ने बड़ी संख्या सेनायें बनाई हुई हैं। हम ने इस बात को घोषणा कर दी हुई है कि हम अगुशक्ति को शान्ति के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लायेंगे परन्तु हमें अपने देश की सुरक्षा के लिये तैयार रहना है। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये। नहीं तो हमारी स्वतंत्रता को खतरा होगा। विदेशी सहायता भी इतनी लाभप्रद नहीं हो सकती। हमें अपने ही संसाधनों से

[श्री जोकिम आल्वा]

अधिकतम लाभ उठाना होगा। हमारे वर्तमान प्रयत्न तो 8,25,000 की संख्या की सेना तैयार करने के हैं। परन्तु मेरा सुझाव है कि हमें 20 लाख सैनिकों की सेना तैयार करनी चाहिये। हमें अपनी नौसेना भी बढ़ानी चाहिये। हमारे देश का समुद्र तट बहुत लम्बा है। उसकी सुरक्षा करने के लिये नौसेना को सुदृढ़ बनाना अत्यावश्यक है। आज पनडुब्बी का बहुत महत्व है। हमें अपनी नौसेना को पन-डुब्बियों से लैस करना है। इसके लिये भी हमें स्वयं प्रयत्न करने हैं। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे तकनीकी विशेषज्ञ हैं। वे सभी प्रकार के हथियार बना सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि कल पुर्जों के कारखानों में भी लड़ाई का सामान तैयार किया जा सके। हमारे देश में चार या पांच मोटरों के कारखाने हैं। इन्होंने देश के सुरक्षा के बारे में कोई काम नहीं किया है। युद्ध काल में इन से युद्ध सामग्री तैयार करने का कार्य लिया जाना चाहिये। यह कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। पश्चिमी देशों में इस प्रकार के कारखानों से लड़ाई के समय युद्ध सामग्री बनाने का काम लिया जाता है। अपने देश के गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने तो निजि लाभ के पीछे ही पड़े रहते हैं। हमारे देश के बहुत से आयुध कारखानों ने बहुत अच्छा काम किया है। कई स्थानों पर सम्पूर्ण वस्तुएं देसी सामान से तैयार की जा रही हैं।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन जो कारखाने हैं उनका कार्य सराहनीय है। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फ़ैक्ट्री में कारें बनाने की भी व्यवस्था है। इसी प्रकार गैर सरकारी क्षेत्र के कारों के कारखानों में आवश्यकता के समय युद्ध सामग्री बनाने की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

मेरे विचार में हमारी गुप्त वार्ता विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने की ओर भी कार्यवाही की गई है। इसमें आधुनिक प्रकार प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिये। इस विभाग पर देश की सुरक्षा बहुत कुछ निर्भर करती है। आज की स्थिति में हमें बहुत सतर्क होना है और देश की लम्बी सीमाओं की रक्षा करनी है। हमारी सेना ने संसार में बहुत ख्याति प्राप्त की है। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ विश्व उड्डयन सप्ताह मनाया गया था। वहाँ पर भारतीय सेना के कुछ डाक्टरों ने अपने पत्र पढ़े उनको सुन कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारी सेना में इतने प्रतिभाशाली लोग हैं। हमें इनका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये। हमें अपने आयुध कारखानों का उत्पादन बढ़ाना है। इन कारखानों में काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है परन्तु उसमें और सुधार होना चाहिये। हमारे अणु शक्ति विभाग ने भी बहुत से कल पुर्जे बनाये हैं। उनका उपयोग भी किया जाना चाहिये। हमें अपनी नौसेना का भी विकास करना है। इसके लिये आवश्यक धन दिया जाना चाहिये। हमारी वायु सेना ने भी बहुत कार्यकुशलता का परिचय दिया है। हमें इनको शक्तिशाली बनाने के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही करनी है। हमारे जवान हिमालय की चोटियों पर बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपना कार्य कर रहे हैं और देश की रक्षा में योग दे रहे हैं। हम उनके कार्य की सराहना करते हैं।

श्री नारायण दांडेकार : (गोंडा) : हमारे भूतपूर्व प्रतिरक्षा मन्त्री की देन के बारे में कहूंगा। वह लगभग पांच वर्ष तक प्रतिरक्षा मन्त्री रहे थे। मैं वर्तमान मन्त्री की आलोचना नहीं करूंगा। इन्होंने तो बहुत कार्य किया है। मैं अपनी बात पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को सामने रख कर करूंगा। यह विभिन्न पार्टियों का प्रश्न नहीं है। हमने 8,25,000 की संख्या से सेना बनाने का लक्ष्य बनाया है। हमारी सेना में 21 डिवीजन होंगी। यदि एक डिवीजन में 20,000 व्यक्ति हों तो 4,20,000 तो इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में भाग लेने वाले हुए। शेष 4,05,000 व्यक्ति शेष जो सेना के लिये पीछे की तैयारी में लगे रहेंगे। मेरे विचार से इन पीछे वालों की संख्या बहुत अधिक है। सरकारी

प्रकाशनों को पढ़ने के पश्चात् मैंने देखा है कि हम ब्रिटेन की इम्पीरियल सेना की प्रणालियों का अनुसरण कर रहे हैं। अंग्रेजों के राज्य काल और आजकल की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। हमें इस प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये कि अपनी सेना के संगठन में क्या क्या परिवर्तन करने चाहियें। चीन की सेना का संगठन बिल्कुल ही विभिन्न है। हमें भी अब इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। जहां तक मोटर गाड़ियों के सेना द्वारा उपयोग का प्रश्न है हमारी सेना में इन का उपयोग बहुत अधिक संख्या में होता है। चीन में सैनिकों और गाड़ियों के अनुपात के मुकाबले हमारी सेना में गाड़ियां बहुत अधिक संख्या में हैं। इस ओर भी ध्यान दिया जाय। हमारी सेना के पास विभिन्न प्रकार के टैंक हैं। हमें इतनी प्रकार के टैंक नहीं रखने चाहियें ताकि सैनिकों को टैंकों के चलाने और सम्बद्ध कार्यों से पूरी जानकारी हो सके। हमारी सेना की अन्य कोरों (Corps) में भी खर्चा बहुत है और जितना खर्चा मांगा जाता है सदन मंजूर कर देता है। मैं प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सेना में मितव्ययिता की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। हमें धन की देश के विकास कार्यों के लिये भी आवश्यकता है। मैं लेख निरीक्षकों की इस आलोचना से प्रभावित नहीं हुआ कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने अधिक धन मांगा था और व्यय कम किया है। हमें तो प्रशंसा करनी चाहिये कि खर्चा कम किया गया है। हमारी सेनाओं के संगठन के बारे में बने हुए नियम बहुत पुराने हैं। नियम पुस्तकें पिछले युद्ध से पहले से चली आ रही हैं। उनमें कई शुद्धि-पत्र लगा दिये गये हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि उनको फिर से छाप कर आधुनिकतम स्तर कर देना चाहिये। आज संसार में नयी नयी प्रणालियां उपयोग में लायी जा रही हैं। हमें आधुनिक वस्तुओं से लाभ उठाना है। हमारी सेनाओं में बहुत अनुशासन है। उनका मनोबल भी बहुत ऊंचा है। अंग्रेजों के राज्य काल में भी उनमें कर्तव्य परायणता की भावना थी परन्तु अब तो उनमें राष्ट्रीय भावनाएँ भी हैं। हमारी सेनाओं में प्रशिक्षण प्रणाली में भी आधुनिक ढंग अपनाये जाने चाहियें। हमें अच्छे अच्छे सैनिक और अधिकारी तैयार करने हैं। अन्य देशों में इस बारे में बहुत प्रगति हुई है। हमारी सेनाओं के बड़े अधिकारियों के दिलों में पदोन्नतियों के बारे में असन्तोष है। उन्हें मालूम नहीं कि इस बारे में प्रक्रिया क्या है।

जहां तक सेना के लिये छोटे हथियारों के उत्पादन का सम्बन्ध है हमने पर्याप्त प्रगति की है। संचार के साधनों में हम बहुत पीछे हैं। इस दशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और कमी पूरी की जानी चाहिये। हमारे पहले के निर्णय के अनुसार हमें छः आयुध कारखाने बनाने थे परन्तु अब केवल चार बनाये जा रहे हैं। मैं इस बात को समझ नहीं सका। 1964 के बजट के समय भी छः की बात की गई थी परन्तु छः महीने पश्चात् इस निर्णय में परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसा पता चला है अमरीका ने भी सरकार से कहा है कि हमें आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। इन चीजों को देखते हुए मैं अपनी तैयारी के बारे में प्रभावित नहीं हुआ हूँ। हमें अपनी वायु सेना को भी शक्तिशाली बनाने की कार्यवाही भी करनी है।

मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारी एयर फोर्स प्रतिक्षात्मक हों तथा आक्रमण न हों तो भी हमें लगभग लड़ाकू विमानों के 45 स्क्वेड्रन चाहियें। मध्यम प्रकार के बाम्बर चाहिए, सेना की सहायता वाले विमान चाहियें, परिवहन विमान चाहिए तथा हेलीकाप्टर चाहियें।

हमारे पास सात प्रकार के लड़ाकू विमान हैं जिनमें से तीन प्रकार के अंग्रेजों हैं, बैम्पायर्स गनाट्स तथा हन्टर्स दो प्रकार के फ्रांसीसी हैं। तूफानी (ओरान्स) और मीस्टीयर्स, एक रूसी है। मिग तथा एक भारतीय है, एच, एफ-24, इन सब की क्या जरूरत है। वैम्पायर तथा तूफानी पुराने हो चुके हैं, मीस्टीयर्स, मिस्टीरीयर्स हैं अर्थात् बिल्कुल बेकार हैं। गनाट्स अतिस्वन नहीं

[श्री नारायण दांडेकर]

है, चार महीनों में दो महीने यह खड़े रहते हैं। गाइडेड मिसाइल्स इनमें नहीं रखी जा सकती हैं तथा इनको नैटोने अस्वीकार कर दिया है। एच० एफ०-24 में 'ग्नाट' का इंजन लगा हुआ है इसलिये यह भी ऐसे ही हैं। इसके अतिरिक्त हम इतने दिनों से एम०ए०सी० एल० 1.5 लड़ाकू विमानों के बारे में इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं। इतनी खराब मशीन मैंने तो देखी नहीं जितनी खराब यह है।

अब मिग विमानों को लीजिए। ये अच्छे विमान हैं तथा आधुनिक हैं। परन्तु मुझे इनके बारे में कुछ संदेह है इनके निर्माण के बारे में इतनी गोपनीयता है कि कुछ भी कहना ठीक नहीं है 1963 में हमें छः मिग मिले थें। इनमें से दो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दो के इंजनों में खराबी आ जाने के कारण उनको खड़ा कर दिया गया। अब केवल दो काम में आ रहे हैं। 1963 से बराबर हम सुनते आ रहे हैं कि मिग विमानों के तीन स्क्वैड्रन आ रहे हैं। परन्तु मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार आ रहे हैं। क्या यह बैलगाड़ी में लद कर आ रहे हैं अथवा मनुष्य उन्हें खींचकर ला रहे हैं इसका हमें मालूम नहीं है।

मेरे मित्र श्री थामस ने एक बार सभा में बताया था कि लगभग चार वर्ष में मिग विमान भारत में बनने लगेंगे। मुझे भी निर्माण संबंधी कुछ अनुभव है। उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इतने कम समय में ऐसा करना नितांत असंभव है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि वह हमें परियों की कहानियां न सुनायें अपितु साफ साफ तथा ठीक ठीक बतायें हमें ये विमान कब तक मिल जायेंगे तथा इनका निर्माण भारत में कब तक होने लगेगा।

हमारे पास इस समय यदि कोई अच्छा विमान है तो वह 'हन्टर' विमान है। इसलिए मेरा यही कहना है कि हमें रूस से मिग लेने का प्रयत्न करना चाहिए तथा अमरीका से एफ-5 तथा फान्टम विमान लेने का भी प्रयत्न करना चाहिए।

अब मैं परिवहन विमानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। डकोटा विमान वास्तव में बहुत अच्छा विमान है। परन्तु मैं इसके बारे में कुछ न कहकर एवरो 748 तथा एच० एफ-24 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने अपना यह बड़ा ही अच्छा प्रचार किया था। 1958-59 से अब तक छः वर्षों में केवल दो विमान बनाये गये हैं जबकि कानपुर के कारखाने का प्रचार इतना किया गया।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यद्यपि आज 1962 के मुकाबले में हमारी सेना की हालात बहुत अच्छी है परन्तु फिर भी अभी हमारे पास अच्छे शस्त्रास्त्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सैनिकों के परिवारों को उनके मरणोपरांत अच्छी पेंशन देने की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में हमें उदारता से व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री श्री बातीं पर ध्यान देंगे।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, 1964-65 के प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि विदेश नीति तथा प्रतिरक्षा आयोजना का काम एक साथ तथा एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इस बात को समझा परन्तु देर से।

प्रतिवेदन में दूसरी बात यह कही गयी है कि चीन लड़ाई की तैयारी कर रहा है और इससे हमें बहुत खतरा है। अध्यक्ष महोदय पाकिस्तान हमारा दिन प्रतिदिन हमारा मजाक बनाता जा रहा है। लूट मारआदि पाकिस्तान का रोजमर्रा का काम हो गया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

मार्शल चैन यी ने 28-3-65 को रावलपिंडि में घोषणा की थी कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में चीन-पाकिस्तान का आपसी सहयोग एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। इस आधार पर हमें चीन तथा पाकिस्तानी सेनाओं की शक्ति का गलत अनुमान नहीं लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इण्डोनेशिया की सीमा भी नीकोबर की सीमा से 40 मील दूर है। इस प्रकार हमें समझना चाहिये कि हमें चारों ओर से खतरा पैदा हो रहा है।

चीन ने अपनी सेना बहुत बड़ी बना ली है आज उसकी सेना में लगभग 40 फील्ड आर्मीज हैं। इसकी पैदल सेना के एक इंफेन्ट्री डिवीजन में 11000 से 12,000 जवान हैं। उनकी वायुसेना में लगभग 2600 विमान हैं जिनमें से 2000 जैर विमान हैं।

इसके बाद मैं चीन के लोगों के मनोभावों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चीन के नेताओं का कहना है कि चीन की सेनाओं को किसी की सेना शस्त्रास्त्र आदि का डर नहीं है। वह चाहें तो नेपाल, भूटान, सिक्किम तथा आसाम किसी भी क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। तिब्बत के निकट अनुमान है कि उनकी सेना के लगभग 1,60,000 सैनिक लगे हुए हैं। भारत को यह सब समझना चाहिए और ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे भारत का मस्तिष्क ऊंचा रहे। चीन तथा पाकिस्तान दोनों ही बातचीत से मानने वाले लोग नहीं हैं। वह तो केवल ताकत की भाषा ही समझते हैं। इसलिए सरकार को देश को शक्तिशाली बनाना चाहिए। इस संबंध में जनता का सहयोग भी लेना चाहिए। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने जब अपील की थी तो देश एक होकर सामने आया था।

जब चीन ने अणुबम का विस्फोट किया था 'लैपनोर' में तो समस्त संसार ने चिन्ता व्यक्त की थी। अमरीका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि चीन का शत्रुतापूर्ण व्यवहार भारतीय सरकार के लिए चिन्ता का कारण बना हुआ है। इसलिए भारत सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए कि अणुबम आदि से सेना को लैस करे।

सभी देश अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं पर बहुत धन व्यय करते हैं अर्थात् वह कुल बजट का 60 प्रतिशत तक हो जाता है। परन्तु हमारे बजट में 1963-64 में 204 करोड़ रुपया रखा, 1964-65 में 716 करोड़ रुपया रखा तथा 1965-66 में 748 करोड़ रुपया रखा। मैं समझ नहीं पाया कि इतनी थोड़ी राशि से हम अपनी सेना को आधुनिक किस प्रकार बना सकेंगे।

अब मैं अपनी समुद्री सीमा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी समुद्र सीमा 3,500 मील लम्बी है। तथा भूमि सीमा 9,945 मील लम्बी है। अर्थात् कुल सीमा की

[श्री रघुनाथ सिंह]

लगभग 30 प्रतिशत समुद्र सीमा है। परन्तु हम उसकी रक्षा के लिए 4 प्रतिशत धन भी व्यय नहीं कर रहे हैं। केवल 3.3 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नौसेना पर केवल एक प्रतिशत ही व्यय कर रहे हैं। अमरीका अपनी नौसेना पर 29 प्रतिशत व्यय कर रहा है।

आप नौसेना के बजट को लीजिए। 1963-64 में इसके लिए 22 करोड़ रुपए रखा था। 1964-65 में 23 करोड़ रुपया रखा था। 1965-66 में 25 करोड़ रुपया रखा था। इस राशि से हम चाहते हैं कि पनडुब्बियां खरीदें। अपने पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज लाये। मैं समझ नहीं पाया कि हम इतनी थोड़ी राशि से ऐसा किस प्रकार करना चाहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हम अपनी नौसेना के विकास पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितना हमें देना चाहिए और नौसेना के लिए किस प्रकार हम आधुनिक शस्त्रास्त्र उपलब्ध करना चाहते हैं।

हमें जल सेना के महत्व को कम नहीं करना चाहिये। चीन, इण्डोनेशिया और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर जल सेना के 1,069 एकक हैं; इसकी तुलना में भारत के पास 44 एकक हैं। हमारी सीमा हिन्दमहासागर में सुमात्रा से केवल 40 मील दूर है और चीनियों की स्टीम बोट्स वहां चलती रहती हैं। हमारा तट 3,500 मील लम्बा है और 44 एककों से हम इसकी किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं। और जल सेना को जो 25 करोड़ रुपये दिये गये हैं वह बहुत कम है।

अंग्रेजों के सहयोग से 1972-73 में तीनफ्रिगेट बनाने का हमारा कार्यक्रम है। परन्तु यदि इस बीच युद्ध छिड़ गया तो हम क्या करेंगे। हमारे पास न तो टारपीडो बोट हैं और न ही पुनडुब्बी से लड़ने वाले पोत हैं। हमें चीन की जल-सेना की शक्ति को ध्यान में रखना चाहिये। इण्डोनेशिया के पास छः पनडुब्बियां हैं जबकि हमारे पास एक भी नहीं है। हमें द्रुत गति वाले विध्वंसक पोत और पनडुब्बियों की आवश्यकता है। हमें जल सेना को आधुनिक शस्त्रों तथा अस्त्रों से सज्जित करना चाहिये।

अन्त में मैं श्री चान्हाण को भारत के लोगों की ओर से आश्वासन देता हूं कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये सब कुछ करने को तैयार हैं। हजारों वर्षों की दासता के पश्चात् जो स्वतन्त्रता हमें मिली है उसको बनाये रखना हमारा कर्तव्य है।

श्री श्याम लाल सर्राह (जम्मू और काश्मीर) : वर्ष 1963-64 में रक्षा मंत्रालय के बजट आंकड़ों को यदि हम देखें तो राजस्व के वास्तविक आंकड़े 704.14 करोड़ और 119.98 करोड़ पूंजीगत बजट में था। वर्ष 1964-65 के संशोधित अनुमानों में राजस्व बजट 717.80 करोड़ हो गया है और पूंजीगत बजट 141.10 करोड़ और कुल 853.90 करोड़। वर्ष 1965-66 में हमारे पास 748.74 करोड़ रुपये का राजस्व है और 130.65 करोड़ रुपये पूंजी बजट के हैं।

श्री दांडेकर ने कुछ आदर्श चीजें बताई हैं जो हमारे पास होनी चाहिये। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि यह धन हमें लोगों से कर के रूप में वसूल करना है। 1963-64 के बजट में लोगों पर अधिकतम कर लगाये गये थे और उस धन का बहुत बड़ा भाग सेना पर व्यय किया जा रहा है।

1964-65 के बजट में सेना के लिये जो राशि निर्धारित की गई थी उसमें राजस्व में 99 करोड़ रुपये की कमी रही है लेकिन वेतन, भत्ते और परिवहन के व्यय में इतनी ही वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो राशि एक मद में व्यय नहीं की जा सकी उसको दूसरे मद में व्यय कर दिया। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने यह प्रशंसनीय कार्य किया है। इसी प्रकार पूंजी में भी 1.15 करोड़ रुपये की कमी रही है; परन्तु मंत्रालय ने इसे किसी और मद में, जिसे उसने उचित समझा, व्यय कर दिया।

700 करोड़ रुपये की राशि जो सेना के लिये आवंटित की गई है, उसमें से 301.12 करोड़ रुपये वेतन और भत्तों के लिये है, 343.9 करोड़ रुपये स्टोर और उपकरणों के लिये हैं, 47.53 करोड़ परिवहन और विविध लेखे के लिये आदि आदि। इससे पता चलता है कि जल स्थल तथा वायु सेना की ताकत में वृद्धि हो रही है। वेतन तथा भत्तों की तुलना में स्टोर, उपकरणों तथा परिवहन पर अधिक व्यय हो रहा है।

1964-65 की तुलना में 1965-66 में 31.93 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया जा रहा है। यह वृद्धि इस प्रकार हुई है: सेना 2 करोड़, जल सेना 2 करोड़ और वायु सेना 28 करोड़। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि हमने अपने साधन देख कर अपने पांव पसारें हैं।

इस वर्ष के पूंजी आयव्ययक में 12.10 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसका काफी भाग विवाहित व्यक्तियों के आवास-निर्माण के लिये व्यय किया जायेगा।

वित्तीय नियंत्रण के लिये जो उपाय किये गये हैं जिससे कि धन उचित रूप से व्यय किया जा सके, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

सेना की कुछ श्रेणियों में, विशेषतया नर्सों के वेतन में जो वृद्धि की गई है बहुत प्रशंसनीय है।

आपात स्थिति की घोषणा के उपरान्त भरती के लिये जो लक्ष्य स्थिर किया गया था वो अब पूरा हो चुका है। और पहली बार बिना इस बात पर विचार किये कि जवान लड़ने वाली कौम में से है कि नहीं भरती की गई है। जवानों और अधिकारियों के सम्बन्ध भी बहुत अच्छे हैं।

डाक्टरों और इंजीनियरों की सेना में कुछ कमी थी। अतः इनको सेना में भरती के लिये उत्प्रेरणा देने के लिये मंत्रालय ने विश्वविद्यालय से सीधे भरती का निश्चय किया है। इंजीनियरिंग कोर्स के चौथे वर्ष में विद्यार्थियों को कमीशन दे दी जाती है। और पांच वर्ष की सेवा के उपरान्त इन्हें असैनिक विभागों में कार्य करने के लिये इजाजत दे दी जाती है। इस प्रकार डाक्टरों को भी यही सुविधा दी जाती है। माननीय मंत्री को वाद-विवाद का उत्तर देते समय बताना चाहिये कि यह योजना किस प्रकार चल रही है।

सेना में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह बहुत ही उत्तम है। चीनी आक्रमण से हमने कई अच्छे पाठ सीखे हैं। इसका पता इससे चलता है कि किस प्रकार सेना ने अपना लड़ने की क्षमता, अच्छे हथियारों की तरक्की की है। सैनिकों को अच्छे और प्रभावकारी हथियार दिये गये हैं। सीमा पर सड़कें बनाने से परिवहन की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

[श्री श्यामलाल शर्मा]

लड़ने की रीति में विकास करने के लिये जिस निदेशालय की स्थापना हुई है वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। हमें सेना के गुप्त वार्ता विभाग में अभी और सुधार करना चाहिये।

माउंटेन डिवीजन के लिये एक जगह से दूसरी जगह द्रुत गति से जाने की क्षमता और अधिक शक्तिशाली हथियार होने चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इन सब चीजों के लिये धन दिया है। सेना अनुसंधान में ऐसे खाद्य पदार्थ बनाये हैं जिनको सरलतापूर्वक ले जाया जा सकता है और पकाया भी जा सकता है। मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूँ। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में दो नई स्काउट बटालिन्स बनाई गई हैं।

हमारी सेना के अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय कार्य सौंपे गये थे जिनका उन्होंने भली प्रकार निर्वहन किया। अपने कार्य से उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है।

प्रतिरक्षा अनुसंधान के लिये एक बहुत ही उत्तम प्रतिरक्षा अनुसंधान विकास परिषद भी है। हमें परिवहन के मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिये। प्रतिरक्षा मंत्रालय को खाद्य के मामले में भी बहुत सतर्क रहना चाहिये।

प्रादेशिक सेना (टैरीटोरियल आर्मी) सुचारु रूप से कार्य कर रही है। एन० सी० सी० की यूनिटें हमारे स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रशंसनीय ढंग से काम कर रही हैं।

मैं देश के उस भाग का रहने वाला हूँ जहाँ कि स्थिति विषम एवं गम्भीर रही है और वहाँ की स्थिति अब भी संकटपूर्ण बनी हुई है। शेख अब्दुल्ला की चर्चा की गई है। उनके वक्तव्य देश तथा सेना के मनोबल के लिए हानिकारक हैं। उन पर रोक लगा दी जानी चाहिए। सरकार को इस सम्बन्ध में स्थिति का सामना करने के लिए दृढ़ कदम उठाने चाहिए, शेख अब्दुल्ला के भाषण सेना के मनोबल पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं और वह अपने अभिभाषणों के दौरान सेना की आलोचना करते हैं। वह हमारे सेना शिविरों के आस पास विषैले भाषण देते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया की भयंकर ज्वालायें सेना के मनोबल को अपनी लपेट में लिए बिना नहीं रह सकती हैं। वह भारत-विरोधी वक्तव्य दिये जा रहे हैं और सरकार चुप बैठी हुई है।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन का जहाँ तक सम्बन्ध है, हमें आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण करके उनका विस्तार करना चाहिए और नए आयुध कारखाने स्थापित करने चाहिए। यद्यपि तुलनात्मक दृष्टि से हमारे प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और हमें इस कार्य में काफी सफलता मिली है, तथापि हमें उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना आवश्यक है।

जहाँ तक वायु सेना का सम्बन्ध है, हमारे पास स्कॉर्डन विमान, लड़ाकू विमान, बम वर्षक विमान तथा गश्ती विमान मौजूद हैं, हमें इन विमानों की किस्म में सुधार भी करना है और उनका उत्पादन भी बढ़ाना है। इसके लिये सुव्यवस्थित प्रशिक्षण बहुत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। वायु सेना के सभी एककों में गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। नौसेना का विकास और समुद्रीय शक्ति में भी वृद्धि हुई है। मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। घोड़े, खच्चर आदि की नस्ल में सुधार किया जाना आवश्यक है। स्थल सेना परिवहन का प्रयोग करने में हमें और अधिक सावधानी तथा निगरानी करने की आवश्यकता है। स्थल-सेना के लिए सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की जांच की जानी चाहिए। प्रतिरक्षा विभाग में भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ है। इंजीनियरिंग योजनाओं के लिए हमें वस्तुरूप (डिजाइन), उसके निर्माण

तथा रख रखाव सम्बन्धी मामलों की स्पष्ट रूखरेखा तैयार करनी चाहिए और प्रतिरक्षा वर्कशॉप्स तथा कारखानों में तैयार किये गये माल की किस्म सर्वोच्च होनी चाहिए ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय को रेलवे मंत्रालय से बातचीत करके दूर से आने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के लिए स्थान सुरक्षित (protected) करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इसके लिए उन्हें अधिक समय बर्बाद न करना पड़े । प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान का उत्पादन करने वाले एककों पर श्रम कल्याण और श्रम नियम लागू कर देने चाहिए । सेना कर्मचारियों के जमीन सम्बन्धी मामलों पर विचार किया जाना चाहिये । जिला सोल्जर्स बोर्ड, सेलर्स बोर्ड तथा एयरमेन्स बोर्ड में सुधार करने और उन्हें और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है । सेना कन्टोन्मेंट बोर्डों में भी सुधार करने की आवश्यकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रतिरक्षा नीति का हमारी वैदेशिक नीति से घनिष्ठ सम्बन्ध है । दो वर्ष पूर्व, चीनी आक्रमण के पश्चात्, प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद के अवसर पर भी मैंने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे और कहा था कि हमें अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं को अधिकतम मजबूत बनाना चाहिए और इसके लिए हमें अपने देश में उपलब्ध साधनों का प्रयोग करना चाहिए । हमें आत्म निर्भर होना चाहिए, आदि । मुझे सन्तोष है कि सरकार ने उन सिद्धान्तों को लगभग पूरी तरह मान लिया है । सरकार का उन सिद्धान्तों का पालन करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का ढंग भिन्न हो सकता है । हमारे देश में आज भी देश विरोधी तत्व मौजूद हैं जिनसे हमारी स्वतन्त्र प्रतिरक्षा नीति को आघात पहुंच सकता है । देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के नारे लगाये जाते हैं । इससे हमारे वैदेशिक-कार्य क्षेत्र में भी बाधा पड़ सकती है । हाल ही में हमारे देश में परमाणु बम के निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में बड़े विरोधी नारे लगाये गये । इस सम्बन्ध में बड़े बड़े तर्क और दलीलें पेश की गईं । किन्तु मेरा कथन है कि यदि हम परमाणु बम तैयार नहीं करते तो फिर हमें दूसरे की शरण ले लेनी चाहिए । कुछ मास पूर्व आणुविक संरक्षण के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार नारे लगाये गये थे । सरकार को इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए ।

सरकार की नीति को देखते हुए ऐसा आभास होता है कि उसकी अपनी कोई भी स्वावलम्बी तथा स्वतन्त्र नीति नहो कर धीरे धीरे किसी का संरक्षण प्राप्त करने अथवा किसी गुट में शामिल होने की है ।

भारत सरकार को स्पष्ट रूप से यह घोषणा करनी चाहिए कि वह प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों पर कोई ऐसी नीति नहीं अपना रही है जिससे कि राष्ट्र की प्रभुसत्ता संकट में पड़े । प्रतिरक्षा से सम्बन्धित मामलों पर हमारी विचारधारा स्वतन्त्रता से पूर्व अंग्रेजी सेना के रवैये पर आधारित है जब कि विदेशी शासकों द्वारा सेना रखी जाती थी । मेरी राय है कि वह विचारधारा हमारे राष्ट्र के लिए संकटपूर्ण सिद्ध हो सकती है । आज पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए गठबन्धन को देखते हुए देश चिन्तित है । भारत की पाकिस्तान से मिलने वाली सीमाओं पर अचानक आक्रमण शुरू हो गये हैं ।

पाकिस्तान सीटों और सेंटों जैसे गुटों का एक सक्रिय सदस्य है और उसने इन गुटों के साथ सैनिक सन्धि की हुई है । पाकिस्तान की हमारी सीमाओं पर लगातार बढ़ते हुए आक्रामक रवैये

[श्री इन्द्र जीत गुप्त]

को और चीन के साथ उसके बढ़ते हुए गठबन्धन को देखते हुए—सरकार को विदेशी सहायता से सम्बन्धित मामलों पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए अन्यथा देश को भविष्य में हानि उठानी पड़ेगी ।

पाकिस्तान के सीटों तथा सेंटों गुटों के सहयोगियों अर्थात् ब्रिटेन और अमरीका से भी हमने शस्त्र-सहायता ली हुई है और विशेषकर अमरीका ने कुछ शर्तें लगाई हुई हैं यथा—हम उन हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सकते । हम देखते हैं कि पाकिस्तान को इन सूत्रों द्वारा हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी के बारे में जानकारी होते रहती है । इसी प्रकार पाकिस्तान के जरिये चीन को भी हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों की जानकारी हो सकती है ।

हमारे संयुक्त राष्ट्रमण्डलीय कार्यों में प्रति वर्ष नियमित रूप से भाग लेने से ऐसा विदित होता है कि हम अभी प्राचीन काल के रूढ़ियों तथा पद्धतियों के प्रभाव से अभी विमुक्त नहीं हुए हैं । हम उनके नौ सेना सम्बन्धी अभ्यासों में शामिल होते हैं । पाकिस्तान भी हमारी तरह शामिल होता है । अतः समझ में नहीं आता कि किस उद्देश्य अथवा भावना से प्रेरित होकर ऐसा किया जाता है और इसका महत्व क्या है । पाकिस्तान का ऐसा करना उचित है क्योंकि वह सैनिक सन्धि के अधीन मित्त राष्ट्र है किन्तु हमारी सेना के बड़े-बड़े पदाधिकारी भी राष्ट्रमण्डलीय सैनिक सम्मेलनों में प्रति वर्ष इंगलैंड जाया करते हैं । हमारी नीति किसी भी गुट में शामिल होने की नहीं है । अतः देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति का गम्भीर रूप से पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है ।

प्रतिवेदन में प्रकाशित सभी मामलों पर चर्चा करना समयाभाव के कारण सम्भव नहीं है । अतः मैं केवल प्रतिरक्षा तैयारी से सम्बन्धित दो-एक बातों की ही चर्चा करूंगा । वर्ष 1962-63 से अभी तक अत्यधिक धीमी प्रगति रही है जिसे देख कर बहुत दुःख होता है । कुछ कार्य किये गये हैं उन्हीं के बारे में विभिन्न प्रकाशनों में विस्तार से वर्णन किया गया है । देश का बहुत सा धन खर्च किया जा चुका है । एच० एफ० 24 विमान के सुपरसोनिक एंजिन तैयार करने अथवा उसे प्राप्त करने में हमें किसी प्रकार सफलता नहीं मिली है । ब्रिटेन के सहयोग से आरफियस एंजिन प्राप्त करने की परियोजना असफल हो गई है । प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं ।

हम बारबार यही प्रयत्न कर रहे हैं कि एच० एफ० 24 के लिए संयुक्त अरब गणराज्यों के इंजिनों, का प्रयोग किया जाय । हम मिग परियोजना के सम्बन्ध में भी प्रायः अभी तक कुछ नहीं कर पाये हैं । अभी तक केवल मिग विमानों के तीन दस्ते प्राप्त हुए हैं । हमारी देश की आवयशकता को देखते हुए यह कुछ भी नहीं है । जहां तक सेना के लिए आधुनिक विमानों की व्यवस्था का सम्बन्ध है अब तक इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है ।

हाल ही में प्रतिरक्षा मंत्री ब्रिटेन के अधिकारियों से बातचीत करने वहां गये थे । ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पनडुब्बियां प्राप्त करने के लिये वहां के अधिकारियों से कुछ गुप्त वार्ता हुई थी किन्तु उसका अभी तक कुछ परिणाम नहीं निकला । जहां तक देश युद्धपोतों का निर्माण करने का सम्बन्ध है, स्थिति निराशाजनक ही है । इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि आज से छः वर्ष पश्चात् हमें मजगांव गोदी से एक युद्धपोत प्राप्त होगा ।

देश में टैंकों के निर्माण में भी कोई प्रगति नहीं हो पायी है । अलादि टैंक कारखाने में अब तक कवल एक टैंक तैयार हो पाया है । हमने हिन्द्यस्तान शिपयार्ड के लिए 'योजनाय तो बना दी किन्तु जहाजों के लिए प्लेटों के अभाव के कारण वे बन्द पड़ी हुई है । सरकार को विदेशों से हल्के तथा मध्यम श्रेणी के टैंक प्राप्त करने के लिए की गई अथवा की जा रही कार्यवाही के बारे में विस्तारपूर्वक बताना चाहिए ।

अब मैं पहाड़ी डीविज़नों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । यह ठीक है कि कवचित सेना मैदानों में लड़ सकती है किन्तु पहाड़ों पर लड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । 1962 में नेफा में हमें इसलिए हार का सामना करना पड़ा कि न तो हमें इन पहाड़ी क्षेत्रों की जानकारी थी और न ही हमें पहाड़ों पर लड़ने का अनुभव था । हमारी संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी और सैनिक गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी । सरकार सभा को सदा ही वास्तविक जानकारी से वंचित रखती है । हमें अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या गुप्तचर सगठन सेना को सौंप दिया गया है अथवा यह कार्य गुप्त वार्ता विभाग अथवा गृह-कार्य मंत्रालय के हाथ में है । पहाड़ी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल एक ही अनुभाग स्थापित किया गया है । मेरा सुझाव है कि कुछ भारत-समर्थक नागा-युवकों को प्रशिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया जाय जो हमारे पहाड़ी डीविज़नों को पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रशिक्षण दे सकें । हमारी सिगनल व्यवस्था भी सन्तोष-जनक नहीं है । सिगनल उपकरणों की कमी अभी तक गम्भीर रूप से बनी हुई है ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में प्रशिक्षण के लिए अपनाये गये तरीकों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जानी चाहिए थी जिससे एक प्रकार की जाति-भेद प्रणाली को समाप्त किया जा सकता था । यदि सेना के कमाण्डरों तथा मुख्य स्टाफ अधिकारियों में इस बारे में असन्तोष हो तो प्रतिरक्षा मंत्रालय को उसे दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए । छोटे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा वेतनों आदि पर चिन्ता किया जाना चाहिए ।

एक ओर तो सैनिक कर्मचारियों के लिए आवास की भारी कमी है और दूसरी ओर कलकत्ता में एक मेजर जनरल के आवास पर 3,900 रुपये प्रतिमास खर्च किये जा रहे हैं । सेना में साहस और अनुशासन की दृष्टि से इस प्रकार की विषमता अनुचित है । प्रतिरक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय की सीमा पर तैनात उन सेना कर्मचारियों के लिए अलग स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए जो थोड़े दिनों के लिए अपने परिवारों से मिलने के लिए छुट्टी पर जाते हैं और छुट्टी समाप्त होने पर जोनाग्रां पर वापस लौटते हैं ।

सेनाओं के लिए जिस तरीके से सामान खरीदा जाता है और उसे बांटा जाता है वह अत्यंत असन्तोषजनक है । अतः प्रतिरक्षा मंत्री को एक सतर्कता आयोग स्थापित करनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि क्या ठेकेदारों जिन्हें करोड़ों रुपये का सामान खरीदने के लिए आर्डर दिये जाते हैं और प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों में किसी प्रकार की साठगांठ तो नहीं चल रही है । नवम्बर, 1962 में बाहर से 1,000 घोड़े खरीदे गये जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 2455 रुपये हैं किन्तु 470 घोड़े जिनका मूल्य 12 लाख रु० है अभी तक डिपो में पड़ हुए हैं । इससे ऐसा सन्देह होता है कि कुछ पोलों के शौकीन सेना अधिकारियों ने ये घोड़े अपने उपयोग के लिये मंगाये हैं । नौसेना के डाकयार्ड कुछ समय पूर्व बनाये गये थे किन्तु बहुत से किस्म के सामान का कुछ भी उपयोग नहीं हो सका क्योंकि उनके रिक्कार्ड नहीं मिल रहे हैं ।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

आयूध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी उत्पादन में भारी वृद्धि करने के कारण बधाई के पात्र है। हम बहुत से उपकरणों का नवीनकरण करने में असमर्थ रहे जिन्हें इन आयूध कारखानों ने कर दिखाया। इन कर्मचारियों की कर्मनिष्ठा तथा काम की लगन को देखते हुए इन के लिए एक अलग मजूरी बोर्ड बनाने के लिए मंत्रालय को विचार करना चाहिए :

यह दुःख की बात है कि ई० एम० ई० में असैनिक कर्मचारियों की छंटनी का सामाचार मिला है। मेरा सुझाव है कि जो कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं उनके सेवाओं का दूसरे असैनिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फिर प्रतिरक्षा कार्यों में लगाया जा सके। तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी करना उचित नहीं होगा क्योंकि देश में ऐसे कर्मचारियों की पहले ही बहुत कमी है? सेना में प्रयोग की जाने वाली मोटरगाड़ियों का एक बार भी ओवरहाल बिना किये नीलाम किया जाता है जो उचित नहीं है। सरकार को इस बारे में जांच करके उचित कदम उठाना चाहिए।

श्री मजीठिया (तरनतारन) : जिस प्रकार हमारे जवानों तथा सेना के अधिकारियों ने न केवल भारत की सीमाओं पर ही अपितु देश के बाहर भी अपना कर्तव्य निभाया है वह अत्यन्त सराहनीय है किन्तु यह बात प्रतिरक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। हमारी सीमाओं पर चीनी पहले के अपेक्षा कहीं अधिक ताकत के साथ जमा हैं। पाकिस्तान तथा चीन में भारत के विरुद्ध आपस में सांठागांठ चल रही है। यह सब कुछ होते हुए भी प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हमारी सुरक्षा को जो खतरा है उसमें कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं हुआ है। वादविवाद के उत्तर के दौरान मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

यह सराहनीय बात है कि हमारी सेना में वृद्धि करके एक यथार्थवादी नीति का अनुसरण किया जा रहा है। किन्तु इसके साथ साथ हमें सेनाओं से सम्बद्ध और कई बातों पर ध्यान देना है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि संकेत देने वाले तथा इंजीनियरी उपकरणों की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है। अतः मेरा अनुरोध है कि रक्षा मंत्री को न केवल उपकरणों के बारे में अपितु सेना में इंजीनियरी अधिकारियों तथा संकेत सिगनल अधिकारियों की कमी की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतिवेदन में आगे यह कहा गया है कि सैनिक सेवाओं को आकर्षक बनाने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उनके लिए असैनिक सेवाओं में कुछ पद सुरक्षित किये जाते हैं। इससे असैनिक सेवाओं में असन्तोष की कुछ मात्रा उत्पन्न हो गयी है और स्वयं सैनिक पदाधिकारी भी सेना में रहते हुए दत्तचित्त होकर काम नहीं करते।

यह हर्ष की बात है कि जिन टैंकों को बनाया जा रहा है उन्हें शीघ्र ही सैनिक उपयोग के लिये भेजा जायगा और मोटरगाड़ियों को एक रूप दिया जा रहा है। इससे उनके रख-रखाव तथा मरम्मत सम्बन्धी खर्च कम हो जायेगा। जो सिद्धान्त बख्तरबन्द गाड़ियों के मामले में अपनाया गया है उसके बिल्कुल विपरीत वायुसेना में अपनाया गया है। हमारे पास 7 भिन्न भिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान हैं और हमें इनके रख-रखाव के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। विमान-चालकों को हर प्रकार के विमान-चालन में कार्यपटुता प्राप्त कराने में व्यर्थ समय बर्बाद होता है क्योंकि यदि कम प्रकार के विमान हों तो विमान-चालक कम समय में वही कार्यपटुता प्राप्त कर सकता है। हमारे देश की सीमा बहुत लम्बी है। हमें किसी आक्रमण अथवा आकाश से होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए केवल 45 ही दस्ते नहीं अपितु कहीं और अधिक दस्तों की आवश्यकता है। अतः हमें हर समय केवल

अपनी रक्षा करने के लिए ही नहीं अपितु आवश्यकता पड़ने पर अथवा किसी बाह्य शक्ति द्वारा आक्रमण किये जाने पर आक्रान्ता का मुकाबला करने और उसे क्षति पहुंचाने पर भी विचार करना चाहिए ।

भारत का सिद्धान्त शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का है । मैं इसका समर्थन करता हूँ । पाकिस्तान बार बार हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और उसकी इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं । चीन एक परमाणु बम का विस्फोट कर चुका है और दूसरा विस्फोट शीघ्र ही करने वाला है । इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे पास बममार विमान हों ताकि आवश्यकता पड़ने पर विनाशकारी हथियार निशाने पर छोड़े जा सकें ।

यह सराहनीय बात है कि हमने अपने देश में युद्धपोतों का निर्माण और उत्पादन का कार्यक्रम बना लिया है; आशा है कि वर्ष 1971 से पूर्व ही हम इनकी सेवाओं का उपयोग करने लगेंगे । यह भी अच्छा है कि प्रतिरक्षा मंत्री पनडुब्बी की प्राप्ति के मामले पर गम्भीर रूप से प्रयत्न कर रहे हैं । एकरूपता करने और खर्च बचाने की दृष्टि से पुराने विमानों से पिछा छुड़ाने के सिद्धान्त को कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि हमने असैनिक एयरलाईनों से डकोटा विमान ले लिये हैं ।

जब भूतपूर्व कर्मचारी असैनिकों के रूप में ए० ओ० सी० में शामिल होते हैं तो उन्हें निवृत्ति वेतन नहीं दिया जाता है । उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं दी जाती है जबकि असैनिक कर्मचारियों को केवल वही वेतन ही नहीं अपितु वार्षिक वेतन-वृद्धि भी दी जाती है । प्रतिरक्षा मंत्री को इस मामले पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): उपाध्यक्ष महोदय, चीनी आक्रमण के दौरान हमें अपनी सैनिक हार के कारण कटु अपमान सहन करना पड़ा था, इससे हमारी आंखें खुल गईं और उससे हमें यह शिक्षा मिली कि यदि हमें आत्म सम्मान करने वाले राष्ट्र के रूप में जीवित रहना है तो हमें अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना होगा, मुझे हर्ष है कि आज हमारी सरकार और देश दुश्मन की चुनौती का सामना करने और हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं ।

दो वर्ष की अवधि में हमारी सैनिक शक्ति लगभग दुगुनी हो गयी है । इसके लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा सैनिक-अधिकारी बधाई के पात्र हैं । यह प्रतिरक्षा मंत्रालय का सराहनीय कदम है कि उन्होंने नई स्थिति का सामना करने के लिए जवानों को प्रशिक्षण देने के समूची प्रशिक्षण प्रणाली का नवीकरण किया है । किन्तु मध्यम वर्ग और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि उन्हें व्यवहारिक रूप से युद्ध सम्बन्धी समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है । अतः सेना के व्यवहारिक प्रशिक्षण पर अधिक बल देना आवश्यक है । नेफा में हमारी हार हमारे वरिष्ठ आफिसरों तथा जनरलों में युद्ध सम्बन्धी कार्यपटुता का अभाव के कारण हुई है । क्योंकि उनमें युद्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण की कमी थी इस कारण वे जवानों पर अपेक्षित कमान भी नहीं कर सकते थे । अतः यह आवश्यक है कि हमें सेना को अपेक्षित प्रशिक्षण देने के मामले में खर्च को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये ।

सेना के लिए पदाधिकारियों की भर्ती का काम अब लगभग पूरा हो चुका है । वर्ष 1962 में इमर्जेंसी कमीशन में भर्ती किये गये लगभग 12,000 पदाधिकारी अभी पूर्णरूपेण प्रशिक्षित नहीं हुए हैं और वे नियमित कमीशन वाले अफसरों के स्तर से नीचे हैं, और उन अफसरों को अधिक संख्या में आपातकाल की समाप्ति पर सेना में नहीं रखा जायेगा, सरकार को उन्हें असैनिक कामों में लगाना

[श्री सुरेन्द्रपाल सिंह]

होगा। उस स्थिति में शॉर्ट सरविस रेगुलर कमीशन को जारी रखने के निश्चय का परिणाम यह होगा कि आवश्यक स्तर के नीचे के मामूली छोटे पदाधिकारियों की संख्या बढ़ती रहेगी और पुनर्वास की समस्याएं बाद में इतनी बढ़ जायेंगी कि शॉर्ट सरविस रेगुलर कमीशन की योजना को समाप्त कर देना ही अधिक अच्छा समझा जायेगा, हमें अल्प सेवा कमीशन देना बिलकुल बन्द करके स्थायी नियमित कमीशन द्वारा अफसरों की भर्ती की पुरानी प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक योग्य अफसर मिल सकें।

सरकार को उन अफसरों के लिए, जिन्हें आपात के बाद असैनिक-खण्ड में जाना पड़ेगा, सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायें इस बारे में अभी से एक निश्चित नीति बनानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 सेवाओं में कम से कम 50 प्रतिशत रिक्त स्थानों को उक्त पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

यह खेद की बात है कि हम अपने पंच वर्षीय प्रतिरक्षा योजना में स्थल सेना और वायु-सेना को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और नौ-सेना की ओर बिल्कुल कम ध्यान दे रहे हैं। नौ-सेना की आवश्यकताओं को और अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नौ-सेना बल किसी देश की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है किन्तु हमारी नौ-सेना अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है अतः यह आवश्यक है कि नौ-सेना की युद्ध शक्ति सर्वोच्च स्तर पर रखी जाये।

पुराने जहाजों को बदलने के निर्णय का स्वागत है। हमारे 50 प्रतिशत जहाज, 25 से 30 वर्ष पुराने हैं। वर्ष 1962 के बाद कोई भी नया जहाज नहीं खरीदा गया है। तीन युद्ध-पोत जो बनाये जाने वाले हैं, वे नौ-सेना में 1973 से पहले नहीं आ पायेंगे। वर्तमान गति से हम न तो जहाजों को बदलने का कार्यक्रम ही पूरा कर सकेंगे और न ही हम अपनी नौ-सेना की शक्ति को कायम रख सकेंगे।

नौ-सेना में जहाजों की कमी होने के परिणाम यह होगा कि हमारे अधिकतर नौ-सेना कैप्टनों को जहाजों की कमान करने का अवसर नहीं मिलेगा। समुद्री सेना अधिकारियों को नवीनतम परिस्थितियों से अवगत रखने के लिए यह आवश्यक है कि वे जहाजों की कमान करने का काम करें। अतएव उन्हें जहाज शीघ्र उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

हमारी नौ-सेना के पास, पनडुब्बियां भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से हमें पनडुब्बियां 1970 से पहले नहीं मिल सकती हैं। ऐसे समय में जब कि हिन्द महासागर तथा हमारे अन्य जल-प्रांगण में कई बेशिनाख्त पनडुब्बियां देखी जाती हैं; और हमारे शत्रु-देशों के पास कई पनडुब्बियां मौजूद हैं; हमारी देश की रक्षा के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो जाता है। अतः देश की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में पनडुब्बियां मौजूद हों।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): Mr. Deputy Speaker, Sir, it has been mentioned in the annual Report of the Ministry of Defence that we are maintaining good relations with our neighbouring countries. But the fact is that we are, of course, not in good terms with Chin and Pakistan. This is nothing but a self-praise only. At this juncture, it is our prime duty to defend our long borders. We need at least 5 million military personnel for our country. In view of the growing developments and flare-up on our borders, the Ministry

of Defence may be allocated larger funds in order to enable them to increase their strength to the extent the country needs. The Government may take effective steps to effect economy in other Ministries/Departments and close down certain unnecessary and useless Departments with a view to meet the increased demand of funds for the purpose. Efforts should also be made to raise the morale among military personnels.

The time also demands the manufacture of Atom Bomb, Government should revise its policy in this regard. The Report says that there is still shortage of military equipments to meet the requirements of our Defence Forces. Steps should also be taken to import extensive training to the newly commissioned Officers. Our soldiers have high morale. They have shown excellent gallantry at the time of Chinese aggression on our frontiers. They fought the aggressors valiantly. Government should also recognise their services and give them due regards.

Government should also not divulge any information regarding setting up and location of ordnance Depots in the country. I would also suggest that steps should be taken by Government to allot land to ex-soldiers all along our borders and provide them such jobs which may be useful for defence forces. They can cultivate land also.

We should introduce the use of Hindi to a greater extent in Defence Forces which will facilitate non-English knowing personnels. Government should also discourage the tendency among defence personnels of taking wine and meat. These may well be substituted by milk and Ghee.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने हमारी सैनिक समस्याओं के आर्थिक, राजनीतिक तथा युद्ध सम्बन्धी पहलुओं पर रोशनी डाली है। सेना के लोग प्रायः यह कहा करते हैं कि राजनीतिज्ञ उनके बारे में केवल आपत्ति के समय ही याद करते हैं अन्यथा नहीं।

हमारे देश में अभी तक सैनिकों तथा राजनीतिज्ञों के मिलाप का अनोखा ढंग है। अंग्रेजों के समय में तो सैनिकों को अलग जान बूझ कर रखते थे। परन्तु स्वतंत्रता के बाद यह जारी रखना ठीक नहीं। फिर भी मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष रक्षा मंत्री कुछ संसद् सदस्यों को पालम हवाई अड्डे पर ले गये और वहां हवाई शिक्षा का प्रदर्शन देखने का अवसर दिया। इस लिये अब सैनिकों को औरों से अलग नहीं रखा जावेगा।

वास्तव में सैनिकों के लिये कोई "लॉबी" नहीं है। ऐसी "लॉबी" श्रमिकों, उद्योगपतियों तथा किसानों के लिये तो हैं, परन्तु सैनिकों के लिये नहीं हैं। उसका एक कारण तो यह है कि सैनिकों पर कुछ नियंत्रण लगे हैं और वे राजनीतिज्ञों से नहीं मिल सकते हैं जैसे कि दूसरे वर्गों के लोग मिल सकते हैं। इसलिये संसद् सदस्यों का सैनिकों से उठ बैठ होनी चाहिये तथा सैनिकों की संसद् सदस्यों से। इस से एक दूसरे की समस्याओं का बोध होगा।

अब मैं मंत्रालय के प्रतिवेदन की ओर आती हूं। मेरा विचार यह है कि यह अच्छा होगा यदि प्रतिवेदन बनाने में रक्षा मंत्रालय तथा सैनिक मुख्यालय का सहयोग हो और वे दोनों मिलकर बनावें। यदि ऐसा होता तो इस से व्यापक ढंग से रक्षा मंत्रालय के कार्य का पता लगता।

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

एक बात अच्छी हो गई है कि अब पहले की भांति हर बात को यह कह कर नहीं छिपाया जाता कि यह जन्ता के हित में नहीं है। इस लिए यह प्रतिवेदन संसद सदस्य के लिये लाभदायक होगा।

सरकार को हम रक्षा के लिये रुपया देते हैं तो हमारा भी इतना अधिकार तो है कि वे यह बतावें कि उनके उद्देश्य क्या हैं।

इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि भारत तटस्थता की नीति पर चलता रहेगा। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि भारत आक्रमण न करने की नीति पर चलता रहेगा। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि यदि शत्रु हम पर आक्रमण करे तब भी हम उनका जवाब नहीं देंगे। क्या वे शत्रु के ओर देखें और उन पर गोली न चलावें। यह शान्ति के समय तो अच्छी नीति है। परन्तु क्या भारत अब शान्ति के समय से गुजर रहा है ?

मैं तो सीधी सी बात सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार का रक्षा सेना की ओर क्या राजपत्र (चार्टर) है तथा भारत के लोगों की ओर क्या राजपत्र है ? सरकार के उद्देश्य क्या हैं ? क्या वह सीमित युद्ध की तैयारी कर रही है अथवा सीमा पर थोड़े पैमाने पर लड़ाई अथवा विशाल स्तर पर सैनिक मुकाबले की तैयारी कर रही है ? क्या हम अब भी नारों के दास बने रहेंगे तथा आक्रमण न करने की बात कहते रहेंगे ? इस से किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस लिये इस प्रतिवेदन में यह सारी बातें आनी चाहियें।

जहां तक भेद की बातों का सम्बन्ध है, हमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु सरकार के उद्देश्य तो संसद तथा देश को पता होने चाहियें। इस प्रतिवेदन से तो यह पता चलता नहीं है। इस लिये रक्षा मंत्री सनिकों तथा देश को ऐसा राजपत्र दें।

श्री नाथ पाई (राजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय हम इस वर्ष रक्षा मंत्रालय की मांगों पर ऐसे समय चर्चा कर रहे हैं जब कि एक ओर तो चीन ने अणु बम्ब विस्फोट किया है तथा दूसरी ओर पाकिस्तान हमारे देशवासियों को डरा रहा है और इसने अभी हमारी 18000 वर्ग एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि यद्यपि श्री चव्हाण के पद ग्रहण के पश्चात् कुछ सैनिक मामलों में सुधार हुआ है, फिर भी यह इतना नहीं जितना होना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER in the Chair]

आज हमारे देश के ऊपर का आकाश भाग ऐसी स्थिति में है कि उस को जीता जा सकता है तथा हमारी नौसेना बहुत पुरानी है।

मैं तो यह चाहता हूँ कि सेना के तीनों सेनाओं की मांगों पर अलग अलग चर्चा हो।

हमारा देश एक निर्धन देश है। फिर भी हम जो रक्षा मंत्री चाहे उन्हें देने को तैयार हैं। परन्तु इसलिये हम जो भी रुपया सेना पर खर्च करते हैं उसका ठीक उपयोग होना चाहिये। आज हमारे देश की आय का 6 प्रतिशत तो सेना के बारे में व्यय होता है। हमारे निर्धन देश के लिये यह बहुत है। आस्ट्रेलिया अपनी आय का 3 प्रतिशत न्यूजीलैंड 2 प्रतिशत से भी कम तथा केनेडा लगभग 4 प्रतिशत सेना पर खर्च करता है। परन्तु इतना रुपया देने के बाद तो हमारी यह तसल्ली हो जावे कि इसका सदुपयोग हो रहा है। जब हम लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहां एक स्थान

पर 56 प्रतिशत रुपया ऐसा रहा जिसे प्रयोग ही नहीं किया गया। इसी प्रकार 1961-62, 1962-63 तथा 1963-64 के प्रतिवेदनों से पता चलता है कि हर वर्ष 21 करोड़, 28 करोड़ तथा 42 करोड़ रुपया बिना खर्च किये वापिस लौटा दिया। ऐसी ही बात लोक लेखा समिति की 1964 के प्रतिवेदन में कही गई है।

अब मैं दूसरी ओर आता हूँ। पिछले वर्ष 21 सितम्बर को रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी नीति तटस्थता की रहेगी। क्या रक्षा मंत्री को हर समय तटस्थता की चिन्ता लगी रहती है। मेरे विचार में तो हमारी रक्षा की नीति का आधार यह होना चाहिये कि हमें कहां से खतरा है न कि किसी और बात पर। मेरे विचार में तो तटस्थता एक साधन है दूसरे साधनों की तरह और वह साधन एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिये है कि यह देश स्वतंत्र रहे। बाकी दूसरी बातें इसके आधीन रहनी चाहियें।

मैं रक्षा मंत्री को इस बात पर बधाई दूंगा कि इस वर्ष उनके मंत्रालय की रिपोर्ट पहले वर्षों से अच्छी है। इससे हमें बहुत बातों का पता चलता है, यद्यपि अब भी कुछ बातें छुपाई गई हैं।

अब मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि पिछले दिनों सरकारी दल के एक सदस्य ने दूसरे सदन में यह कह दिया कि जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो कलकत्ता के समीप एक एयरक्राफ्ट केरियर लगाया गया था और सरकार की ओर से यह कहा गया कि यह सच नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या समाचार देना आवश्यक था? क्या आप सदा तटस्थता के कारण डरते रहेंगे? यदि जवाहर लाल नेहरू ने ऐसी कोई प्रार्थना कर भी दी थी तो इसमें क्या बुराई है, आखिर वह एक देश भक्त थे और उनका पहला कर्तव्य अपने देश की ओर था। हमारा पहला कर्तव्य अपने देश की स्वाधीनता बनाये रखना है। यद्यपि श्री चर्चिल का केवल उद्देश्य साम्यवाद को नष्ट करने का था, फिर भी उन्होंने स्टालिन से ऊपरी रूप से मैत्रीपूर्ण सम्बंध रखे।

क्या हमारी रक्षा नीति हमारे चीन अथवा पाकिस्तान के साथ झगड़े तक सीमित है, या हमने अपनी प्रतिरक्षा के लिये कोई दीर्घविधि नीति अपनाई है? ऐसी नीति के लिये दो बातें आवश्यक हैं : सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था और जनता का मनोबल और अनुशासन। देश को मनोबल, एकता, अनुशासन, आर्थिक सुव्यवस्था, नेतृत्व के सम्मिश्रण की आवश्यकता है। इसके साथ हमें ऐसे मित्र राष्ट्र भी चाहियें जिन पर हम निर्भर कर सकें।

हमें चीन के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा को जापान के सागर से आरम्भ करके अफगानिस्तान तक लानी चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हमारी उत्तरी सीमा पर दो शत्रु बैठे हैं और इन दोनों ने भारत को हानि पहुंचाने के लिये तथा उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिये आपस में मैत्री कर ली है। और वह शक्तिशाली भी हैं। यदि हमें चीन का सामना करना है तो यह आवश्यक है कि हम चीन को समझें तथा उसका अध्ययन करें। इसके लिये कैप्टेन की श्रेणी से ऊपर के सैनिक अधिकारियों के लिये युद्ध और युद्ध-नीति पर लिखी माओत्से तुंग की किताबों का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिये। माओत्से तुंग ने ऐडगर स्नो के साथ भेंट में कहा : 'मैं जानता हूँ कि श्री केनेडी युद्ध पर मेरी किताबों का अध्ययन किया करते थे। श्री केनेडी युद्ध और शांति के बारे में बहुत सतर्क थे।' माओत्से तुंग ने भी जनरल मैक्सवैल की गुरिल्ला युद्ध के बारे में किताबों का अध्ययन किया है।

[श्री नाथ पाई]

हम शांति चाहते हैं, लेकिन चाहने से शांति नहीं हो सकती। संसार के लेखबद्ध इतिहास में केवल 270 वर्ष ही शांति से बीते हैं। लेकिन शांति के लिये प्रयत्न करते हुये हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि संसार में युद्ध होते आये हैं। यदि यह ठीक है तो हमें क्या करना चाहिये? मैं मई, 1962 के टाइम्स आफ इण्डिया से एक समाचार आपको पढ़ कर सुनाता हूँ :

“हिमालय के दक्षिण की ओर सैन्य संचालन के लिये बहुत कठिनाइयां होने के बावजूद सीमा के किसी क्षेत्र में मुठभेड़ होने पर भारतीय सेना अच्छी तरह से सामना करने की स्थिति में है। भारत के सेना विशेषज्ञों को पूरा विश्वास है कि यदि चीनियों ने कोई आकस्मिक आक्रमण किया तो हम उनका मुकाबला कर सकेंगे। उनका यह भी विश्वास है कि शीघ्र ही घोर युद्ध होगा।”

परन्तु अब मुझे विश्वास है कि जो आश्वासन श्री चव्हाण दे रहे हैं वह अधिक यथार्थवादी हैं।

हमने जल सेवा को क्या कार्य सौंपा है? हमारे लगभग सभी पोत 22 वर्ष पुराने हैं। अच्छे पोत बहुत कम हैं। परन्तु 3,500 मील लम्बे समुद्र तट की रक्षा करने के लिये क्या वे काफी हैं? दूसरे, हम केवल ब्रिटेन की जल सेना से ही क्यों सहायता लेते हैं; हम अन्य देशों की जल-सेनाओं से भी सहायता ले सकते हैं? हमें ब्रिटेन की जल सेना के पुराने और प्रयोग में लाये गये जहाजों को नहीं लेना चाहिये।

श्री दांडेकर ने बताया कि हमारी वायु सेना के पास छः प्रकार के विमान हैं; हमारे पास न केवल छः प्रकार के विमान हैं बल्कि छः प्रकार के हेलीकोप्टर भी हैं। परन्तु यह विभिन्नता हमारे लिये लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। हमें बताया गया है कि हमारी वायु सेना में केवल 45 स्क्वार्डन हैं। यह हमारी सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है। जब दो वर्ष में मिग विमान का उत्पादन आरम्भ होगा तो यह भी गत प्रयोग हो जायेगा क्योंकि वायु सेना के विमानों के मामलों में बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है। हमें किसी से भी सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिये यदि वह हमारी आवश्यकता के अनुसार हो।

हमने जो एच० एफ०-24 विमान बनाया है, उस का इंजन रूसी है और राडार पश्चिमी देशों का है। हमने विमान बनाने में भी तटस्थता दिखाई है, परन्तु ऐसा विमान उड़ नहीं सकता।

हमारी प्रतिरक्षा शक्ति इतनी होनी चाहिये कि न केवल हम आक्रमण करने वाले को परास्त कर सकें बल्कि इस शक्ति को देख कर कोई हम पर आक्रमण करने का साहस ही न कर सके।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : मैं उन सब मंत्रियों तथा अधिकारियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने देश की प्रतिरक्षा की वृद्धि के लिये तन मन से सेवा की है।

राजापुर से एक माननीय सदस्य ने चीन द्वारा अणु बम के विस्फोट उत्पन्न स्थिति का निर्देशन किया। इस अणु बम के विस्फोट से चीन विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के बराबर पहुंच गया है। और उस के सीमावर्ती देशों के लिये आतंक का विषय बन गया है।

यह सच है कि अणु बम गिराने के साधन चीन के पास नहीं हैं और इन्हें बनाने में चीन को कई वर्ष लग जायेंगे। परन्तु हम उस धारणा के सहारे नहीं रह सकते कि चीन अणु बम गिराने के साधन नहीं बनायेगा अथवा मानवता के नाते हम पर नहीं गिरायेगा। हम इस अनुमान के सहारे भी नहीं रह सकते कि वह हम पर दया कर के अथवा विश्व के लोक मत को ध्यान में रखते हुए हम पर बम नहीं गिरायेगा।

हमारे पास और क्या विकल्प हैं ? हम किसी के साथ सैनिक समझौता कर लें, परन्तु यह हमें नष्ट होने से नहीं बचा सकती। हम संयुक्त राष्ट्र और अणु शस्त्रों वाले राष्ट्रों से ऐसे राष्ट्रों के विरुद्ध, जिन के पास अणु शस्त्र नहीं हैं, अणु शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के लिये संयुक्त गारंटी की मांग कर सकते थे, और यही हम ने किया है। हम अपने आणविक शस्त्र भी बना सकते थे और उनको गिराने के लिये साधन भी बना सकते थे, परन्तु यह सर्वविदित है कि हमारे पास इतना धन नहीं कि हम यह सब कर सकते। अतः इस मामले में सरकार ने बहुत ही समझदारी का निर्णय लिया और संयुक्त गारंटी से ही हमें वो सुरक्षा मिल सकती है जिस की हमें आवश्यकता थी।

मैं इस से सहमत हूँ कि किसी भी सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य देश की रक्षा करना है, चाहे वो आणविक शस्त्रों से करे अथवा राजनीति से। और यदि आप देश की रक्षा करना चाहते हैं तो आप को प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं का पूर्वनिर्माण लगाना चाहिये।

मैं एक माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूँ कि हमें दीर्घावधि युद्ध नीति अपनानी चाहिये। इसके लिये हमें चीन की युद्ध नीति तथा उद्देश्यों का पता होना चाहिये।

आजकल युद्ध केवल किसी देश पर कब्जा करने के लिये नहीं किया जाता। चीन का युद्ध करने का उद्देश्य अपनी विचारधारा को फैलाना है और अन्य देशों को अपने राजनैतिक दबाव में लाना है। राजापुर से एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हमें माओत्से तुंग की किताबों का अध्ययन करना चाहिये। मैंने उसकी किताबें पढ़ी हैं। इनमें उसने सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये सीमित युद्ध के लिये कहा है; इससे न तो युद्ध के क्षेत्र में विस्तार होने का खतरा है क्योंकि यदि विरोधी राष्ट्र अधिक शक्तिशाली है तो वो युद्ध को बढ़ाने का दायित्व अपने ऊपर कभी नहीं लेगा, और चीन अपने चुने हुए स्थल पर युद्ध कर सकता है और जितना समय चाहे कर सकता है। चीन का मुकाबला तभी किया जा सकता है यदि हम भी ऐसी नीति अपनायें जो माओत्से तुंग के तौर तरीके को काट सके। अब क्योंकि हम भी चीन के आक्रमण के शिकार हैं इसलिये हमें इस नीति को कि पहले कब्जा करो फिर बातचीत करो, भली प्रकार समझ लेना चाहिये। चीनी सैनिकों को जिस प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है उसके लिये हमारा सीमा क्षेत्र बहुत उपयुक्त है। क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान में सांठ-गांठ हो गई है, इसलिये अब दोनों देश हमारे उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अतिक्रमण करने का प्रयत्न करेंगे। इनका प्रयत्न यह होगा कि इन क्षेत्रों की नाकेबन्दी की जाय जिससे इन क्षेत्रों को किसी प्रकार की सहायता न पहुंचे।

अब चीन ने गुरिल्ला प्रशिक्षण के लिये पाकिस्तान में अड्डे स्थापित किये हैं। यदि आप आसाम का मानचित्र देखें तो आप पायेंगे कि चीन के लिये ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे से घुसना और पाकिस्तान के लिये ब्रह्मपुत्र के दक्षिण किनारे के प्रदेश में घुसना बहुत आसान है। यह स्पष्ट है कि सरकार पहाड़ी लड़ाई के लिये अपनी सेना को प्रशिक्षण दे रही है। परन्तु चीन का सामना करने के लिये हमें कुछ राजनैतिक दाव-पेंच भी लड़ाने पड़ेंगे।

हमें पहल करने का अधिकार शत्रु को ही नहीं दे देना चाहिये। हमें शत्रु द्वारा चुने हुए क्षेत्र में ही युद्ध नहीं करना चाहिये। हमें शत्रु पर प्रत्याक्रमण करना चाहिये और उसकी सप्लाई लाइन को तोड़ना चाहिये।

हमें गुरिल्ला अतिक्रमणों का सामना करने के लिये भी तैयारी करनी चाहिये। हमारे सीमान्त में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां के निवासियों की शकल सूरत चीनियों से मिलती है। ऐसे क्षेत्रों में चीनी

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

गुरिल्ला सैनिकों का सामना करना बहुत कठिन है। हमें इस समस्या की ओर तत्कालिक ध्यान देना चाहिये।

हमें सीमित युद्ध के लिये आवश्यक हथियारों, प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिये। हमें छत्रीधारियों को प्रशिक्षण देने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

इस सीमित समय में जासूसी की आवश्यकता के बारे में अधिक नहीं कह सकता। हमें अपनी वायु सीमा की रक्षा की ओर भी तुरन्त ध्यान देना चाहिये। हमें राडर और ऐसे अस्त्र बनाने की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये जो हमारी वायु सीमा की रक्षा कर सकें।

श्री बृजराज सिंह (कोटा झालावाड़) : हमें आज दो आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ रहा है। वे हैं चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो अमरीका से प्रोत्साहन मिल रहा है। चीन के मुकाबले में हमें तैयारी करनी है। इसके लिये हमें अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों के लिये सोचना होगा। अल्पावधि के लिये तो हमें अपने युद्ध के हथियारों तथा सेना में वृद्धि करनी होगी। हमें चीन को एक अणुशक्ति समझना है। इस ओर भी ध्यान देना है। मैं जानना चाहता हूँ क्या हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस बारे में सोचा है ?

एक अणु बम छोड़ने के लिये विशेष मशीनरी की आवश्यकता होती है। चीन अभी तक उस को तैयार नहीं कर पाया है। हां, उस ने अणु विस्फोट अवश्य किया है। आज हम प्रतिरक्षा की व्यवस्था पर बहुत धन व्यय कर रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार करते रहे तो ऐसी स्थिति आ जायेगी कि हमें अणु शक्ति वाले हथियार बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा।

आज युद्ध में संचार व्यवस्था का बहुत महत्व है। इस ओर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। हमें अपनी प्रतिरक्षा सेवाओं को एक ही प्रतिरक्षा अधिकारी वर्ग के अधीन लाना चाहिये जैसे कि ब्रिटन में है। इस आशय की सिफारिश प्राक्कलन समिति ने भी की थी।

वायु सेना को शक्तिशाली बनाने के बारे में शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है। वायुसेना एक तो आक्रमणकारी विमानों के रोकने का काम करती है और दूसरे स्थल सेना की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त युद्ध क्षेत्रों में रसद पहुंचाने का काम भी होता है। आज जब चीन ने अणु शक्ति वाले हथियार बना लिये हैं तो यह आवश्यक है कि हम भी यह सोचें कि क्या हमें भी अपनी सुरक्षा सेनाओं को अणु शक्ति वाले हथियारों से लैस करना है अथवा नहीं। हमारे पड़ोसी देशों के पास तीव्र गति वाले सुपरसोनिक विमान हैं। हमारे पास ये अपर्याप्त मात्रा में हैं। यह ठीक है कि हम मिग विमान का निर्माण करने जा रहे हैं परन्तु यह रोकने का काम ही अच्छा कर सकता है। हमारे पास भूमि से उड़ कर हमला करने वाला विमान नहीं है। हमें एफ-5 फ्रीडम फाइटर टाइप का विमान ले लेना चाहिये। हमें चीन की सेनाओं की अधिक संख्या से डरना नहीं चाहिये। उस को और भी कई दायित्व पूरे करने हैं। हमने बंगलौर तथा कानपुर के कारखानों को एक सार्वजनिक समवाय के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यह अच्छा किया गया है। अब इस कार्य में समन्वय रहेगा। इस उपक्रम को अधिक अधिकार दिये जायें। हम संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हुए समझौते के परिणामों की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि ईशापुर फैक्ट्री में अपने आप भरी जाने वाली राइफलें बन रही हैं। परन्तु ये बहुत भारी हैं। पहाड़ों पर

ले जाना कुछ कठिन है। इस लिये कोई हलकी राइफल बनाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। एक ब्रह्मिष्ठ कहावत है कि यदि शान्ति चाहते हो तो युद्ध के लिये तैयार रहो। हमें इस को ध्यान में रखना चाहिये।

श्री शिंदरे (मरमागोआ) : प्रतिरक्षा मंत्री को मंत्रिमंडल में सातवां या आठवां दर्जा दिया गया है। आपात काल में ऐसा होना बहुत आश्चर्यजनक मालूम होता है। सूचना और प्रसारण मंत्री से भी इन का स्थान नीचे है। आज की स्थिति को देखते हुए मालूम होता है कि सरकार असफल रही है। इस के लिये मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराता और न ही प्रतिरक्षा मंत्री श्री चव्हाण इस के जिम्मेदार हैं। जब सरकार इस मंत्रालय को ही महत्व नहीं देती तो आज जैसी स्थिति ही होगी। आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में एक बहुत अच्छा लेख छपा है। इस में ब्रिटेन के एक भूतपूर्व खाद्य मंत्री की बात को दोहराया गया है। इस में कहा गया है कि यदि 1930 की मुख्य समस्याएं आर्थिक थीं तो 1960 के पश्चात की समस्यायें रक्षा से सम्बन्ध रखती हैं। और वह हाल ही में भारत से ही कर गये हैं। आज हमारे देश के सामने बहुत सी समस्यायें हैं। मैं समझ नहीं सकता कि क्या सरकार इन समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिये पाकिस्तान और चीन की बात करती है और अपनी असफलताओं पर पर्दा डालती है। पाकिस्तान सरकार तो यह बात आरम्भ से ही कर रही है। मेरे विचार में तो जब तक हम अपने देश की आन्तरिक समस्याओं का समाधान नहीं करते यह बाह्य झगड़े चलते ही रहेंगे। श्री वीवेन बोस, जो एक विख्यात न्यायाधीश हैं, ने लिखा है कि राष्ट्रों के बीच स्थायी शान्ति तभी हो सकता है जब वहां के समुदाय शान्ति से रहते हों। सरकार हमें समय समय पर पाकिस्तान तथा चीन द्वारा दी जाने वाली धमकियों से डराती रहती है ताकि हम न्याय की मांग न करें। मैंने इस चर्चा के समय बहुत से माननीय सदस्यों को सुना है। श्री जोकीम आल्वा ने सरकार की बहुत सरहाना की है। इस के साथ साथ उन्होंने ने सेना में सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने की मांग भी की है। मैं समझ नहीं सकता कि हम इस सम्बन्ध में और खर्चा कैसे बढ़ाश कर सकेंगे। पहले ही हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति इतनी संतोषजनक नहीं है। हमें देश की सुरक्षा की ओर ध्यान देना है परन्तु अपनी परिस्थितियों को देख कर। सुरक्षा वास्तव में ही सब से प्रथम आती है। एक देश की विदेश नीति और प्रतिरक्षा नियोजन का बहुत निकट का सम्बन्ध है। अब तक हमारे देश की इन नीति में समन्वय नहीं रहा है। ये तो व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होती रही हैं। देश के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। और बात कहने से पूर्व मैं यह कहूंगा कि आज सैनिक मामलों में जो सुधार दिखाई देता है उसका श्रेय इस समय के रक्षा मंत्री तथा सेना के मुख्यों को मिलना चाहिये। यह विचार मैं अपने व्यक्तिगत रूप से व्यक्त कर रहा हूँ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[MR DEPUTY SPEAKER in the Chair]

भारत की आधुनिक सेना का निर्माण अंग्रेजों ने किया। परन्तु उन्होंने इसे जो प्रशिक्षण आदि दिया वह केवल अपने कार्य-सिद्ध के लिये दिया। अंग्रेजों ने भारत में एक आधुनिक

[श्री इकबाल सिंह]

ढंग की सेना बनाई। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत की उस सेना से यह था कि उन्हें मध्यपूर्व चीन तथा जापान के क्षेत्रों में एक ऐसा स्थान उनके अधिकार में हो जहां वे अपने शत्रु को निष्फल बना सकते थे। यह बात उस तार से भी सिद्ध हो सकती है जो लार्ड वेवल ने इस समय की इंग्लैंड के युद्ध कालीन मंत्रिमण्डल को भेजा और जिसमें उससे पूछा कि वे भारत तथा लंका को बचाना चाहते हैं अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाजन के पश्चात् भारत को दो-तिहाई तथा पकिस्तान को एक तिहाई सेना मिली। भारत की सेना की लड़ाई की बड़ी क्षमता थी परन्तु हमने इसकी उपेक्षा की और इस का फल हमें 1962 में भोगना पड़ा।

1962 के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री ने स्वयं कहा है कि हमें जो हानि उठानी पड़ी उसका कारण हमारे घटिया शस्त्र, घटिया संगठन तथा प्रशिक्षण तथा हमारे कमांडरों की कम-क्षमता और घटिया सैनिक गुप्तवार्ता विभाग था। 1962 के पश्चात् सेना में बड़ा सुधार हुआ है।

अब चीन तथा पाकिस्तान में मैत्री है। 1963 के पश्चात् चीन क्यों चुप रहा, इसका कारण शायद यह है कि उसे अपनी सेना से रूस, कोरिया, फारमोसा, वियतनाम तथा भारत की सीमाओं पर लगाना पड़ा।

हम अपनी फौज को बढ़ाते जा रहे हैं और 1969 तक इसमें 21 डिविजन हो जायेंगे। यह पर्याप्त होगी अथवा नहीं, यह मुझे पता नहीं।

आजकल यह बहुत अधिक महत्व की बात नहीं कि किसी सेना की संख्या कितनी है अपितु यह महत्वपूर्ण है कि वह किस प्रकार की है, अर्थात् संख्या की तुलना में उसकी युद्ध क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है।

अपने दौरे के पश्चात् प्रतिरक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया वह अच्छा है परन्तु उस में भारी बम्बरों, भारी टैंकों, राकेटों तथा अन्य चीजों का कोई उल्लेख नहीं है। आजकल इन्हीं शास्त्रों की लड़ाई में अधिक आवश्यकता है। इनकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

हमारा दूसरा शत्रु पाकिस्तान है जिसने हमारे लिये स्थान स्थान पर कठिनाई खड़ी कर दी है जैसे कच्छ, काश्मीर, कूचबिहार तथा आसाम की सीमा पर। ऐसे ही चीन ने हमारे लिये आपत्तिजनक स्थिति पैदा कर दी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिये ऊपर बताये हुये शस्त्रों का बहुत महत्व है। यदि पाकिस्तान और चीन में से हम ने एक की भी उपेक्षा की तो हमारे लिये खतरनाक होगा।

अब मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आता हूँ और वह यह है कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय ने राकेट तथा मिसाइलों की भी उपेक्षा की हुई है। यह मैं कह चुका हूँ कि यह भविष्य के शस्त्र हैं। और यदि हम ने इनका निर्माण नहीं किया तो हम गलती करेंगे।

हम ने इस देश में 5000 शक्तिमान ट्रक, 8000 निसान ट्रक तथा 3700 जीपों का उत्पादन किया है। क्या इस सामान से हमारी सेना को उतनी गतिशीलता मिल सकती है जितनी इसे आवश्यक है।

अब मैं जे०सी०ओ० तथा एन०सी०ओ० की ओर आता हूँ और पूछता हूँ कि हमारी सेना में इतने दर्जे रखने की क्या आवश्यकता है । दुःख की बात है कि एक श्रमिक के वेतन में तो प्रति वर्ष वृद्धि होती है परन्तु सेना के हवलदार तथा सूबेदार के वेतनों में कोई वृद्धि वार्षिक नहीं होती है । ऐसे ही जमादार के वेतन में केवल तीन वार्षिक वृद्धियाँ हैं । यह बात याद रखनी चाहिये कि नेफा तथा लद्दाख की लड़ाइयों में इन्हीं लोगों ने अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से निभाया । इसलिये इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, I cannot say that there can be any defect in the work of Defence Minister Shri Y. B. Chavan or the Deputy Minister, Dr. Raju. They have served the country but the party to which they belong *i.e.* the Congress party and the Congress Government have got a history of defeat. It has lost 38,000 square miles of its territory to Pakistan. A small number of Nagaas have proved much troublesome to them. If they want to preserve the independence of the country, they will have to rise above superstitions from which they are suffering for the last some years.

The greatest need of the hour is to establish our posts in those areas which have been vacated by China. We do not have our soldiers on Thagla Ridge. The fact is that it is not in our occupation at all.

We have not so far given appropriate punishment to the traitors of the country who supplied our maps and other secrets to the enemy. Mr. Sharma who was a pilot in the Indian Air Force and who gave our secrets to Pakistan and obtained money for so doing has been given a punishment of only 7 years. He also disclosed that there was complicity in his work of many high officials. Unless and until such traitors are shot dead, these problem would not be solved.

All adults, children and even girl should be given military training.

The government should stop crying most that they would defend the country. If they are so serious in so saying, they will have to be in possession of nuclear weapons. Nuclear weapons are as important to the army these days, as a bridegroom to the marriage party and a speaker to the Parliament. We should think over these seriously. Only those survive who have the backing of a good army and of defendable friend. Even the world opinion is against India. China has got nuclear weapons and India has not got them. When government asks for guarantees, it means sheer beggary before the enemy. The government will not be able to defend the country.

The government has failed even in character building of the nation. The Government is engaged only in doing of three things *viz.*, Panchsheel, Peaceful living and Non-alignment. But it should be the duty of the government to protect the country and to build character of the people. But the Congress Government has failed in these things. The problems which can be solved with sword are being tried to be solved by the means of talk by this government. But this cannot be solved by talks.

It is a very sad commentary on the working of the Ministry of Defence that they have returned to the Exchequer Rs. 68 crores as unutilized.

[Shri Yashpal Singh]

On the one hand we find that army is not getting engineers to solve these and on the other hand we find many engineers jobless.

The train which carried army personnel from Kotdwar to Calcutta was kitchenless and created much discomfiture to the army personnel there. It also reached late by 48 hours.

The government should give military training to the people and throw away Panchsheel if it want to defend the country.

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि): प्रतिरक्षा मंत्रालय ने सीमा पर सड़क बनाने के कार्य को बहुत सुधारा है । मुझे प्रसन्नता है कि रक्षा मंत्री ने स्वयं इसमें रुचि ली है और आज देश तथा संसद् को यह विश्वास हो गया है कि हमारी सेना कम से कम अच्छे संचार साधनों के कारण घाटे में नहीं रहेगी ।

हम उन सब देशों के लिए आभारी हैं जिन्होंने हमें सहायता दी है ।

हमें एक बात तो याद रखनी चाहिये वह यह है कि हमारे सैनिकों पर सामग्री से अधिक उन भाषणों का प्रभाव पड़ेगा जो उन के बारे में यहां हो रहे हैं ।

अमरीका वालों की यह स्थिति है कि एक बार तो वह हमें वायु सेना के लिये अच्छे शस्त्र देने की बात कहते हैं और फिर एक दम बदल जाते हैं और कहते हैं कि हमें केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिये ।

हमारे देश की चीन और भारत के युद्ध में बुरी हार हुई है । आज हमारे विरुद्ध जो बातें चीन चाहता है वह पाकिस्तान कर रहा है ।

मैं अब कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं । एक तो यह कि मेरी सूचना के अनुसार जो शस्त्र पाकिस्तान को अमरीका तथा ब्रिटेन ने दिया है उसे वह किसी को बतावेंगे नहीं । परन्तु उन्होंने जो शस्त्र हमें दिये हैं उन के भेद उन के आपसी समझौते के अनुसार वे पाकिस्तान को दे देते हैं । मैं ने सुना है कि उन देशों के जो सैनिक अफसर उन के दूतावासों में रहते हैं वे तो यहां उन की जांच करने का भी अधिकार है । यदि ऐसा है तो यह हमारे लिये बहुत लज्जा की बात है ।

मेरे मित्र श्री दांडेकर ने उन वायुयानों का उल्लेख किया जिनका इस देश में उत्पादन होता है । परन्तु मैं उन्हें यह बता दूँ कि हमारे लिये दूसरों के दान दिये शस्त्रों से अपने बनाये शस्त्रों पर अधिक भरोसा रखना अधिक लाभदायक है । हमें अपने उत्पादन पर गर्व भी करना चाहिये ।

वास्तव में मिग विमान बहुत प्रभावशाली हैं । चीन के पास मिग—17 विमान हैं । अभी इस बात का पता लगाना है कि क्या चीन ने मिग—19 और मिग—21 विमानों का निर्माण आरंभ कर लिया है । मैं समझता हूँ कि हमें अपने देश में मिग—17 विमानों के स्थान पर मिग—21 विमानों का निर्माण करना चाहिए ।

हमारे देशवासियों में देश भक्ति की भावना है । वे न केवल सुविधाओं तथा वेतन के लिए ही अपितु देश की रक्षा की भावना से सेना में भर्ती होते हैं । इसका

प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हमारे जवानों ने गत चीनी आक्रमण के समय वीरता से चीनी सेनाओं का सामना किया। उस समय हमारी असफलता के अनेक कारण थे। जिन्हें मंत्रालय दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सेनाओं को आवश्यक हथियार तथा सुविधायें दिये जाने पर वे किसी भी दुश्मन का सफलता से मुकाबला कर सकती हैं। किन्तु अभी हमारे सैनिक सेवाओं को आकर्षित बनाने के लिए इन में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। सेवा-निवृत्त सैनिक अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन पर आयकर नहीं लिया जाना चाहिये। सैनिकों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं नियमित रूप से दी जानी चाहिए। ब्रिटेन की तरह सैनिक अधिकारियों के बच्चों को स्कूलों और कालिजों में छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। जब तक उन के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक समस्या पूरी तरह हल नहीं हो पायेगी।

पेंशन के सम्बन्ध में भी असैनिक कर्मचारियों तथा सैनिक कर्मचारियों के बीच भी भेद-भाव किया जाता है। उदाहरणार्थ सभी श्रेणी के सैनिक कर्मचारियों की पेंशन के लिए उन की सेवा की पूरी अवधि का हिसाब लगाया जाता है जबकि वायु सेना के कर्मचारियों का केवल आधा सेवा काल गिना जाता है। इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए।

यह उचित नहीं है कि हमारे प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक अधिकारी आयुध कारखानों तथा आयुध डिपों जैसे संस्थानों में काम करें। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी सेवाओं का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय अनुभव असैनिक अधिकारियों को आयुध कारखानों तथा डिपों का कार्यभार सौंप दें। इससे प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी अधिक उपयुक्त सेवाओं पर कार्य कर सकेंगे। मेरा प्रतिरक्षा मंत्री से यह भी अनुरोध है कि वह आयुध कारखानों में कार्य करने वाले असैनिक कर्मचारियों की शिकायतों की ओर ध्यान दें। उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक अलग एकक स्थापित किया जाना चाहिए जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके।

मुझे आशा है कि प्रतिरक्षा मंत्री मेरे द्वारा उठाई गई बातों पर विचार करेंगे।

प्रति रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं, चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का आभारी हूँ। सदस्यों द्वारा प्रकट किये गये विचारों से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि गत दो वर्षों से चर्चा रचनात्मक तथा वास्तविक होती जा रही है।

सदस्यों द्वारा कई बातें उठाई गई हैं किन्तु मैं आलोचना के मुख्य तर्कों का ही उत्तर दूंगा। मैं समझता हूँ कि 1962 में चीनी आक्रमण के बाद हमारे देश के जीवन में एक नये युग का आरंभ हुआ है। चीनी आक्रमण हमारे लिए एक भारी वक़्का था क्योंकि हमें चीन द्वारा इस प्रकार आक्रमण किये जाने की आशा नहीं थी। मुझे विश्वास है कि हम अब अधिक प्रभावकारी रूप से अपना कार्य कर रहे हैं।

मैं उन माननीय सदस्य के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ जिन्होंने युद्ध नीति के बारे में एक विशेषज्ञ द्वारा लिखे गये लेख का उल्लेख किया है। सुरक्षा की समस्याओं के

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

महत्व के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा में भी परिवर्तन हो रहा है। आज विभिन्न देशों में सुरक्षा की समस्याओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है। यह बात हमारे देश के लिए अधिक सच साबित होती है। मैं समझता हूँ कि कम से कम आगामी दस वर्षों में हमें देश की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। इससे मेरा अभिप्रायः यह नहीं है कि अन्य आर्थिक विकास के कार्यों की उपेक्षा की जायेगी। विकास के कार्य भी साथ साथ होते रहेंगे।

माननीय सदस्य श्री नाथपाई ने सरकार द्वारा प्रतिरक्षा पर किये जाने वाले व्यय की तुलना आस्ट्रेलिया और कनाडा में प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय के साथ की है। माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन देशों की तथा हमारे देश की परिस्थितियों में बहुत अधिक अन्तर है। हम इसको तुलना अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा प्रतिरक्षा पर किये जाने वाले व्यय के प्रतिशत से कर सकते हैं।

चीन आक्रमण करके हमारे आर्थिक विकास को अस्तव्यस्त करना चाहता था। अतः उसने आक्रमण करके भारत को चुनौती दी। हमारे देश ने चीन की चुनौती को अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण से स्वीकार किया है। मुझे इस बात का गर्व है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर पिछले तीन वर्षों में किसी ने भी प्रतिरक्षा व्यय की स्वीकृति देने पर आपत्ति नहीं की। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि समचे देश ने चीन की चुनौती को एक होकर स्वीकार किया है तथा प्रतिरक्षा की तैयारी पर अधिक से अधिक व्यय करने का फैसला किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि स्थिति पूर्णतः ठीक है किन्तु यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि पिछले दो वर्षों में हमने शान्तिपूर्वक जो तैयारी की है उससे प्रतिरक्षा सेवाओं में तथा जनता में यह विश्वास पैदा हो गया है कि वे किसी भी विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा कर सकते हैं।

आज हमें चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सम्बन्धों के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे से लाभ उठाने को चाल चल रहे हैं। इसमें कौन अधिक सफल रहेगा अभी नहीं कहा जा सकेगा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे देश में हो रही प्रतिरक्षा की तैयारी का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह चीनी खतरे का सामना करने के लिए कर रहे हैं। इस के साथ ही हम चीन के साथ पाकिस्तान के बढ़ रहे सम्बन्धों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

पिछला वर्ष, अर्थात्, 1964 हमारे लिए महत्व का वर्ष रहा क्योंकि हमने उस अवधि में देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी योजनाएं तैयार की। हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए कम से कम दस वर्ष आगे के लिए तैयारी करनी होगी। अतः हमने यह निर्णय किया है सेनाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण किया जाये। हमने नौसेना की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिया है।

अब मैं वायुसेना के बारे में कुछ कहूँगा। श्री नाथपाई ने कहा है कि हमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रत्येक उपलब्ध साधन से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। हमारा तटस्थता

की नीति अपनाने का तात्पर्य यही है कि हम जहां से चाहें सहायता लें। यदि हम किसी गुट में शामिल हो जाते हैं। तो हमारी यह स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। हम नहीं चाहते कि इस मामले में हम किसी के सिद्धांत अथवा दृष्टिकोण का अनुसरण करें। मैं यह बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हम किसी के राजनीतिक प्रभाव में रह कर काम करना नहीं चाहते।

एक माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किए हैं कि यदि हम संधि करके किसी गुट में शामिल हो जायें तो संभवतः हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयारी नहीं करना पड़ेगी। इस प्रकार की बात मान लेना हमारे लिए अत्यन्त दुर्भाग्य की बात होगी। किसी गुट में शामिल होकर स्वयं तैयारी न करना देश के लिए बतारनाक बात है। माननीय सदस्य मेरे विचार से अवश्य सहमत होंगे कि प्रतिरक्षा के लिए तैयारी करना एक प्रकार से स्वयं की प्रत्येक कार्य के लिए तैयार करना है। हम में इस से अंतविश्वास उत्पन्न होता है। अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख कर ही हम गुटों से अलग रहने की नीति तथा विश्व शान्ति की बात कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने हमारी वायु सेना के लिए विभिन्न देशों से विमानों के विभिन्न पुर्जे तथा भाग मंगाने का उपहास किया है, उनके विचार में ऐसा करना उचित नहीं है। आज कम से कम तकनीकी विकास के क्षेत्र में केवल अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं अपितु महाद्वीपों में भी आपस में सम्बन्ध स्थापित होते हैं। आज प्रविधिकी इतनी विकसित ही चुकी है कि 'बोइंग' विमान के इंजन तो ब्रिटेन में बनते हैं और उनके पुर्जे तथा ढांचे अमरीका में बनते हैं। अतः मैं समझता हूं कि इसमें उपहास अथवा लज्जा की कोई बात नहीं है। हम 'एच एफ 24' में मेक 11 की क्षमता के विकास का अनुमान लगाने के लिए मिश्र में बने हुए इंजन का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि हमें राष्ट्र को देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक ढंग से तैयार करना है तो हमें गलत धारणाओं का परित्याग करना होगा।

माननीय सदस्य श्री दांडेकर ने इस बात की आलोचना की है कि भारतीय वायुसेना के पास अनेक प्रकार के मशनों वाले विमान हैं। मैं माननीय सदस्य से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय वायुसेना को विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं यही कारण है कि इनके मशनों उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहले हम अपनी इच्छानुसार विमान नहीं मंगा सकते थे। यह विमान देने वाले देशों पर निर्भर रहता था।

मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि विभिन्न प्रकार के विमानों का मानकीकरण किया जाये ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरह हो सके। किन्तु हम विमानों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करने के लिए उन्हें नहीं मंगा रहे हैं। हम केवल पुराने विमानों के स्थान पर नये विमानों का उपयोग करने के लिए ही नये विमान अमरीका आदि देशों से मंगा रहे हैं। जहां तक विमानों के मानकीकरण का सम्बन्ध है, यह तभी संभव हो सकता है जब हम स्वयं अपने देश में विमानों का निर्माण करने लगेंगे। जब तक हमें आधुनिक हथियारों तथा विमानों को प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा तब तक हम अपनी वायु सेना का आकार तथा संगठन के बारे में पूर्णतः अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकते।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

यह सर्वविदित है कि 'मिग' विमान आधुनिकतम विमान है। इन विमानों के बारे में श्री दांडेकर की शंका दूर कर देना चाहता हूँ। इनका निर्माण कार्यक्रम वास्तविकता के आधार पर तैयार किया है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि इनका निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

श्री दांडेकर ने इस बात का भी उपहास किया है रूस द्वारा दिए जाने वाले 'मिग' विमानों को भारत पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है। माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिए कि 'मिग' विमानों की तीन टुकड़ियों के संभरण के लिए अक्टूबर 1964 में रूस सरकार से करार किया गया था। करार के अनुसार विमान इस वर्ष के अन्त तक भारत पहुंचने हैं। आशा है कि इस अवधि के अन्दर ही विमान भारत पहुंच जायेंगे। अतः माननीय सदस्य को इस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।

माननीय सदस्य ने पांच छः प्रकार के हेलीकोप्टरों के बारे में भी आपत्ति की है। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ किस्मों के हेलीकोप्टर हैं किन्तु उनमें से कुछ प्रयोग किये जा सकने की स्थिति में नहीं हैं। वास्तव में हमारे पास इस समय केवल दो प्रकार के हेलीकोप्टर हैं।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें अपनी वायुसेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम इसके लिए पूर्णतः प्रयत्नशील हैं तथा इस मामले में हमारे मित्रराष्ट्र हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। विदेशों से सहायता प्राप्त करने के साथ साथ हमें अपने देश में ही विमानों का निर्माण करने के अपने उत्तरदायित्व को नहीं भूलना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि इसमें समय लगेगा क्योंकि हम अभी इस क्षेत्र में बिल्कुल नये हैं। ब्रिटेन जैसे देश को 'सुपर सोनिक' विमान बनाने में लगभग 12 वर्ष लगे थे। हमें और अधिक धैर्य से काम लेकर स्थिति के प्रति अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

माननीय सदस्य श्री नाथ पाई का यह शंका करना उचित है कि जब तक भारत में विमान बनने लगेंगे तब तक अन्य देशों में और अधिक अच्छे किस्म के विमान बनने लगेंगे तथा भारत में बनाये जाने वाले विमान पुराने किस्म के पड़ जायेंगे। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस डर से विमानों का निर्माण ही न करें। हम भारत में जो 'मिग' 21 विमान बनायेंगे वह आधुनिकतम प्रकार का होगा और हमारी वायुसेना के लिए अत्यन्त उपयुक्त होगा। अतः माननीय सदस्य को इस बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या नये प्रकार के विमानों के पुर्जे भी मिल सकेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां। यदि इस प्रकार की व्यवस्था न हो तो नये किस्म के विमान मंगाना ही व्यर्थ हो जायेगा। मैं सभा की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमें न केवल पुर्जे ही मिलेंगे अपितु भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। यदि मिग विमानों से हमारा कार्य कम से कम दस वर्ष तक भी संतोष पूर्वक चलता रहा तो यह हमारे लिए पर्याप्त होगा।

अब मैं नौसेना के बारे में कुछ कहूंगा। 1962 में से ही मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि नौ सेना में काफी सुधार की आवश्यकता है किन्तु देश गत तीन वर्षों से जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उनको देखते हुए हमें स्थल सेना तथा वायु सेना की ओर ही अधिक ध्यान देना पड़ा। आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जब कि हम अपनी नौसेना के विकास की ओर अधिक समय तक अवहेलना नहीं कर सकते। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के

पास किसी देश की पनडुब्बी को गश्त लगाते हुए देखे जाने से कुछ नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः नौसैनिक विकास का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गया है। मैंने संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और रूस से, उन देशों के अपने दौरे में, नौ सेना के लिए जहाजों का संभरण करने के बारे में बातचीत की थी। कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना उचित है कि हमें नौसेना के विकास के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। किन्तु हमें कुछ वास्तविकताओं को दृष्टि में रख कर ही आगे बढ़ना होगा।

सरकार नौसैनिक विकास सम्बन्धी समस्याओं से पूर्णतः अवगत है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि नौसैनिक विकास के लिए 'फ्रिगेटों' के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। ब्रिटेन ने पनडुब्बियां बनाने में हमें तकनीकी सहायता देने का आश्वासन दिया है। अब इसके लिए धन की व्यवस्था करना शेष है। कम से कम यह बात निश्चित है कि भारतीय नौसैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ब्रिटेन हमें वर्ष में दो महीने के लिए अपनी पनडुब्बियां देने के लिए तैयार है।

श्री दांडेकर ने सेना की कुछ समस्याओं का उल्लेख किया है। हम इन समस्याओं के बारे में पूर्णरूप से अवगत हैं। पिछले दो वर्ष में हमने सेना के कर्मचारियों के कार्य के बारे में अध्ययन किया। भारतीय सशस्त्र सेना के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप लड़ने वाले तथा न लड़ने वाले ग्रुपों का अनुपात क्रमशः 75 और 22 है तथा पैदल सेवा में यह अनुपात क्रमशः 83 और 17 का है जबकि चीन में लड़ने और न लड़ने वाले ग्रुपों का अनुपात 86 और 14 का है। निस्संदेह यह अनुपात चीन की तुलना में कम है किन्तु हमें इसमें हिसाब लगाने के विभिन्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। हम वर्तमान परिस्थितियों से पूर्णतः अवगत हैं और हम सभी उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करेंगे।

माननीय सदस्यों ने सेना में की जाने वाली पदोन्नतियों की भी आलोचना की है। मैं समझता हूं कि उन्हें गलत सूचना दी गई है। जहां तक पदोन्नतियों का सम्बन्ध है, लेफ्टिनेन्ट कर्नल के स्तर तक पदोन्नतियां सामान्यतः वरिष्ठता के आधार पर ही की जाती हैं। उसके बाद उच्च पदों के लिए पदोन्नतियां चुनाव तथा वार्षिक गोपनीय (कॉन्फिडेंशल) रिपोर्टों के आधार पर की जाती हैं क्योंकि ये पद बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण समझे जाते हैं। चुनाव बोर्ड में बहुत उच्च अधिकारी होते हैं। अतः माननीय सदस्यों द्वारा पदोन्नतियों के बारे में शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक सैनिकों को प्रशिक्षण देने का सम्बन्ध है, नये सैनिकों को, विशेषतः जिन्हें आपात कालीन परिस्थितियों के फलस्वरूप भर्ती किया गया था, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने स्वयं उन्हें प्रशिक्षण देते हुए देखा है। हमारे जवानों तथा अधिकारियों में सराहनीय मनोबल है। वास्तव में वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे अपने अपमान का, जो उन्हें सहन करना पड़ा था, बदला ले सकें। माननीय सदस्य स्वयं स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने सेना में प्रयोग किये जाने वाली मोटरगाड़ियों के अनुपात के बारे में जानकारी मांगी है। अतः मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चीनी डिवीजन के पास 1209 मोटरगाड़ियां हैं जबकि हमारे पहाड़ी डिवीजन के पास 1362 गाड़ियां हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि सेना में प्रयोग होने वाली मोटर गाड़ियों को किस आधार पर उपयोग न करने लायक घोषित किया जाता है। इसके लिए हमने एक मापदंड निर्धारित किया है। यदि कोई गाड़ी 35,000 मील अथवा 7 वर्ष तक चल चुके तो उसे बेच दिया जाता है। जिन इलाकों

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

में हमें गाड़ियों को ले जाना पड़ता है वे दुर्गम और ऊबड़ खाबड़ होते हैं। बेकार गाड़ियों की देखभाल करने की तथा उनके लिए स्थान की समस्या भी हमारे सामने होती है। अतः उन्हें बेचना ही अधिक उपयोगी साबित होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : क्या यह बात दुर्गम क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों पर ही लागू होती है अथवा सबके लिए ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रायः सभी पर लागू होती है क्योंकि सभी गाड़ियों को आवश्यकता पड़ने पर दुर्गम स्थानों में चलाना पड़ता है। सेना द्वारा गाड़ी बेचे जाने पर वे असैनिक कार्यों के लिए प्रयोग में आती हैं।

जवानों की विधवाओं को पच्चीस रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि यह राशि काफी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहले की अपेक्षा यह राशि काफी है।

हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए उस क्षेत्र में अच्छी सड़कें होना आवश्यक है। पिछले दो वर्षों में सीमा सड़क विकास संगठन ने बहुत जोखिम उठाकर सराहनीय प्रगति की है। इस सम्बन्ध में कार्यक्रम अभी बहुत लम्बा है किन्तु जिस गति से हम कार्य कर रहे हैं उसके देखते हुए हम परिवहन तथा संचार के प्रश्न को शीघ्र ही संतोषजनक रूप से हल कर लेंगे।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री स० मो० बनर्जी तथा डा० मेलकोटे ने आयुध कारखानों में कर्मचारियों की छंटनी के बारे में प्रश्न उठाया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है कि आयुध कारखानों के कर्मचारियों ने गत दो वर्षों में बहुत सराहनीय कार्य किया है। हमने कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं। जिनको यथासमय कार्यरूप दिया जायेगा।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि मुझे एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है और मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि उसे निभाने का भरसक प्रयत्न करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आपकी अनुमति से आपका तथा सभा का ध्यान प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा 22 फरवरी को दिए गए उस भ्रामक वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ वे हैं जो 22 नवम्बर, 1962 से पहले निर्धारित थीं, अर्थात्, चीनी आक्रमण के बाद क्योंकि चीन ने 22 नवम्बर, 1962 से पहले आक्रमण किया था। माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि वास्तव में उनका तात्पर्य क्या था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 1947 तथा 1962 की सीमाओं में कोई अन्तर नहीं है। हमने किसी अन्तर को स्वीकार नहीं किया।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं समझता हूँ कि आपको मेरा नोट मिल गया होगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने आजाद हिन्द फौज में श्वेत, भूरे तथा काले लोगों का वर्गीकरण मांगा है। हमने इस अन्तर को स्वीकार नहीं किया है।

श्री नाथ पाई : यह अन्तर अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : 1963 या 1964 में उन लोगों को सहायता देने के लिए 30 लाख रुपये मंजूर किये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं कोई कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखूं ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 17 से 21 तथा 30, सभा की अनुमति से, वापिस लिए गये ।

The cut motions Nos. 17 to 21 and 30 were by leave, withdrawn.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं भी सभा की अनुमति से अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 6, सभा की अनुमति से, वापिस लिए गये ।

The cut motions Nos. 1 to 6 were by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following demands in respect of Ministry of Defence were put and accepted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
10	प्रतिरक्षा मंत्रालय	56,90,000
11	रक्षा सेवायें, सक्रिय-स्थल सेना	4,88,97,75,000
12	रक्षा सेवायें, सक्रिय नौसेना	20,92,30,000
13	रक्षा सेवायें, सक्रिय-वायुसेना	1,31,15,00,000
14	रक्षा सेवायें-निष्क्रिय	17,89,27,000
117	रक्षा सम्बन्धी पूंजीपरिव्यय	1,08,79,17,000

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 31 मार्च, 1965/10 चैत्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday March 31, 1965/Chaitra 10, 1887 (Saka).